पंचम माला, खंड 38, अंक 37 मंगलवार 16 अप्रैल, 1974/26 चैत्र, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXVIII No., 37 Tuesday, April 16, 1974/Chaitra 26 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र / Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. XXXVIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 37—मंगलवार, 16 अप्रैल, 1974/26 चैत्र, 1896 (शक)

No. 37—*Tuesday*, *April* 16, 1974/*Chaitra* 26, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
689.	सस्ती लागत पर विद्युत का उत्पादन	Genertaion of Power at Cheapest Cost	1–5
690.	बर्मा शेल और कालटेक्स द्वारा अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि करने की मांग	Demand for increase in price of Crude Oil by Burmah Shell and Caltex . .	5–7
692.	लखनऊ और दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त तेज गाड़ी चालू करने की योजना	Scheme to introduce Additional Fast Train between Lucknow and Delhi	7–8
693.	रेलवे वर्कशापों में वैगनों के उत्पादन में कमी	Reduction in Production of Wagons in Railway Workshops	
706.	वैगन की कीमतों संबंधी सूत्र (फार्मूला) के बारे में समझौता	Agreement in regard in Formula for Wagon Prices . .	10–13
694.	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में उत्पादित एक डीजल इंजन की लागत	Per Capita Diesel Engines Cost produced in DLW, Varanasi	13–15
695.	कोचीन तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों को एक दिन के वेतन की अदायगी न करना	Non-Payment of one Day's Pay to Employees of Cochin Refinery	15816
696.	गाड़ियों के विलंब से चलने के कारण अलवर और दिल्ली के बीच बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling between Alwar and Delhi due to late Running of Trains . .	16–18

अल्प सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
8	नेताजी के सम्बन्ध में बनाए गए वृत्त चित्र का विस्तार वाला भाग (लांगर वर्जन) दिखाए जाने के बारे में मंत्री द्वारा मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन को लिखे पत्र का पाठ	Text of the letter written by the Minister to Motion Pictures Associations for Showing longer version of Documentary Film on Netaji	18–21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—14 L. S. S./74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
691.	कृषि, औद्योगिक तथा घरेलू कार्यों के लिए बिजली की खपत	Consumption of Power for Agricultural, Industrial and Domestic Purposes . . .	22
697.	अहमदपुर कटवा नेरो गज लाइन चलाने वाली मार्टिन बर्न की की एक कम्पनी मकलियोड म सरकार के शयर	Government's Share in Mcleod— A concern of Martin Buru Running Ahmadpur Katwa Narrow Gauge Line . .	23
698.	पांचवी योजना में मध्य प्रदेश के लिए मध्यम सिंचाई योजनाएं	Medium Irrigation Schemes for M. P. in Fifth Plan. .	23
699.	धुवरन बिजलीघर को तेल को सप्लाई में कटौती	Cut in Oil Supply to Dhuwaran Power House . . .	23-24
700.	आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी की पन बिजली क्षमता	Hydro Power Potential of Brahmputra River in Assam .	24
701.	जल संसाधनों का अनुमान लगाया जाना	Assessment of Water Resources	24
702.	उडीसा को धनेई सिंचाई परियोजना को स्वीकृति	Clearance of Dhanei Irrigation Project in Orissa . .	25
703.	उड़ीसा के पिछड़ क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बिछाने का लक्ष्य	Target for New Railway Lines in Backward Areas of Orissa	25
704.	टाटा बन्धुओं द्वारा ट्राम्बे तापीय बिजली घर में अतिरिक्त जनरेटिंग सेट लगाया जाना	Setting up of Additional Generating set at Trombay Thermal Station by Tatas . .	25-26
705.	उड़ीसा उच्च न्यायालय मे दायर अपीलें और मुकदमें	Number of Appeals and Cases filed in High Court of Orissa	26
707.	रेलों में विद्युतीकरण धीरे धीरे करने के बारे म सरकार का निर्णय	Government Decision to Go Slow in Electrification of Railways	26
708.	कास्टिक सोडा उद्योग पर ऊर्जा संकट का प्रभाव	Impact of Energy Crisis on Caustic Soda Industry .	25-27
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
6784.	चम्बल जल विद्युत योजना द्वारा मध्य प्रदश में भमि की सिंचाई	Irrigation of Land in Madhya Pradesh by Chambal Hydro Electric Scheme . . .	27
6785.	मध्य प्रदश में कृषि भूमि को बेकार होन से बचाना	Saving of Agricultural Land from Wastage in M.P. .	27-28

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6786.	बस्तर क्षेत्र में मोमबत्ती बनाने के लिए मोम की कमी	Shortage of Wax for Manufacturing Candles in Baster Region . . .	28
6787.	मूल्यों के अनुमोदन के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र	Applications Pending Approval for Prices . . .	28
6788.	कुछ औषधियों के लागत-मूल्य अध्ययन संबंधी औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन	Report of Bureau of Industrial Cost and Prices on cost price study of certain Drugs . . .	29
6789.	बेकार पड़े रेल इंजन	Idle Locomotives	29
6790.	पांचवी योजना में बिजली उत्पादन के लिए नियत लक्ष्य	Target fixed for Power Generation in Fifth Plan . . .	29–30
6791.	मध्य प्रदेश में गाड़ियों का नियमित समय पर चलना	Running of Trains in Madhya Pradesh According to Time Schedule	30
6792	मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ क्षेत्र में रेलवे लाइन	Railway Lines in Chhattisgarh Region of Madhya Pradesh . .	30
6793.	वर्ष 1973–74 के दौरान मध्य प्रदश में ग्रामीण विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Madhya Pradesh during 1973-74	31
6794.	मध्य प्रदेश सरकार को खाद्यान्नों की सप्लाई न करना	Non Supply of Foodgrains to Government of Madhya Pradesh	31
6795.	वर्ष 1974–75 में केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा योजनाओं की क्रियान्विति	Execution of Schemes by REC in Kerala in 1974-75 . .	31–32
6796.	वर्ष 1973–74 में बिना टिकट यात्रा करने वाल यात्रियों स वसूल की गई राशि	Amount recovered from Ticketless Travellers during 1973-74	32–33
6797.	दिल्ली में डीजल की चोर बाजारी	Black Marketing of Diesel in Delhi	33
6798.	रामश्वरम द्वीप में पुन: रेल–लाईन बिछाना	Relaying of Railway Lines in Rameshwaram Island .	34
6799.	जनवरी, 1974 में छात्रों द्वारा मुरादाबाद रेल स्टेशन पर हमला	Attack on Moradabad Railway Station by Students in January, 1974	34
6800.	उत्तर रेलवे के रेल कर्मचारीयों के विरुद्ध विभागीय जांच	Departmental Enquiries Against Railway Employees of Northern Railway . . .	34
6801.	वर्ष 1974–75 के दौरान तमिल नाडु में बनाए जाने वाले प्रस्तावित नए उपरिपुल	New over Bridges proposed to be constructed in Tamil Nadu during 1974-75 . . .	35

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6802.	दक्षिण मध्य रेलवे में नेल्लोर पर रेल की पटरियों की फिश प्लेटें, बोल्ट तथा बियरिंग का निकाला जाना	Fish Plates, Bolts and Bearing of Railway Track removed at Nellore on S.C. Railway	35
6803.	ठेकेदारों द्वारा विभिन्न रेलवे में किये गये कार्यों के लिए धनराशि की अदायगी	Payments to Contractors for Works Carried out by them	35-36
6804.	नागपुर क्षेत्र में संतरों की ढुलाई के लिए वेगनों की कमी	Shortage of Wagons in Nagpur Region for Orange haulage	36
6805.	दिल्ली कैंट-नांगल राय रलव फाटक पर रेलवे तथा सार्वजनिक जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया जाना	Encroachment upon Railway and Public Lands at Delhi Cantt. Nangal Raya Railway Crossing	36
6806.	बम्बई वी० टी० तथा मनमाड के बीच तेज चलने वाली गाडी की मांग	Demand for a Fast Train between Bombay V.T. and Manmad	37
6807.	मध्य प्रदेश में और अधिक संयंत्रो की स्थापना	Setting up of More Power Plants in M.P. . . .	37
6808.	देश में कोयले की वैगनों का रोका जाना	Holding up of Coal Wagons in the Country . . .	37-38
6809.	चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों द्वारा सरकारी मशीनरी का उपयोग	Use of Government Machinery by the Prime Minister, Chief Ministers and other Ministers during Election Campaign .	38
6810.	भारतीय तेल निगम में पूर्वी क्षेत्र के कर्मचारी	Employees of Eastern Region in IOC	38-39
6811.	ऊर्जा संकट से रेलवे को लाभ	Beneficial Impact of Energy Crisis in case of Railways	39
6812.	कोचीन क्षेत्र में विभिन्न टर्मिनल सेवाओं को सुव्यवस्थित किये जाने के बारे में कार्य अध्ययन दल	Work Study Trains on Rationalising various Terminal Services in Cochin Area .	39
6813.	बड़े व्यापार गृहों के नियंत्रण के अन्तर्गत कंपनियों की वर्ष 1971-72 तथा 1973-74 के दौरान कुल परिसंपत्ति, कुल बिक्री तथा लाभ	Total Assets, Turn over and Profits of Companies under the Control of Larger Houses during 1971-72 and 1973-74	40

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6814.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अशोधित तेल के अधिक मूल्य की मांग	Demand for Higher Price of Crude by O & N G C. .	40
6815.	आठसराय (उत्तर प्रदेश) के सहायक स्टेशन मास्टर पर हमला	Attack on Assistant Station Master of Athsarai (U. P.) .	41
6816.	पहली सितम्बर, 1973 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत लाई गई कम्पनियां	Companies covered under the Companies Act, 1956 as on the 1st September, 1973 . .	41
6817.	पोलिस्टर रेशे का उत्पादन करने वाली फर्में	Polyster Fibre Producing Firms .	42–43
6818.	विकास परिषद (भेषज) का गठन	Composition of Development Council (Drugs) . . .	43
6819.	"इंडियन फार्मास्युटिकल इण्डस्ट्री, 1973" नामक पुस्तिका का विमोचन	Release of a Booklet Indian Pharmaceutical Industry, 1973	44
6820.	मंदिरों में हरिजनों को पुजारी के रूप में नियुक्ति	Appointment of Harijans as Priests in Temples . .	44
6822.	रलवेज में नैमित्तिक श्रमिकों की मंजूरी	Wages of Casual Labour in Railways	44–45
6823.	राजस्थान में पचपडरा, डीडवाना और साम्भर नमक उत्पादन क्षेत्रों को 'सी' और 'ई' श्रेणी के माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of 'C' and 'E' Class Railway Wagons to Pachpadra, Didwana and Sambhar Salt Source in Rajasthan . .	45
6825.	भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधायें	Facilities afforded to Directors and Senior Officers of FCI	45
6826.	शिक्षित बेरोजगारों और सहकारी समितियों को दिये गये बुक स्टालों के ठेके	Contacts for Book Stallsgiven to Educated Unemployed and Co-operative Societies . .	46
6827.	बम्बई हाई में पाये गये तेल की मात्रा और उस पर किया गया व्यय	Quantity of Oil found in Bombay High and Expenditure incurred thereon . . .	46
6828.	प्रारंभिक उद्योगों को रियायती दरों पर तेल की सप्लाई	Supply of Oil to Primary industries at concessional rates	46
6829.	वर्ष 1973–74 के दौरान तीसरी श्रेणी के रेलवे टिकटों की बिक्री से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि	Increase in Revenue Receipts for sale of Third Class Railway Tickets during 1973-74 .	47

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6830.	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त सहायक अधिकारियों को स्थायी करना	Confirmation of Assistant Officers recruited through UPSC .	47
6831.	कलकत्ता में पटसन उद्योग में हड़ताल से वैगनों के आवागमन पर प्रभाव	Wagon movement affected by Jute Strike in Calcutta .	47–48
6832.	पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों में निर्माणाधीन रेलवे लाइनें	Railway Lines under Construction in West Bengal during last three years	48
6833.	पश्चिम बंगाल में नई रेलवे लाइनों के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट	Techno-Economic Surveys for Railway Lines in West Bengal	48–49
6834.	राज्यों की राजधानियों को रेलवे लाइनों से जोड़ने का निर्णय	Decision to connect Capitals of States with Railways	49–50
6835.	क्विलोन में छात्रों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां	Difficulties experienced by Students at Quilon .	50
6836.	अलवर और गुड़गांव स्टेशन के बीच चार औरतों के साथ चलती गाडी में बलात्कार	Criminal asault on four women in the Train running between Alwar and Gurgaon . .	50
6837.	कुर्माडांगा हाल्ट को स्टेशन में बदलना	Conversion of Kurmadanga Halt into a full station .	51
6838.	रेल सेवा आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का चयन	Selection of Scheduled Castes/Scheduled Tribes Candidates by Railway Service Commissions for different Classes .	51
6839.	झांसी स्टेशन पर विभिन्न विभागों के रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway Employees of different Departments at Jhansi Station	51–52
6840.	इंटेग्रेल कोच फैक्ट्री, मद्रास द्वारा फिलीपाइन्स नेशनल रेलवे को रेल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Rail Coaches to Phillippines National Railways by ICF Madras . . .	52
6841.	कोयले से तेल निकालने संबंधी परियोजना	Project for extraction of oil from Coal	52–53
6842.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और ईराक के एन० ओ० सी० के बीच करार	Agreement between O. & N. G. C. and NOC of Iraq . .	53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6843.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा उड़ीसा में बड़ो सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना .	Clearance of Major Irrigation Projects in Orissa from CW-PC	54–55
6844.	उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से अनिर्णित पड़ मामले . . .	Cases pending in High Courts for more than Five Years .	55–56
6845.	उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों का लक्ष्य	Target of New Railway Lines in Fourth Five Year Plan for Orissa	56
6846.	चौथी योजना में सिंचाई परियोजनाओं का लक्ष्य	Target of Irrigation Projects in Fourth Plan . . .	57
6847.	कम संख्या में वैगनों के उपलब्ध होने के कारण सौराष्ट्र में लवण पटलों में बड़ी मात्रा में लवण जमा हो जाना	Huge Accumulation at Salt Pans in Saurashtra due to Poor availability of Wagons .	57
6848.	गुजरात में सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना	Clearance of irrigation Schemes in Gujarat	58
6849.	निर्माण लेखा कार्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली (उत्तर रेलवे) में ठेकेदारों के बिलों से संबंधित कार्य कर रहे कर्मचारियों का स्थानांतरण	Transfer of Staff dealing with contractor's Bill in Construction Accounts Office Kashmero Gate, Delhi (Nothern-Railway)	58–59
6851.	उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के दिल्ली क्षेत्र के सब हैड़ो को पुनरीक्षित वेतनमानों के कारण पूर्ण अदायगी	Final Payment to Sub-heads of Northern Railway Accounts Department for Delhi Area due to Revised Pay-Scales .	59
6852.	तेल के संबंध में नई नीति बनाना	Formulation of a New Policy on Oil	59–60
6853.	अपमिश्रण रोकने के लिए पेट्रोल पम्पों पर इश्तहार लगाया जाना	Display of Posters at Petrol Pumps to Check Adulteration	60
6854.	उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाना	Setting up of New Lines in Uttar Pradesh	60–61
6856.	चौथी योजना में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	Electrification of Harijan Bastis in Fourth Plan . .	61–62
6857.	छः वर्ष पुराने रिफ्रशमेंट कन्ट्रेक्टरों तथा चाय के स्टाल वालों को बदलने की योजना का स्थगित किया जाना	Postponement of Scheme to Change Refreshment Contractors and Tea Stall Owners Functioning for the Last six years	62

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6858.	आगामी गर्मी के मौसम में और अधिक रेल गाड़ियां चलाना	Introduction of Trains during the ensuring Summer Season	63
6859.	भारतीय रेलवे में नई किस्म का दूसरा दर्जा	New Variety of Second Class on Indian Railways . .	63–64
6860.	दिल्ली तथा बम्बई के बीच मुख्य ब्राड गज लाइन को दोहरी लाइन बनाना	Doubling of Main Broad Gauge Line between Delhi and Bombay	64
6861.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयल से तेल निकालना	Producing Oil from Coal by Engineers India Limited .	64–65
6862.	मेयार रेलवे स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर उपरि पुल का निर्माण	Construction of Overbridge Maihar Railway Station (Madhya Pradesh) . .	65
6863.	विदेशी फर्मों को एकाधिकार तथा निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के बार में जांच संबंधी प्रतिवेदन	Reports of Investigation into the Monopoly and Restrictive Trade Practices of Foreign Firms	65–66
6864.	सियादह डायमंड हार्बर लक्मीकांतपुर लाइन (सियालदेह डिवीजन) पर समाज विरोधी तत्व	Anti-Social Elements on Sealdah Diamond Harbour-Lakshmikantapur Line (Sealdah Division)	67
6865.	राज्यों के समक्ष बिजली सप्लाई की कमी की स्थिति	Shortage of Power Supply faced by States	67–68
6866.	आल इंडिया अलेम्बिक एम्पलाइज फेडरेशन से ज्ञापन	Memorandum from All India Alembic Employees Federation	68–69
6867.	आल इंडिया स्विचमन एंड लीवरमैन एसोसिएशन, धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) का बीमारी के आधार पर बड़ी संख्या में छुट्टी लेने का आन्दोलन	Mass Sick Report Movement by All India Switchmen and Leverman Association, Dhanbad Division (Eastern Railway)	69–70
6868.	भारतीय रेलवे में हाई स्कूल/मिडिल स्कूल/प्राइमरी स्कूल और आस्टेरिटी टाइप प्राइमरी स्कूल	High Schools/Middle Schools/Primary Schools and Austerity Type Primary Schools on Indian Railways . . .	70
6869.	मोतिहारी स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर अंडरग्राऊंड पूल के बारे में दिया गया आश्वासन	Assurance given on underground bridge/over bridge at Motihari Station (N. E. Railway)	71
6870.	बिजली का उत्पादन बराबर करने तथा बिजली शुल्क की दर समान करन की योजना	Scheme for even Power Production and Uniform rates of electricity Charges . .	71

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6871.	विभिन्न राज्यों को पेट्रोल और मिट्टी के तेल को सप्लाई	Petrol and Kerosene Oil supplied to various states . . .	71–72
6872.	गत तीन वर्षों के दौरान बंगाल को सिंचाई के लिये सहायता	Assistance to Bengal for Irrigation during last three Years	72
6873.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास बेमार पड़े हुये जनित्र एकक	Generating units lying idle in U. P. with State Electricity Board	72
6874.	विद्युत के प्रजनन और वितरण को केन्द्रीय नियंत्रण में लिया जाना	Taking up of Generation and distribution of Power under Central control . . .	72–73
6875.	हरदुआगंज तापीय बिजली घर को क्षति	Damage to Harduarganj Thermal Power Station . .	73
6876.	औषध उद्योग में उत्पादन पर आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया के सुझाव	Suggestion of OPPI on production of Drug Industry . .	73–74
6877.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स के गोदाम से इस्पात के पाईप की चोरी के मामले की जांच	Inquiry into theft of Steel Pipes from Hindustan Organic Chemicals godown . .	74
6878.	भारतीय तेल निगम द्वारा विद्युत प्रजनन के लिये नई किस्म के ईंधन तेल की सप्लाई	Supply of new Furnace Oil by Indian Oil Corporation for Power Generation . .	74–75
6879.	मार्च, 1974 में बिहार में उपद्रवों के कारण गाड़ियां बन्द किया जाना	Cancellation of trains due to disturbances in Bihar in March, 1974 . . .	75
6880.	एकाधिकार और निर्बंधात्मक व्यापार, प्रक्रिया आयोग द्वारा "हिन्दुस्तान टाइम्स" और "टाइम्ज आफ इंडिया" को जारी किये गय नोटिस	Notices issued to the Hindustan Times and Times of India by Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission	75–77
6881.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रूमानिया से तेल की खुदाई करने वाले रिगों को खरीदना	Purchasing of drilling rigs by O & N G C from Rumania	77
6882.	रेलवे जोनों का गठन और रेलवे सेवा आयोगों के मुख्यालय	Constitution of Railway Zones and Headquarters of Railway Service Commission . .	77–78
6883.	प्रभागीय क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता समितियों में छात्रों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व	Representation to students and teachers in Divisional, Zonal and National Railway Users' Committees	79

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6884.	कांगड़ा घाटी रेलवे के लिये ज्वाली और गुलेर स्टेशनों के बीच वैकल्पिक मार्ग	Alternate Alignment for Kangra Valley Railway between Jwali and Guler Stations .	79
6885.	पांचवीं योजना में जम्मू काश्मीर, पंजाब और हरियाणा के लिये विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति	Sanction of Hydel and Power Projects for Punjab and Haryana in Fifth Plan . .	79
6886.	बिहार में मार्च, 1974 के दौरान हुए दंगों के परिणाम स्वरूप रेलवे को हुई क्षति	Loss suffered by Railways during disturbances in Bihar in March, 1974 . . .	79–80
6887.	बिहार में राजगीर स्थान पर 6 मार्च, 1974 को हुई रेल दुर्घटना	Railway accident at Rajgir in Bihar on 6th March, 1974 .	80
6888.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कार के रखने के लिये एक रुपये का शुल्क लिया जाना	Charging of Re. 1 for Car Parking at New Delhi Station . .	80
6889.	जनवरी, 1974 में वैस्टर्न कोसी नहर के उद्घाटन पर हुआ खर्च	Expenditure incurred on the inauguration of Western Kosi Canal in January, 1974	81
6890.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 और 31 के कटाव का खतरा	Erosion threat to National Highway Nos. 21 and 31 .	81
6891.	बिहार में विद्युत जनित्र संयंत्रों का स्थापित किया जाना	Setting up of a Power Generating Plant in Bihar . . .	81–82
6892.	भारत में तेल की खोज के लि सोवियत संघ के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना	Inviting Soviet Experts for Oil Exploration in India . .	82–83
6893.	1976–77 में होने वाले निर्वाचनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण की शर्तें	Conditions for the Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in General Elections of 1976-1977	83
6894.	कुकिंग गैस के सिलेंडरों की कमी	Shortage of Cylinders for Cooking Gas	83–84
6895.	रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन का प्रस्ताव	Proposal to reorganise Railway Protection Force . . .	84
6896.	1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान रेल वैगनों तथा यात्री डिब्बें (कोचों) का निर्माण	Railway Wagons and Coaches produced during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 . .	84
6897.	डिजलीकरण के संबंध में खान मंत्रालय का प्रस्ताव	Proposal from Ministry of Mines on Dieselisation . . .	84

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6898.	कार्यरत डीजल इंजन और उनका उत्पादन	Diesel Engines at Work and their Production	85
6899.	गत तीन महीनों में सियालदह डिवीजन में रेल गाडी सेवाओं का अस्त-व्यस्त होना	Disruption of Train Services in Sealdah Division during the last three Months	85–86
6900.	सियालदह स्टेशन पर उपद्रवों के कारण गाड़ियों को बंद करना	Cancellation of Trains due to disturbances at Sealdah Station	86
6901.	गत 6 महीनों में पूर्वोत्तर रेलवे में दुर्घटनाएं	Accidents on North Eastern Railway during the last 6 months	86–87
6902.	आन्ध्र प्रदेश में पीथापुरम से राजामुंद्री मुख्य लाइन को काकीनाडा होकर ले जाया जाना	Diversion of main line from Pithapuram to Rajahmundry *via* Kakinada in Andhra Pradesh	87
6903.	आन्ध्र प्रदेश में रेलवे द्वारा माने गये पिछड़े क्षेत्रों के नाम	Names of Areas in Andhra Pradesh considered backward by Railways	87
6904.	दक्षिण मध्य रेलवे में बिना चौकीदार के रेलवे फाटक	Unmanned Railway crossings in South Central Railway	87–88
6905.	गाजियाबाद स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर कार्य करने वाले भारवाहक कुलियों के वेतन वृद्धि का बकाया	Increment arrears to luggage porters working at Ghaziabad Station (Northern Railway)	88
6906.	बारामुरा में तेल की खुदाई बंद करना	Suspension of Drilling for Oil at Baramura	88
6907.	राज्यों में वर्ष 1973–74 में विद्युत का उत्पादन और उसकी खपत	Generation of Power and Consumption in States during 1973-74	89
6908.	तेल की खुदाई संबंधी 'रिगस' की खरीद के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों का अमरीका का दौरा	Visit of officials of O & N G C to USA to purchase Oil Drilling Rigs	89
6909.	रेलवे में भर्ती के लिये क्षेत्रीय आयोग	Zonal Commission of recruitment to Railways	90
6910.	मध्य प्रदेश में सिंगरौली स्थान पर एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करना	Setting up of a fertilizer plant at Singrauli in Madhya Pradesh	90
6911.	मध्य प्रदेश के खनन उद्योगों के सन्मुख वैगनों की कमी का संकट	Mining Industry in Madhya Pradesh facing Wagon shortage	90
6912.	संभल मुरादाबाद सडक पर उपरि पुल बनाने का प्रस्ताव	Proposal to construct over bridge over Sambhal Moradabad Road	91

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6913.	मुरादाबाद में इंडियन आयल की निर्माणाधीन टंकी का टूट जाना	Breaking of Indian Oil Tank at Moradabad while under construction	91
6914.	नैफ्था के मूल्य में वृद्धि होने के कारण कलकत्ता में पेट्रो-रसायन एककों को हो रही कठिनाइयां	Difficulties faced by Petro Chemical Units in Calcutta due to increase in Price of Naphtha	91–92
6915.	राजस्थान में राक-फास्फेट पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन	Report submitted by FCI to set up a Rock Phosphate based Fertiliser factory in Rajasthan	92
6916.	प्रत्येक उच्च न्यायालय में प्रशासकीय बेंच की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal for establishment of Administrative Bench in each High Court . . .	92
6917.	चौथी योजना के दौरान केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Kerala in Fourth Plan . . .	92–93
6918.	गत दो वर्षों में केरल की सिंचाई और विद्युत परियोजनायें	Irrigation and Power Schemes for Kerala during Last Two Years.	93
6919.	पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल म ग्रामीण विद्युतीकरण के लिय स्वीकृत राशि	Amount sanctioned for rural Electrification in Kerala during last three years . .	93–94
6920.	केरल में पुलों एवं उपरि पुलों का निर्माण	Construction of Bridges and Over Bridges in Kerala .	94
6921.	केरल में काल्लदा सिंचाई परियोजना से भूमि की सिंचाई	Irrigation of land from Kallada Irrigation Project in Kerala	94–95
6922.	तेल के बदले में सीमेंट का निर्यात	Export of Cement in Exchange of Oil	95
6923.	लोको रनिंग कर्मचारियों के लिये दस घंटे तक काम के संबंध में कुरेशी समिति के प्रतिवेदन का पूरा किया जाना	Completion of Qureshi Committee Report for Ten hour work for Loco Running Staff	95–96
6924.	इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास में श्रेणी एक, दो तीन तथा चार के पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	SC/ST Holding Class I, II, III and IV Post in ICF, Madras	96
6925.	आंध्र प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण का निर्धारित लक्ष्य	Target for Construction of New Railway lines in Fourth Five Year Plan in Andhra Pradesh	97
6926.	आंध्र प्रदेश में ग्रामीन विद्युतीकरण के चौथी योजना के लक्ष्य	Target of Rural Electrification in Andhra Pradesh for Fourth Plan	97

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6927.	आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनों का लक्ष्य	Target for New Railway Lines in Backward Areas on Andhra Pradesh	97
6928.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा निर्मित 'रिगों' से शिवसागर में तेल के लिए खुदाई	Drilling of Oil at Sibsagar with Rigs Manufactured by HEC	98
6929.	तेल का उत्पादन करने वाले देशों मे तेल परिशोधक कारखानों में इक्विटी अंश खरीदने के भारत के प्रयास	India seeking Equity participation in Refineries in Oi Producing countries . .	98
6930.	बंगलो-चपड़ासो के पद पर लगे प्रतिबंध में ढील	Ban relaxed on Post of Bungalow Peon	98–99
6931.	मध्यस्थता के पंचाट (मियाभाई और अन्य न्यायाधिकरण) को स्वीकृति	Upholding of Award of Arbitration (Miaboy and other Tribunals)	99
6932.	अहमदाबाद से कोचीन तक सीधी रेलगाड़ी चलाने की मांग	Demand for direct train from Ahmedabad to Cochin .	99
6933.	अल्यूमिनियम उद्योग के लिये स्नेहक तेलों की कमी	Shortage of Lubricating Oils for Aluminium Industry . .	100
6934.	रेलवे गार्ड आन्दोलन के दौरान ब्रेक वैन के गार्डों के बिना चलने वाली गाडियों की दुर्घटनाएं	Accidents to trains running without Guards of brake-van during the Railway Guards Agitation . . .	100
6935.	कश्मीर घाटी की बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Kashmir Valley	100–101
6936.	नानपाडा—गुरुपुर 'नैरो गेज लाइन'	Naupada-Gurupur Narrow Gauge Line	101
6937.	पांचवी योजना में बडो सिंचाई परियोजनाओं के लिये धनराशि का नियतन	Allocation of Money for Major Irrigation Projects in Fifth Plan	101
6938.	वर्ष 1974 से 1976 तक अतिरिक्त बिजली पैदा करने का लक्ष्य	Target for additional Production of Power during 1974 to 1976	101–102
6939.	सरकारी क्षेत्र के एककों में बिजली की कमी	Power shortage in Public Sector Units	102
6940.	हरियाणा में कटवाल में पेट्रोलियम का पता लगाना	Discovery of Petroleum at Katwal in Haryana . . .	102–103
6941.	मेसर्स सैण्डोज द्वारा ब्राइनरडाइन का निर्माण	Manufacture of Brinerdine by M/s Sandoz	103
6942.	त्रिपुरा के बारामुरा में तेल की खोज	Oil exploration at Baramula in Tripura	103–104

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6943.	बिहार में उपद्रवों के कारण रेल गाड़ियों के रद्द किये जाने का आसाम राज्य पर प्रभाव	Effect of cancellation of trains due to disturbances in Bihar, on Assam	104
6944.	4 जनवरी, 1974 को सासनी स्टेशन पर मालगाडी से चोरी	Pilferage from Goods Train at Sasni Station on the 4th January, 1974 . . .	104
6945.	वर्ष 1973-74 में विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त न करने वाले राज्य	States which have not achieved target of Electrification in 1973-74	104-105
6946.	औषध फर्मों को "की इण्डस्ट्री श्रेणी" के अंतर्गत लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Pharmaceutical Firms Under Key Industry' Category . .	105-106
6947.	कोयले की कमी के कारण गाडियों के रद्द होने से रेलवे की हुई हानि . . .	Loss suffered by Railway due to cancellation of trains due to coal shortage . . .	106
6948.	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नई लाइनों के लिये किया गया अनुरोध	Request of Andhra Pradesh Government for new lines .	106-107
6949.	आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल की खोज	Oil exploration in Krishna Godawari Basin of Andhra Pradesh	107
6950.	हैदराबाद हावडा एक्सप्रेस गाडी की गति बढाना	Speeding up of Hyderabad Howrah Express train . .	108
6951	सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) के बडानगर में सिगनल तथा दूर संचार विभाग संबंधी इन्स्टालेशन	Installation pertaining to Signal and Telecommunication Department on Baranagar in Sealdah Division (Eastern Railway)	108
6952.	सियालदेह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में एब्सोल्यूट परिमिसिव ब्लाक-सिस्टम के लागू करने संबंधी लागत	Cost involved in installation of Absolute permissive Block System in Sealdah Division (Eastern Railway) . .	109
6953.	फिल्मी गीतों के रिकार्डों को बजाने संबंधी रेल मंत्रालय के निदेश	Railway Ministry Introducing Cinema song recording .	109
6954.	धनबाद स्टेशन पर बसों के ठहरने का शुल्क वसूल न करने के कारण	Reasons for not Realising Parking charges from Buses at Dhanbad Station . . .	110
6955.	आसनसोल और हावडा स्टेशनों का विकास	Development of Asansol and Howrah Stations . . .	110
6956.	आसनसोल में शायिकाओं (बर्थ) के आरक्षण का प्रबंध	Arrangement for Reservation of Berths at Asansol . .	110
6957.	सफाई व्यवस्था में सुधार करने संबंधी मांग	Demand for Improvement in the Sanitation Arrangements	110-111

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6958.	भारतीय रेलों के रोड साइड स्टेशन के कैरज एंड वैगन मेकेनिकल विभाग के अंतर्गत स्वच्छता विंग को समाप्त करना	Abolition of Sanitation Wing of Road side station carriage and Wagon Mechanical Department of Indian Railways	111
6959.	अहमदाबाद से मारवाडा जंक्शन तक गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव	Proposal to run Trains from Ahmedabad to Marwar Junction	111
6960.	सराय रोहिला स्टेशन पर टेलीफोन की स्थापना	Installation of Telephone at Sarai Rohilla Station . .	111–112
6961.	गत 6 महीनों के अंदर कोयले की कमी के कारण राजस्थान में रद्द की गयी गाडियां	Trains Cancelled in Rajasthan due to Coal Shortage during the last six Months . . .	112
6962.	मेसर्ज कृषि विकास केन्द्र रिवाडी को उर्वरकों का व्यापार करने संबंधी अनुमति	Dealership in Fertiliser Granted to M/s Krishi Vikas Kendra, Rewari	112
6963.	शेयरों के आवेदन कर्ताओं को मांगी गई राशि अथवा ब्याज देने में विफलता पर जुर्माना	Penalty for Failure to pay Call Money or Interest to the Applicants for Shares . .	112
6964.	पांचवी योजना के दौरान संश्लिष्ट धागे का उत्पादन	Production of Synthetic Fibre in Fifth Plan	113
6965.	उर्वरक बचाव योजना	Fertiliser Saving Plan . .	113–114
6966.	पेट्रो-उद्योग समूहों को तेल शोधन शालाओं के समीप स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Petrol Complexes close to Oil Refineries	114–115
6967.	खाली माल डिब्बों के लाने ले जाने से रेलों द्वारा उठाई गई हानि	Loss sustained by Railway by running Empty Wagons .	115
6968.	राम नगर से काठ गोदाम तक नई रेलवे लाइन	New Railway Line from Ramnagar to Kothagudem . .	115

अविलंबनिय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— / Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली के सहायक स्टेशन निदशक द्वारा आत्म हत्या किये जाने का समाचार— / Reported Suicide by an Assistant Station Director of the Television Centre, Delhi—

श्री इन्द्रजीत गुप्त :	Shri Indrajit Gupta .	116–117
श्री आई० के० गुजराल :	Shri I. K. Gujral	136–117 व 119–120

विशेषाधिकार प्रश्न— / Question of Privilege—

मंत्री महोदय द्वारा कथित गुमराह करनेवाली जानकारी देना / Alleged Misleading Information given by the Minister . . . 120

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	121
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत किये गये	Reports and Minutes—presented	121–122
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee —	
एक सौ इक्कीसवा प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Hundred and Twenty First Report—Presented . .	122
कानपुर के एक अस्पताल में नकली ग्लूकोस इंजैक्शनों के कारण अनेक रोगियों की मृत्यु के बारे म वक्तव्य—	Statement Re : Death of Several Patients in Kanpur Hospital due to Spurious Glucose Injections—	
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh. .	122–123
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under Rule 377—	
वियतनाम में अमरीकी सेवाओं के बारे बारे में प्रधान मंत्री के विचारों के बारें में समाचार	New item about Prime Minister's view on US Troops in Vietnam	124
रेल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित रेल हड़ताल के बारे में	Re. proposed strike by Railwaymen	12?–126
अनुदानों की मांगें, 1974–1975—	Demands for Grants, 1974-75—	
इस्पात और खान मंत्रालय—	Ministry of Steel and Mines—	
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	127–128
श्री प्रबोध चन्द्र	Shri Prabodh Chandra .	128
श्री सी० टी० दंडपाणि	Shri C. T. Dhandapani .	128–130
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta . .	130–131
डा० महीपतराय मेहता	Dr. Mahipatray Mehta .	131–132
श्री नरसिंह नारायण पाण्डे	Shri 'Narsingh Narain Pandey	132
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate .	132–13–
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansada .	133–136
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao .	136–137
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan .	137–138
श्री सी० डी० गौतम	Shr C. D. Gautam . .	138–139
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	139–140
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	140
श्री सुखदेव प्रसाद	Shri Sukhdev Prasad .	141
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi .	141–142
श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav . .	142
श्री एस० एल० पेजे	Shri S. L. Peje . .	142
श्री गेंदा सिंह	Shri Genda Singh . .	143
श्री केशव देव मालवीय	Shri K. D. Malaviya .	143–146

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 16 अप्रैल, 1974/26 चैत्र, 1896 (शक)
Tuesday, April 16, 1974/Chaitra 26, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Generation of power at cheapest cost

\+

***689. Shri Jagannathrao Joshi:**

Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the steps being taken to generate power at the cheapest possible cost in the country; and

(b) when the power generating projects under construction at present are likely to be completed?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Steps to generate power at the cheapest possible cost in the country comprise the following :—

(i) Accelerated development of hydro potential which is generally the cheaper source of power.

(ii) Establishment of large thermal power stations at suitable locations in and near the coal bearing areas so as to avail of economies of scale and minimise transport costs.

(iii) Integrated operation of the power systems on a regional/national basis to secure optimum and most economic utilisation of the available generating capacity.

(iv) Adopting the largest permissible sizes of generating units consistent with availability of the necessary manufacturing facilities operating know how within the country and the capability of the system to asborb such large size sets.

(v) Improved operation and maintenance by trained personnel so as to minimise costly forced and maintenance outages.

(vi) Research and Development work to bring down the costs of plant and equipment and their operation.

Efforts are being made and will continue during the Fifth and the subsequent plans to implement the above measures progressively.

(b) The likely programme of completion of the various projects under construction is given in the annexure.

ANNEXURE

Power generating projects which are under construction and their likely date of commissioning

(Figures in million KW)

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1978–79	Total
A—Hydro						
(i) Spillover & continuing	0·8	1·38	1·36	0·5	1·0	5·04
(ii) New	..	..	..	..	0·01	0·01
Sub Total (A)	0·8	1.38	1.36	0.5	1.01	5.05
B—Thermal						
(i) Spillover & continuing	1.54	1.12	1.46	0·55	0.12	4.79
(ii) New	..	0.06	0.57	0.54	0.20	1.37
Sub Total (B)	1.54	1.18	2.03	1.09	0.32	6.16
C—Nuclear						
(i) Spillover & continuing	..	0.2	0.2	..	0.02	0.60
(ii) New	..	..	..	..	..	..
Sub Total (C)	..	0.2	0.2	..	0.2	0.60
Grand Total	2.34	2.76	3.59	1.59	1.53	11.81

Shri Jagannathrao Joshi: Mr. Deputy Speaker, Sir, I have just now received this statement from the Table Office, even then I want to know from the Hon'ble Minister that if the Power generators are established near the places where coal is available in abundance. Have you worked out whether the laying of transmission lines is more costly or whether the transportation of coal is more costly, so that the power is generated at cheaper rates, because in this the question, the availability of wagons is involved?

Further I want to know the names of the places where it is proposed to establish Thermal Power Stations during the Fifth Five Year Plan along with the names of the places where these have already been established?

Shri K. C. Pant: Sir, it is a fact that if a Power Station is set up near the place where coal is available in abundance, the power generated there is cheaper as compared to that generated in the power station established at a place where coal

is not available, but we have to see about the cost to be incurred on laying of the transmission lines and also the expenditure to be incurred on the transmission of the power, as the Hon'ble member has said we cannot state the exact position, if we don't take note of the expenditure on the transmission of power from the place, where the power is generated to the place where it is to be consumed. So we have to see the both aspects, only then we would be able to decide about the site or the establishment of the power station.

We propse to set up some big power stations which are called as power stations and we have appointed a committee to select the sites for the establishment of these super power stations. The report of this Committee is likely to be submitted soon.

Shri Jagannathrao Joshi: In the context of part (b) of my question, it appears that one of the reasons for so much delay in the completion of construction works is this that this work has been entrusted to the State Electricity Board. Therefore, I want to know whether there are reasons also for this delay or the state Government have not done this work properly. Now the question arises that the power is being generated in the whole of the country, this is generated from water, thermal and Atom, and this power is supplied for agricultural, industrial and domestic consumption, but the rates for each state are different. I don't like this thing. May I know whether the Government would think over it that there should be uniform rates of the power in each state and each category.

Shri K. C. Pant: So far as the second question is concerned, each state has been empowered to fix its rates and as the Hon'ble member has said, to have uniform rates, but it is not so easy to introduce uniform rates of the power. For example, the power in Kerala and Karnataka is being generated is Hydel power and it is cheaper. The power in Madhya Pradesh and Vidarbha is being produced from coal and there is much difference in it. We would have to take note of all these rates and all such these things and when the national grid would be established and the time of considering the tariff question we would see that upto which extent we can reduce the difference to the minimum.

So far as your first question is concerned, I have only to say that the State Governments have not delayed intentionally and it is in the interest of the State Governments to complete these projects as soon as possible and generate the power, but sometimes some such conditions are created, as the material is not available to them, so they can not complete work soon. Therefore we would have to consider all these things, but I think that the State and Central Governments would have to give special attention to this during the Fifth Five Year Plan and they should take special steps to implement the targets fixed in the Fifth Five Year Plan.

श्री डी० डी० देसाई : श्रीमान् जी, माननीय मंत्री ने जल-विद्युत् की कम दरों का उल्लेख किया है और वर्तमान प्रश्न में भी सस्ती बिजली का उल्लेख किया गया है। उन्होंने प्रेषण तथा वितरण लाईनों की कम लागत के प्रभाव का भी उल्लेख किया है। इस संबंध में 15 लाख किलोवाट की क्षमता वाली नर्मदा जल विद्युत् परियोजना पर सब से कम लागत आयेगी। प्रत्येक जल-विद्युत् परियोजना में जलमग्नता होती है और जिससे बचा नहीं जा सकता। अत: क्या मंत्री महोदय नर्मदा जल विद्युत् परियोजना को शीघ्र पूरा करेंगे, ताकि नर्मदा से 15 लाख किलोवाट की बिजली से समस्त पश्चिम भारत . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक विशेष मामला है।

श्री डी० डी० देसाई : हम सस्ती जल-विद्युत की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है। आप एक विशेष मामले को विस्तृत रूप दे रहे हैं।

श्री डी० डी० देसाई : मुझे एक सामान्य प्रश्न पूछने दीजिये। क्या नर्मदा सहित जल विद्युत् परि-योजनाओं को यथा सम्भव पूरा किया जायेगा या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप एक विशेष परियोजना सहित जल विद्युत् उत्पादन पर ज़ोर देंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे विचार में उनकी रूचि सामान्य उत्तर में नहीं है। जहां तक विशेष प्रश्न का संबंध है, यह अन्तर्राज्यिय विवाद का विषय है और इस बात को मेरे मित्र जानते हैं।

श्री जे० माता गौडर : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि कितने बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के बारे में विचार किया जा रहा है और ये किन-किन राज्यों से संबंधित हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न यह है कि कितनी परियोजनाये विचाराधिन हैं। इनकी संख्या नहीं बतायी गयी ह। किन्तु विवरण में सामान्य स्थिति का उल्लेख किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप को इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे राज्यों के नामों के संबंध में सूचना की आवश्यकता है। कुछ सूचना दी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बताया है कि कितनी बिजली का उत्पादन होगा।

श्री वयालार रवी : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि चुंकि केरल सस्ती बिजली का उत्पादन करने वाला एक राज्य है, इसलिये क्या यह सच है कि इद्दीकी परियोजना पर जो पूरी होने वाली है, धन के अभाव के कारण हाल ही में बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने इस धन का नियतन नहीं किया है। यदि हां, तो इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिय क्या कायवाही की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि यदि मैं एक विशेष प्रश्न की अनुमति देता हूं, तो मुझे भारत में सभी परियोजनाओं के संबंध में प्रश्नों को पूछने के लिये अनुमति देनी होगी।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं, क्या सरकार यह बात जानती है कि युद्ध से पूर्व पश्चिम बंगाल की सरकार ने सकोदा एण्ड कम्पनी से नगर की रद्दी और कूड़ा करकट से बिजली का उत्पादन करने की एक विशेष योजना खरीदी थी। इस का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि इस बात को सरकार नहीं जानती है, तो क्या वह इस मामले की जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की कलकत्ता नगर की रद्दी और कूड़ा करकट से बिजली बनाने के लिये इसे प्रयोग में लाया जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इसकी जांच करनी होगी।

डा० महिपतराय मेहता : बिजली की कमी के संदर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने बी० एच० ई० एल०, हरिद्वार को बिजली उत्पादन उपकरण के लिये क्रयादेश दिये थे, किन्तु ये उपकरण अभीतक निर्माताओं के पास पड़े हुये हैं, क्योंकि उन्हें उठाया नहीं गया है ? यदि हां, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि इस मशीनरी को उठाया जाय तथा इसका बिजली उत्पादन के लिये उपयोग किया जाये ताकि बिजली की कमी को दूर किया जा सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है ?

डा० महिपतराय मेहता : यदि मशीनरी को उठा लिया जाये, तो अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मशीनरी को उठाने के बारे में आपको पृथक प्रश्न पूछना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कोयले और बिजली की बढ़ती हुई कमी तथा बिजली संकट को देखते हुये, ऊर्जा शक्ति के एक वैकल्पिक साधन के रुप में सूर्य-प्रकाश का उपयोग करने के लिये वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है और यदि हां, तो क्या इस सूर्य की ऊर्जा का उपयोग सूर्य के जल हीटरो, कृषि उत्पाद के लिये सूय शोषकों, सूर्य यंत्रकों तथा घरेलू प्रकाश के लिये शक्ति प्रदान के लिये किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सुझाव कार्य किये जाने योग्य है ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या सरकार ऊर्जा के एक वैकल्पिक साधन के रूप में सूर्य ऊर्जा का उपयोग करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एक बिजली-दल की नियुक्ति की गयी थी जो ऊर्जा के गैर-परम्परागत साधनों के प्रश्न पर विचार कर रहा है । चूंकि सूर्य ऊर्जा उन में से एक साधन है, इसलिये भारत में निश्चित रुप से इस पर अध्ययन किया जा रहा है । कुछ वर्ष पूर्व इस बारे में थोड़ा बहुत विचार शुरू हुआ था । किन्तु, बाद में इस के प्रति रूचि में कमी आ गयी । अब हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि इस पर फिर से विचार शुरू किया जाये ।

श्री रामसहाय पांडे : कई बार सभा में यह सुझाव दिया गया है कि इस संकट को मुहानों पर बिजली उत्पादन करके, संयंत्रों विशषकर मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जहां कोयला काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, दूर किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : विवरण में यह बात बतायी गयी है । यह सुझाव कार्य करने योग्य है ।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या 1965 में नियुक्त ऊर्जा आयोग की, जिसके साथ विदेशी विशेषज्ञों को सम्बद्ध किया गया था, शिफ़ारिशों को ध्यान में रखा गया, विशेषकर कि उन क्षेत्रों में बिजली केन्द्रों के स्थापना करने के मामले में ऐसा किया गया है जहां वास्तविक सप्लाई की जानी होती है , ताकि वहां लम्बी प्रेषण लाइनें न बनायीं जायें ?

उपाध्यक्ष महोदय : विवरण में मंत्री महोदय ने बताया है कि वह इसे करेंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने पहले ही बता दिया है कि तापीय बिजली कारखानों के स्थाननिर्धारण के मामले में, इन दोनों बातों, अर्थात कोयला-उत्पादन करने वाले क्षेत्र की निकटता और उपभोक्ता केन्द्रों की दूरी को ध्यान में रखना होगा ।

बर्मा शेल और कालटैक्स द्वारा अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि करने की मांग

***690. श्री वी० मायावन :**
श्री देवेंद्र सिंह गरचा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों की तेल कम्पनियों और खाड़ी के देशों के बीच पत्ती (पार्टिसिपेशन) करार के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप अशोधित तेल के मूल्यों में और वृद्धि होने की सरकार को आशंका है ;

(ख) क्या इस करार के बाद बर्मा शेल और कालटैक्स कम्पनियों ने भूतलक्षी प्रभाव से तेल मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ): (क) से (ग) पश्चिमी देशों की तेल कम्पनियों और कुछ खाड़ी देशों के बीच सहभागिता करार के पुनरीक्षण के लिए अभी बातचीत चल रही हैं । इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम करार हो जाने पर इसे गत 1 जनवरी, 1974 से लागू करने की सम्भावना है । तेल कम्पनियों की प्रति बैरल लागत पर अन्तिम समझौते का सही प्रभाव करार को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही जाना जा सकेगा । तथापि, बर्मा शेल और कालटैक्स ने इस करार के पुनरीक्षण के पूर्वानुमान में अपने मूल्यों में अस्थाई वृद्धि सूचित की है । ऐस्सो ने भी इसी आधार पर केवल 1 मार्च, 1974 से मूल्य बढ़ाने के लिए कहा है । इस समय इस मामले की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री वी० मायावन : क्या मंत्री महोदय से मैं यह जान सकता हूं कि इस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? बर्मा शैल और कालटैक्स ने इस पत्ती (पार्टिसिपेशन) करार के पुनरीक्षण के पूर्वानुमान में अपने मूल्यों में अस्थायी वृद्धि सूचित की है । क्या सरकार ने इन दोनों कम्पनियों पर तब तक मूल्य न बढ़ाने के लिये जोर दिया जब तक पश्चिमी तेल कम्पनियों और खाड़ी के कुछ देशों के बातचीत को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता ?

श्री देवकान्त बरुआ : मैं तेल कम्पनियों और तेल उत्पादक देशों के बीच पत्ती (पार्टिसिपेशन) करार के बारे में सही स्थिति का जानना पसंद करूंगा . . .

श्री वी० मायावन : सरकार की इस के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री देवकान्त बरुआ : हम उन्हें इस बारे में पुनर्विचार करने के लिये कह रहे हैं ।

श्री वी० मायावन : क्या भारत सरकार इन दोनों कम्पनियों को एस्सो कम्पनी की तरह अपने नियंत्रण में ले लेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है । मेरे विचार में एक नीति वक्तव्य दिया गया था और यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था ।

श्री देवकान्त बरुआ : सरकार इन कम्पनियों को यथाशीघ्र अपने नियंत्रण में ले लेगी ।

Shri Jagannath Mishra: Sir, may I know whether our financial cooperation with oil surplus countries does not have good effect on the prices of oil and if so, this question of rise in prices by Burmah Shell and the Caltex company does not arise ?

श्री देवकान्त बरुआ : तेल उत्पादक देश अपने द्वारा 1 जनवरी, 1974 को स्वीकृत अपने सूत्र के आधार पर तेल बेच रहे हैं और उन्होंने उस मूल्य को जिसे वे 'पोस्टिड' मूल्य कहते हैं, बढ़ाकर लगभग 11.57 डालर कर दिया । उस में से जो मूल्य हम ने देना होता है, वह इसका 93 प्रतिशत है । जहां तक राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बिक्री का संबंध है , उन्होंने यह मूल्य निश्चित कर दिया है ।

जहां तक तेल कम्पनियों का संबंध है, वे इस करार पर दृढ़ रहेंगी जो उन्होंने अपने और तेल कम्पनियों के बीच किया है । यही कारण है कि तेल कम्पनियां राष्ट्रीय कम्पनियों की तुलना में कम मूल्य वसूल करने की स्थिति में हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि मैंने मंत्री महोदय की बात ठीक समझी है, तो उन्होंने कहा है कि बर्मा शैल तथा कालटैक्स ने पहले ही उस वृद्धि के पूर्वानुमान में मूल्यों में वृद्धि के लिये सरकार से कहा है जिस की स्वीकृति खाड़ी देशों तथा तेल कम्पनियों के बीच करार द्वारा प्रदान की जाती है । अत: मैं उन से यह जानना चाहूंगा कि बर्मा शैल और कालटैक्स ने पूर्वानुमान में प्रति बैरल कितनी वृद्धि करने के लिये कहा है और दूसरे यह कि श्री मायावन के मूल प्रश्न के उत्तर में उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख क्यों नहीं किया जो

कि उन्होंने बाद में उनके अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा कि सरकार ने इन कम्पनियों को अपनी मांग पर पुर्नविचार करने के लिये कहा है। मैं विशेषकर कि यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने उन्हें मूल्य में पूर्वानुमानित वृद्धि के लिये नहीं, अपितु, प्रतीक्षा करने के लिये कहा है तो क्या इन कम्पनियों की प्रतिक्रिया उपलब्ध हो गयी है और उन्होंने सरकार को इस बारे में क्या कहा है। मैंने मूल्य में पूर्वानुमानित वृद्धि के बारे में कभी भी नहीं सुना है। वे प्रतीक्षा करने के लिये भी तयार नहीं हैं।

श्री देवकान्त बरुआ : मैं बता चुका हूं कि इस पर विचार किया जा रहा है। हमारी भुगतान करने की इच्छा नहीं है। हमने उन्हें बता दिया है कि हम भुगतान नहीं करेंगे। उन्होंने प्रस्ताव किया था। हमने इसे स्वीकार नही किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक बैरल के मूल्य में कितनी वृद्धि मांगी गई है।

श्री देवकान्त बरुआ : उन्होंने 1 जनवरी 1974 से नये मूल्य बताये हैं। कालटैक्स ने 8.97 डालर प्रति बरल और बर्माशेल ने 9.12 डालर प्रति बैरल की मात्रा की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसमें वृद्धि की मांग कितनी है।

श्री देवकान्त बरुआ : यह मूल्य उन्होंने मांगा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पूरे आंकड़े बता दिये है। वह पुराने मूल्यों की तुलना में वृद्धि की मात्रा जानना चाहते है।

श्री देवकान्त बरुआ : मैं प्रतिशतता नहीं बता सकता। मैं सही आकड़ें बता सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : गणना वह स्वयं कर लेंगे।

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक एक्सन का सम्बन्ध है हम प्रति बैरल 8.29 डालर के हिसाब से भुगतान कर रहे है अब वे 9.27 डालर प्रति बैरल मांगते है। कालटेक्स ने 8.97 डालर और बर्मा शैल ने 9.12 डालर प्रति बैरल की मांग की है। हम जो मूल्य उन्हें दे वे एक से अर्थात 8.29 अथवा 8.30 डालर प्रति बैरल होने चाहिये।

Scheme to introduce additional fast train between Lucknow and Delhi

*692. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme to introduce an additional fast train between Lucknow and Delhi keeping in view the increasing passenger traffic on this line; and

(b) if so, the time by which this scheme will be implemented?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, may I know the number of trains running between Delhi and New Delhi upto Lucknow and via Lucknow and what is the capacity of these trains . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है। मूल प्रश्न अतिरिक्त तेज गाड़ी चलाने के बारे में है। अब आप लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली गाड़ियों की संख्या पूछ रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: I am asking this Question because the passenger traffic is increasing and the Hon. Minister has said 'no' in his reply. Therefore, I want to know the number of trains running at present, the number of fast trains and the number of trains running in a week and the number of passengers do not find themselves able to avail this service.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: There are 20-30 Lucknow Mail and 83-84 Lucknow Express running between New Delhi and Delhi to Lucknow. Both of them start at night. Besides these two trains there is one 55-56 Delhi-Patna Express which starts during the day time. Thus, there are only three trains. Trains starting at night carry heavy rush whereas there is no rush in Delhi-Patna Express. The main difficulty is that we do not have terminal capacity at present that is why we cannot introduce more trains.

Shri Hukam Chand Kachwai: The Hon. Minister has agreed that there is heavy rush in the trains running at night. We find 300 passengers travelling in a bogie having the capacity of 70 or 80 passengers. Will he be kind enough to enquire into the matter? Pockets are picked and there are other disturbances due to this heavy rush. Passengers have to pay something to get a seat.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: He knows better about pick pockets. I have no information in this regard. But, this is a fact that there is overcrowding in these trains. We are taking steps to see that the rush is reduced. We are trying to add more bogies with these trains.

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, my question has not been replied.

उपाध्यक्ष महोदय: आपने जेब कतरों के बारे में पूछा । मंत्री महोदय इसका उत्तर किस प्रकार दे सकते हैं । वह जेब-कतरों के कार्यभारी नहीं हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, I wanted to know the steps proposed to be taken to reduce the rush of the passengers and for this purpose whether they intend to add more bogies to the existing trains or propose to provide additional train. What is governments shceme in this regard?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: मैंने बताया है कि इन दोनों गाड़ियों में अर्थात् 29–30 लखनऊ मेल, 83–84 लखनऊ एक्सप्रेस क्षमता का उपयोग तीसरी श्रेणी 109-110 प्रतिशत है । अटेन्डेट का (ए० सी०) में 93 प्रतिशत तथा प्रथम श्रेणी में 88 प्रतिशत । उनमें भीड़ कम है ।

Shri D. N. Tiwary: This is the only link for Uttar Pradesh and north Bihar. In case there is no train at Lucknow, passengers cannot reach in parts of east Uttar Pradesh and north Bihar. May I know the reasons for which the government do not intend to introduce additional train while there is heavy traffic on this route?

Shri Mohd Shafi Qureshi: We are making efforts to see that more travelling facilities are available to passengers. But the difficulty is that unless there is one more terminal at Delhi we cannot provide additional fast train between Delhi and Lucknow.

उपाध्यक्ष महोदय: : अगला प्रश्न–प्रश्न संख्या 693 । इस के साथ ही प्रश्न संख्या 706 भी लिया जायेगा । दोनों प्रश्न एक जैसे हैं ।

रेलवे वर्कशापों में वैगनों के उत्पादन में कमी

***693. श्री इन्द्रजीत गुप्त† :**

श्री एम० कल्याण सुन्दरम :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे वर्कशापों में वैगनों के उत्पादन में कमी की है ;

(ख) क्या सरकार ने गैर-सरकारी वैगन निर्माताओं को अधिक वैगनों का आर्डर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन गैर-सरकारी वैगन निर्माताओं के नाम क्या हैं जिनके आर्डरों में वृद्धि की गई है ; और

(घ) इन गैर-सरकारी वैगन निर्माताओं की क्षमता क्या है ?

रेल मंत्री (श्री एल०एन० मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) पिछले वर्षों की तुलना में 1973-74 में गैर-सरकारी माल डिब्बा निर्माताओं को सब मिलाकर दिये गये आर्डरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । लेकिन निम्नलिखित पांच गैर-सरकारी माल-डिब्बा निर्माताओं को अधिक आर्डर मिले हैं क्योंकि उनका काम अधिक अच्छा होने के कारण बकाया कम था ।

1. मेसर्स टेक्समेको
2. मेसर्स सिमको
3. मेसर्स ब्रेथवेट
4. मैसर्स मौडर्न इंडस्ट्रीज
5. मैसर्स जेसप एण्ड कं०

इन माल डिब्बा निर्माताओं की क्षमता इस प्रकार है :—

(आंकड़े चौपहिओं के हिसाब से)

	लाइसेंस शुदा क्षमता	संस्थापित क्षमता
मेसर्स टेक्समेको . . .	3600	3600
मेसर्स सिमको .	2000	2000
मेसर्स ब्रेथवेट	3000	3000
मेसर्स मौडर्न इंडस्ट्रीज	2000	2000
मेसर्स जेसप एण्ड कं०	3279	3279

वैगन की कीमतों सम्बन्धी सूत्र (फार्मूला) के बारे में समझौता

***706 श्री प्रसन्नभाई मेहता† :**
श्री तरुण गोगोई :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगन की कीमतों सम्बन्धी सूत्र के बारे में कोई समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्रा) : (क) से (ग) मालडिब्बों के मूल्यों के बारे में भारी उद्योग मंत्रालय के परामर्श से समझौता हो गया है । इन मूल्यों का परिकलन करते समय जिन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(i) इस्पात की लागत ।

(ii) खरीदे गये पुर्जों की लागत ।

(iii) परिवर्तन की लागत ।

(iv) परिवर्तन की लागत का 15 प्रतिशत की दर से लाभ ।

उपर्युक्त समझौते के आधार पर 1973-74 के चल-स्टाक कार्यक्रम के अन्तर्गत मालडिब्बों के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में बताया गया है कि माल डिब्बे बनाने वाली पांच गैर-सरकारी फर्मों को वर्ष 1973-74 में अधिक माल डिब्बों के क्रयादेश दिये गये । मैं यह बात जानना चाहता हूं कि वर्ष 1973-74 के दौरान इन पांच फर्मों को दिये गये क्रयादेशों में किस सीमा तक वृद्धि की गई और उनसे कितने अधिक माल डिब्बे सप्लाई करने के लिये कहा गया ।

श्री एल०एन० मिश्र : वर्ष 1972-73 में टैक्समाको ने 2859.5 माल डिब्बे सप्लाई किये और इस वर्ष 2870 माल डिब्बों का आदेश दिया गया है । ब्रैथवेट ने 2527.5 माल-डिब्बे सप्लाई किये और इस वर्ष 3476 माल-डिब्बों का क्रयादेश दिया गया है । मेरे पास लम्बी सूची है । माडर्न इन्डस्ट्रीज ने 378 माल-डिब्बे सप्लाई किये और उन्हें 850 माल-डिब्बों की सप्लाई के लिये क्रयादेश दिये गये हैं । जैसप्स ने 200 माल-डिब्बे सप्लाई किये और अब 900 माल डिब्बों की सप्लाई के लिये क्रयादेश दिये गये हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ब्रैथवेट तथा जैसप्स को पूर्ण रूप से गैरसरकारी फर्म बताना ठीक नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : वे गैरसरकारी नहीं हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु मंत्री महोदय ने उन्हें अपने उत्तर में माल-डिब्बे बनाने वाली गैर सरकारी फर्म बताया है । इस उत्तर से पता चलता है कि दो बड़ी फर्मों—बर्न एण्ड कम्पनी तथा इन्डियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी—का उल्लेख नहीं किया गया है । क्या यह सच है कि क्या इन कम्पनियों के साथ पहले वर्षों में अर्थात् 1972-73 में जो मूल्य निश्चित किये गये थे वे इन फर्मों के अनुसार इतने कम थे कि उनके लिये बकाया माल डिब्बों की सप्लाई करना संभव नहीं था और इसीलिये फर्मों ने मूल्य वृद्धि की मांग की । यदि ऐसा है, तो क्या मूल्य बढ़ाने से इन्कार करने के कारण ही इन कम्पनियों को अधिक क्रयादेश नहीं दिये गये ।

श्री एल० एन० मिश्रा : श्री इन्द्रजीत गुप्त को पता है कि माल डिब्बे बनाने, माल डिब्बों का निर्माण और उत्पादन, भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। पहले यह रेल मंत्रालय के अधीन था परन्तु जब भारी उद्योग मंत्रालय बना तब यह कार्य उनके पास चला गया। अतः सीधा दायित्व भारी उद्योग मंत्रालय का है। और इस समय इस सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि उन्हें बड़े आदेश उनका निष्पादन देखते हुये दिये गये। उत्तम निष्पादन तथा उत्तम प्रकार के कारण ही उन्हें अधिक क्रयादेश दिये गये। इसके लिये इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या क्रयादेश रेल मंत्रालय ने नहीं अपितु भारी उद्योग मंत्रालय ने दिये हैं।

श्री एल०एन० मिश्र : हम अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं और वे हमारी ओर से सरकारी तथा गैर सरकारी कारखानों को क्रयादेश देते हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या माल-डिब्बों के मूल्य सम्बन्धी फारमूले के बारे में भारी उद्योग मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के बीच कोई मतभेद था? किसने अधिक मूल्यों की मांग की तथा कब? करार कब किया गया? वर्ष 1971-72 के दौरान माल डिब्बों के उत्पादन में कितनी कमी हुई?

श्री एल० एन० मिश्र : जहाँ तक पहले प्रश्न अर्थात् अधिक मूल्य मांगने का सम्बन्ध है, इस्पात उपकरणों तथा श्रमिकों पर आने वाली लागत में वृद्धि हो जाने के कारण लगभग सभी गैरसरकारी तथा सरकारी कारखानों ने मूल्यवृद्धि की मांग की। अतः दोनों क्षेत्रों सरकारी तथा गैर सरकारी द्वारा यह मांग की गई। माल डिब्बों के मूल्य में हमने काफी वृद्धि की अनुमति दी है। जहाँ तक 1971-72 में उत्पादन का सम्बन्ध है इस प्रश्न के लिये नोटिस दिये जाने की आवश्यकता है। एक यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या कोई मतभेद था? कोई मतभेद नहीं है। हम मिल जुलकर कार्य करते हैं। हमने आपस में बात-चीत की। श्री पाई के साथ मेरी स्वयं की तीन बैठकें हुई। अतः हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : प्रस्ताव कब रखा गया था? समझौता कब हुआ? ये मूल प्रश्न हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : फरवरी अथवा मार्च में।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : रेलवे वर्कशाप तथा माल डिब्बे बनाने वाली गैर सरकारी कम्पनी में सामान्य रूप से उत्पादन लागत कितनी आती है? यदि कोई अन्तर है तो कितना?

श्री एल0 एन0 मिश्र : श्री गोस्वामी बड़े चतुर व्यक्ति हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल में एक चतुर व्यक्ति भी होना चाहिये।

श्री एल० एन० मिश्र : उत्पादन लागत बताना किसी भी उत्पादक के लिये वांच्छनीय नहीं है। जहाँ तक रेलवे के कारखानों का सम्बन्ध है, सरकारी उत्पादन लागत बताना सार्वजनिक हित में नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता चलता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्या यह सच है कि हम बहुत से समाजवादी देशों को माल-डिब्बों का निर्यात कर रहे थ, यदि हां तो उसका क्या हुआ? वर्ष 1971-72 के निर्यात आंकड़े क्या हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : निर्यात का मामला बीच में कैसे आ गया? प्रश्न यहाँ निर्माण पर आने वाली लागत का है। निर्यात एक अलग प्रश्न है। कृपया निर्यात की बात इसमें न लाइये। यह प्रश्न वाणिज्य मंत्री से पूछिये। आप कोई दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री भाटिया।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : रेलवे वर्कशाप अमृतसर में एक वर्ष में 3000 से 3500 माल-डिब्बे बनते थे। अब वहाँ केवल 1500 के लगभग माल-डिब्बे बनते हैं। अमृतसर वर्कशाप की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है? गैर सरकारी कम्पनी को क्रयादेश क्यों दिया गया?

श्री एल० एन० मिश्र : यह सरकारी अथवा गैर सरकारी कम्पनी को क्रयादेश देने का प्रश्न नहीं है। इस समय हमारे पास चार कारखाने हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा कार्यक्रम इन चारों कारखानों अमृतसर, समस्तीपुर तथा अन्य स्थानों पर, की क्षमता को दुगना करने का है। कारखानों में माल-डिब्बों का उत्पादन दुगना करने की क्षमता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैंने मंत्री महोदय द्वारा दिया गया विवरण देखा है। इस समय माल-डिब्बों की वास्तविक रूप में कितनी आवश्यकता है और क्या रेलवे में सप्लाई और मांग की स्थिति में कोई अन्तर है ?

श्री एल० एन० मिश्र : पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में अन्तर हो सकता है। इस समय रेल वैगनों के बारे में हमें कोई कठिनाई नहीं है। जहां तक वैगनों के निर्माण का संबंध है उसमें कोई समस्या नहीं है। हमारी समस्या तो वैगनों के परिवहन के संबंध में है। जहां तक निर्माण किये जाने वाले वैगनों की संख्या की बात है उस बारे में हमारी कोई समस्या नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस बारे में हमारा भी कुछ अनुभव है। इसी कारण मैं जानना चाहता हूं कि रेल्वे के लिये वैगनों की कुल कितनी आवश्यकता है।

श्री समर गुह : क्या जैसप एण्ड कम्पनी जैसी गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को बढ़ा हुआ क्रयादेश देने से पूर्व सरकार न इस बात की जांच की थी कि क्या सरकारी कारखानों द्वारा वैगन निर्माण की स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं ? क्या लागत के प्रश्न पर भी विचार किया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमने मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर यह विचार किया है। गैर-सरकारी कम्पनी को क्रयादेश देने से पूर्व लागत के प्रश्न पर विचार किया गया था। जहां तक वैगन निर्माण संयंत्रों की क्षमता की बात है हम पूर्ण क्षमता के उपयोग के प्रयास कर रहे हैं।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। गैर सरकारी कम्पनी को क्रयादेश देने से पूर्व क्या इस बात की जांच की गई थी कि सरकारी कम्पनियों की स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि "हां"।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Deputy Speaker, Sir, in reply to the main question the hon. Minister has stated that some Iron and some components are required for the manufacture of a wagon. May I know how much Iron is required, how many components are required and what is the labour cost involved? What is the manufactured cost of a wagon and is it the same in private sector companies also? If no, how much is the difference between the two?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इन के सब उत्तर के लिये उन्हें पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

Shri Hukam Chand Kachwai: Hon. Minister has got the figures but he is reluctant to give.

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं। उन्हें यह प्राप्त करने हैं। आंकड़े रेल भवन में तयार होते हैं। उनके पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: Hon. Minister has got all the information but he does not want to give. If information is not available with him at this time he should say that information would be collected and supplied later on. .. (*Interruptions*). I want the information. Manufacturing cost of a Government factory is more whereas in case of a private company it is less. (*Interruptions*).

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो मैं आगे से आपका नाम पुकारने से पूर्व सोचुंगा। आप इसके लिये अलग से प्रश्न पूछें और मंत्री महोदय उत्तर देंगे। कृपया बैठ जाय।

(अन्तर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। शांति, शांति। मैं श्री साठे और मंत्री महोदय की बातों के अतिरिक्त किसी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा।

श्री वसन्त साठे : माननीय मंत्री के इस उत्तर को देखते हुए कि वैगनों की कमी नहीं अपितु वास्तविक कठिनाई परिवहन के संबंध में है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किय जा रहे हैं कि वैगनों को किसी विशेष स्टेशन पर अधिक अवधि तक रोका न जाय और वे प्रयोग में रहें।

श्री एल० एन० मिश्र : हमारा वैगनों को हर समय चलते रहने का एक कार्यक्रम है परंतु वैगनों के परिवहन में कमी रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि काफी संख्या में वैगने अनुपयोगी घोषित कर दी गई हैं और चोरियों के कारण वैगने तोडी गई और इसकी प्रतिशतता बढ़ गई है। इस प्रकार वगनों की कमी हुई है। परंतु हम इस बात के लिये विशेष प्रयास कर रहे हैं कि अनुपयोगी वैगन भी प्रयोग में लाये जा सकें और जैसा कि श्री साठे को ज्ञात है पिछले वर्ष विलम्ब शुल्क दोगुने किये गये थे जिससे कि लोग वैगनों को खाली खड़ा न करें।

Shri Ramavatar Shastri: Is it a fact that in order to manufacture increased number of wagons the Government has decided to take over Arthur Butler and Co., Muzaffarpur and Britania Engineering Company, Mokameh? If so, when the manufacturing operations would start in both these units and how many wagons would be manufactured annually?

Shri L. N. Mishra: So far as Arthur Butler & Co. is concerned the Government has come to the decision and has already been taken over but the old owners have moved the High Court and obtained the writ.

So far Britania Engineering Co. is concerned we have decided in principle to bring it under Public Sector. There are some legal difficulties, therefore, some delay is taking place but we are waiting for the writ to be vacated by the High Court and then take it over.

Shri Ramavatar Shastri: You have already started manufacturing operation in Mokameh Compay. .. (*Interruptions*)

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में उत्पादित एक डीजल इंजन की लागत

*694. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में कितने डीजल इंजन बनाये गये ; और

(ख) इस कारखाने में निर्मित एक इंजन की लागत क्या है तथा अन्य कारखानों में निर्मित डीजल इंजनों की और आयातित डीजल इंजनों की उत्पादन लागत की तुलना में यहां निर्मित डीजल इंजनों की लागत कितनी न्यूनाधिक है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों में डीज़ल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में तैयार किये गये डीज़ल बिजली रेल इंजनों की कुल संख्या इस प्रकार थी :—

वर्ष	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	जोड़
1971–72	70	35	105
1972–73	60	35	95
1973–74	54	33	87

(ख) (i) 1970-71 से 1972-73 तक डीज़ल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में तैयार किये गये मुख्य लाइन के डीज़ल बिजली रेल इंजनों की औसत लागत इस प्रकार रही :—

प्रति डीझल बीजली रेल इंजन लागत
(लाख रुपयों में)

वर्ष	प्रोफार्मा प्रभार को छोड़कर		प्रोफार्मा प्रभार सहित	
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1970–71 . . .	23.44	18.12	26.86	21.24
1971–72 . . .	22.59	17.90	25.08	20.01
1972–73 . . .	27.13	17.93	30.46	20.12

(ii) डीज़ल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में जिस प्रकार के डीज़ल बिजली रेल इंजन तैयार किये जा रहे हैं, उस प्रकार के रेल इंजन किसी अन्य रेलवे उत्पादन कारखाने अथवा सार्वजनिक /निजी क्षेत्र के उत्पादन कारखाने में तैयार नहीं किये जा रहे हैं। इसलिए उत्पादन लागत की तुलना करना संभव नहीं है।

(iii) वाराणसी में तैयार किये जा रहे मुख्य लाइन के डीज़ल बिजली रेल इंजनों की तरह के रेल इंजनों का पिछले तीन वर्षों में आयात नहीं हुआ है। अतः इसी प्रकार के आयातित रेल इंजनों की तुलनात्मक लागत उपलब्ध नहीं है।

श्री शक्ति कुमार सरकार : मंत्री महोदय ने सावधानी से उत्तर टाल दिया है। यह भारत के एक महत्वपूर्ण उद्योग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे किन्ही डीज़ल इंजिनों का आयात कर रहे हैं अथवा गत तीन वर्षों में डीजल इंजिन आयात किये गये।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जिस प्रकार के डीजल इंजिनों का डीजल वर्कशापों में निर्माण किया जाता है उस प्रकार के इंजिनों का गत तीन वर्षों में कोई आयात नहीं किया गया। अतः, जैसा कि मैंने पहिले कहा है उत्पादन लागत की तुलना संभव नहीं है।

श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या यह सच है कि नियन्त्रक और महालेखाकार ने डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के कार्यकरण की काफी आलोचना की है? यह प्रश्न कैसे उठा? क्या इसका कारण यह है कि लागत का अनुमान समुचित ढंग से नहीं लगाया गया था?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : नियन्त्रक तथा महालेखाकार की आलोचना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इस की जांच करूंगा और माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध करूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उत्तर से प्रतीत होता है कि वाराणसी वर्कशाप में 1971-72 में 105 डीजल इंजिन बनाए गए; 1972-73 में 95 बनाए गए और 1973-74 में यह संख्या घट कर 87 हो गई। मैं मंत्री महोदय से उत्पादन में इस क्रमिक गिरावट के कारण जानना चाहता हूं। यह भी जानना चाहता हूं कि इंजन की उत्पादन लागत में वृद्धि का क्या कारण है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापित क्षमता 150 लोकोमोटिव प्रति वर्ष है। परंतु जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा बताए गए आंकड़ों से पता चलता है। हम 1971-72 में 105 लोकोमोटिव इंजिनों का निर्माण कर सके और 1973-74 में उत्पादन गिर कर 87 हो गया। शायद यह 100 तक पहुंच जाय, क्योंकि आंकड़े नवीनतम नहीं हैं। मुख्य कारण श्रमिक अनुशासनहीनता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्रश्न . . .

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मुख्य कारण श्रमिक अनुशासनहीनता, बिजली की कटौती और आयात किये जाने वाले कुछ अतिरिक्त उपकरणों की अनुपलब्धता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : और अत्यधिक भ्रष्टाचार।

Shri Mohd. Jamilurrahman: May I know the Engine manufacturing capacity of D.C.W. Varanasi and how much they supplied during these three years? I am asking this question as the production is falling every year. Is it a fact that there were disturbances in 1972-73 and some workers were killed, which hampered the production? The second reason is there is discontentment amongst the staff with regard to promotion. Their promotion cases are pending since a long time and has it also affected production?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I have already replied that the installed capacity is 150 Diesel Engines. It includes both, meter gauge as well as broad gauge Engines. 105 Engines were manufactured during 1971-72; 95 Engines in 1972-73 and production would touch 100 Engines during 1973-74. It is a fact that labour trouble has adversely affected the production. In addition there was Power cut and some components and spares which were to be imported from abroad, were not received in time. It also affected the production.

कोचीन तेल-शोधक कारखाने के कर्मचारियों को एक दिन के वेतन की अदायगी न करना

*695. **श्री वयालार रवि** :
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'केरल बन्द' में भाग लेने के कारण कोचीन तेलशोधक कारखाने के कर्मचारियों के वेतन से एक दिन के वेतन की कटौती की गई थी;

(ख) क्या कोचीन तेलशोधक कारखाना कर्मचारी संघ ने काम करने की इच्छा व्यक्त की थी और पर्याप्त सुरक्षा तथा परिवहन सुविधायें उपलब्ध करने के लिए प्रबन्धकों से अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो उनकी एक दिन की मजूरी का भुगतान न करने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) से (ग) केरल बन्द के दौरान 21 दिसम्बर 1973 को कोचीन शोधनशाला में 339 कामगारों में से 69 कामगार बिना अवकाश लिए अनुपस्थित थे। बन्द के परिणामस्वरुप तेल शोधनशाला के प्रबन्ध ने अनुपस्थित कर्मचारियों को अपनी आकस्मिक छुट्टी में से उस दिन का समायोजन करने की अनुमति दी थी। 69 अनुपस्थितों में से 26 ने अवकाश का समायोजन किया और उनके वेतन में कटौती नहीं हुई। शेष 43 कर्मचारियों ने अवकाश का समायोजन नहीं कराना चाहा अतः एक दिन के लिए वेतन की हानी उठाई।

अप्रिय घटनाओं के डर से कम्पनी ने बन्द के दिन गाडियां नहीं चलाई। बन्द से पहले कर्मचारी संघ को इसकी सूचना दी गई थी। काम पर आने के लिए संघ ने प्रबन्ध द्वारा परिवहन की सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने के संबंध में कोई शर्त नहीं लगाई थी। कंपनी की परिवहन सुविधाएं उपलब्ध न होने के बावजूद अधिकांश कर्मचारी काम पर आये और जो काम पर नहीं आये उनको छुट्टी समायोजन करने की सुविधा दी गई थी।

श्री वयालार रवि : पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से टालमटोल वाले उत्तर सुनना हमारे लिए आम बात हो गई है। अन्तर केवल इतना है कि पहले श्री शाहनवाज़ खां मंत्री थे और अब श्री डी० के० बरुआ मंत्री हैं।

मेरा प्रश्न स्पष्ट है। क्या यह सच है कि कर्मचारी संघ ने प्रबन्धकों को यह लिखकर भेजा था कि वे काम करने के लिए तैयार हैं और प्रबन्धक वर्ग उनके लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए। क्या प्रबन्धक वर्ग ने कर्मचारियों को यह लिखकर भेजा था कि उनके लिए बसें चलाना सम्भव नहीं है। जब कर्मचारी काम करने के लिए तैयार थे तो उनके वेतन में कटौती करने का क्या औचित्य था ?

श्री देवकान्त बरुआ : केरल की स्थिति के बारे में माननीय सदस्य मुझसे अधिक जानते हैं। मैं लेकिन 'बंद' के अवसर पर प्रबन्धकों ने सोचा कि गतियों में बसें चलाना शायद सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि 'बंद' के अवसर पर कोई अप्रियजनक घटना हो सकती थी जिसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति की हानि हो सकती थी।

श्री वयालार रवि : प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को यह सूचित क्यों नहीं किया कि वे बसें नहीं चला सकते ? जब कर्मचारी काम पर आने के इच्छुक थे बशर्ते कि उन्हें बसें उपलब्ध कराई जाएं, तो उनके वेतन में कटौती करने के क्या कारण थे ? इसमें कर्मचारी संघ की कोई गलती नहीं थी।

श्री देवकांत बरुआ : मैंने अभी-अभी बताया कि अप्रियजनक घटना की आशंका से कम्पनी की बसें 'बंद' के दिन नहीं चलाई गईं और कर्मचारी संघ को 'बंद' से पूर्व ही सलाह दे दी गई थी। सलाह का अर्थ है 'सूचना'।

श्री वयालार रवि : 'सलाह' के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। क्या मंत्री महोदय ने लिख कर भेजा था ?

श्री देवकान्त बरुआ : 'सलाह' का अर्थ है 'सूचना'।

श्री वयालार रवि : क्या मंत्री महोदय ने सूचना-पट पर लिखवाया था ? सूचित करने का यही एक तरीका है।

श्री देवकान्त बरुआ : मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि प्रबन्धक वर्ग मजदूर संघ को किस प्रकार सूचित करता है। निश्चय ही वे कोई न कोई प्रक्रिया अपनाते होंगे। मैं पता लगाकर माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दुंगा।

श्री वयालार रवि : इस आधार पर, क्या मंत्री महोदय प्रबन्धक वर्ग को मामले पर पुनः विचार करने के लिए कहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

श्री वयालार रवि : मेरा प्रश्न स्पष्ट है। क्या मंत्री महोदय प्रबन्धक वर्ग को मामले पर पुनः विचार करने के लिये कहेंगे ?

श्री देवकान्त बरुआ : मेरे विचार में यह अच्छा सुझाव है। श्रमिकों की समस्याएं श्रमिक संघ और प्रबन्धक वर्ग के बीच बातचीत के माध्यम से हल हो सकती हैं।

श्री रामचन्द्रन कड़नापल्ली : क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्मचारी निर्दोष थे, वेतन कटौती को समाप्त करेगी ?

श्री देवकान्त बरुआ : जैसा कि मैंने कहा कि माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव अच्छा है। कर्मचारी संघ और प्रबन्धक वर्ग के बीच बातचीत होनी चाहिए।

Ticketless Travelling between Alwar and Delhi due to Late Running of Trains

***696. Shri Laljit Bhai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether certain persons travel without tickets daily between Alwar and Delhi stations because most of the trains operating between these stations run late;

(b) whether such persons harass in many ways the male and female passengers in the trains and commit thefts and the police do not provide protection in any way to the persons so harassed; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard?

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी नहीं । फिर भी, इस खंड में बिना टिकट यात्रा के मामलों की रिपोर्टें मिली हैं लेकिन उनका कोई संबंध गाड़ियों के देर से चलने से नहीं है ।

(ख) ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है ।

(ग) (i) **गाड़ियों का समय पालन सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपाय**:—ऐसे सभी मामलों में, जिनमें गाड़ियों का अवरोध बचाया जा सकता था, यदि रेल कर्मचारी दोषी पाये जाते हैं, तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और गाड़ियों के संचलन में सुधार करने के लिए दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है ।

(ii) **बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए की गयी कार्रवाई** :—ऐसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध प्रभावशाली प्रचार के अलावा बिना टिकट यात्रा समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) 10 जून, 1969 से बिना टिकट यात्रा के लिए दिया जाने वाले दण्डों में वृद्धि कर दी गयी है । बिना टिकट यात्रा के लिए न्युनतम जुर्माना 0.50 पैसे से बढ़ा कर 10 रुपये कर दिया गया है ।

(2) नियमित और अचानक जांच के अलावा, भेद्य खंडों में टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस और मेजिस्ट्रेट की सहायता से बड़े पैमाने पर सामुहिक जांच की जाती है ।

(3) राज्य सरकारों के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं ।

(4) कर्मचारियों द्वारा इस काम में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए, गलती करने वाले कर्मचारियों को दण्ड और अनुकरणीय सेवा करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देने की प्रणाली अपनायी गयी है ।

(iii) **यात्रियों की जान और माल की रक्षा करने के लिये किये गये उपाय** :—

(1) रात में चलने वाली सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में रक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस साथ चलती है ।

(2) अपराधियों और कुख्यात बदमाशों पर निगरानी रखने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस की नियमित गश्त की व्यवस्था की जाती है ।

(3) सूचना इकट्ठी करने और अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ।

(4) राज्य/केन्द्र सरकार (रेलों सहित) के वरिष्ठ अधिकारियों का एक अध्ययन दल बनाया गया है जो स्थिति की पूरी तरह जांच करेंगा और रेलों पर अपराधों की समस्या प्रभावपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सुझाव देगा ।

3—14 L S S/74

(5) यार्डों और स्टेशन प्लेटफार्मों पर ड्यूटी करने वाले रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को इस आशय की कड़ी हिदायतें जारी की गयी हैं कि वे रेल सम्पत्ति की रक्षा करें, बुलाये जाने पर तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच जायें और पीड़ित व्यक्तियों की हर सम्भव सहायता करें।

Shri Lalji Bhai: Trains are running late, passengers are harassed and incidents of Goondaism is on an increase and no stringent action is taken against bad elements because police and Railway Ministry have also their hand in it. In this regard I had asked a question but an evasive reply was given. About four months ago 4 lady passengers were raped in a train operating between Delhi and Alwar by bad characters. May I know what measures Government are contemplating to prevent such crimes?

श्री समर गुह : माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके प्रश्न को बदल दिया गया है। माननीय सदस्य को सूचना दिए बिना इसे कैसे बदला जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जानकारी नहीं कि प्रश्न बदल दिया गया है। मैं इस मामले की छान-बीन करूंगा।

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Question has been fully replied. Unless affected party lodges a complaint, how can we get information. But adequate arrangements are made for the safety of passengers travelling in night passenger trains.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ। अब अल्प सूचना प्रश्न।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya: Mr. Deputy Speaker, Sir, women have been publicly raped and hon. Member had asked question on confirmed information. Evasive reply should not be given.

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विशिष्ट मामले के बारे में मंत्री महोदय को लिखिए और मंत्री महोदय इस पर छान-बीन करेंगे। आपने सदन में यह बात कही है और मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि वह इस मामले में क्या कर सकते हैं। माननीय सदस्य कुछ बातों को क्यों नहीं समझते ? ये सब बातें सदन के सामने कही गई हैं। उनका अपना महत्व है। लेकिन आप जोर जोर से बोलकर इसमें कुछ वढ़ा नहीं सकते और न ही अपने विचार थोप सकते हैं।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

नेताजी के सम्बन्ध में बनाये गये वृत्त चित्र का विस्तार वाला भाग (लांगर वर्जन) दिखाये जाने के बारे में मंत्री द्वारा मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन को लिखे पत्र का पाठ

अ. सू. प्र. 8. श्री समर गुह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नेताजी के सम्बन्ध में आशीष मुखर्जी द्वारा निर्मित वृत्त चित्र का विस्तार वाला भाग दिखाने के लिए मोशन पिक्चर्स की विभिन्न एसोसिएशनों को पत्र लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का पाठ क्या है ; और

(ग) उसके सम्बन्ध में अब तक क्या प्रतिक्रिया मिली है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) साउथ इंडियन फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मद्रास ने यह कहा है कि उन्होंने अपने से सम्बद्ध संगठनों से अनुरोध किया हैं कि वे नेताजी पर चार रिलों वाली फिल्म को दिखाएं। अन्यों से उत्तर अपेक्षित है।

सूचना और प्रसरण मन्त्री द्वारा चलचित्र प्रदर्शकों की एसोशिएनों के सचिवों को जारी की गई अपील संख्या 38/3/69-एफ० पी० तारीख 19 मार्च, 1947 की प्रति।

प्रिय मित्र,

श्री आशिष मुखर्जी, जो एक उद्यमी प्रोड्यूसर हैं, ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस पर 1140 मीटर (3800 फुट) लम्बी तथा 38 मिनट की चार रील की एक डाकुमेन्ट्री फिल्म बनाई है। इसको केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड ने मुख्य रूप से शैक्षणिक फिल्म के रूप में प्रमाणीकृत किया है।

यह नेताजी के जीवन तथा कार्य पर प्रथम फिल्म है जिसके द्वारा लोग हमारे महान देशभक्त नेताजी की गाथा के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को जान सकें। मुझे विश्वास है कि यह फिल्म उन युवकों को विशेष रूप से पसन्द आयेगी जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त पैदा हुए हैं। मेरा मंत्रालय राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को यह लिख रहा है कि वे प्रदर्शक को उस दिन स्वीकृत फिल्म को दिखाने से छूट दे दे जिस दिन वह इस डाकुमेन्ट्री को पूर्ण रूप से दिखायें। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपना सहयोग दें और अपनो एसोसिएशन के सिनेमा प्रदर्शकों से यह अनुरोध करें कि वे नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में इस डाकुमेन्ट्री फिल्म को दिखाएं।

धन्यवाद।

आपका
ह०
(इन्द्र कुमार गुजराल)

श्री समर गुह : मुझे विश्वास है कि सम्पूर्ण देश नेताजी के जीवन और कार्य की फिल्म बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहल की सराहना करेगा और मुझे आशा है कि फिल्म निर्माता भी नेताजी की गाथा के बारे में जान सकेंगे।

हालांकि चलचित्र प्रदर्शकों की एसोसिएशनों के सचिवों को पत्र लिखा जा चुका है और यह एक अच्छी बात है फिर भी अनजाने में एक त्रुटि रह गई है। पत्र में कहा गया है, "नेता जी की स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में इस डाकुमेन्ट्री फिल्म को दिखाएं . . .", 'स्मृति' शब्द अनजाने में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि नेताजी जांच आयोग नेताजी के गायब होने के बारे में अभी भी जांच कर रहा है। दूसरी ओर मुझे इस बात में रती सा भी शक नहीं है कि नेताजी विमान-दुर्घटना में नहीं मरे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप जीवित व्यक्ति को याद नहीं करते ? मैं आपको याद कर सकता हूं। आपके जीते जी मैं आपकी स्मृति में कुछ कर सकता हूं।

श्री समर गुह : 'स्मृति' शब्द का अपना एक अर्थ है और इसलिए मेरे विचार में इसे ठीक कर लिया जाएगा जैसा कि मंत्री महोदय ने परामर्शदात्री समिति में आश्वासन दिया था। अगले पत्र में इसे ठीक कर देना चाहिए।

क्या यह सच है कि आजाद हिन्द सरकार द्वारा नेताजी तथा आजाद हिन्द फौज की गतिविधियों के बारे में बनाए गए 4 रीलों के वृत्त चित्र को सरदार पटेल ने सारे देश में दिखाया था और लगभग 3 लाख रुपये इकट्ठे किए गए थे लेकिन अब वह महत्वपूर्ण वृत्तचित्र गुम है ? क्या इस गुम ऐतिहासिक वृत्तचित्र को ढूंढने के लिए खुफिया विभाग तक की सेवाएं प्राप्त करने के लिए विषेश प्रयत्न किए जाएंगे ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरे, क्या सरकार पश्चिम जर्मनी, पूर्व जर्मनी, जापान, बर्मा, फिलपाइन के अभिलेखागारों में नेताजी के जीवन और आजाद हिन्द फौज की गतिविधियों के बारे में कुछ वृत्तचित्रों की विद्यमानता का पता लगाएगी और विदेश मंत्रालय की सहायता से उन सरकारों को यह लिखेगी कि वे इस बात का पता लगाएं कि क्या कोई कागजात अब भी वहाँ हैं ? आशीष मुखर्जी ने यह सूचना दी है कि वह अमरीका गए थे और वहाँ कुछ वृत्तचित्र भी थे और आज़ाद हिन्द फौज और नेताजी के बारे में कुछ फिल्में भी थीं। क्या मंत्री महोदय आजाद हिन्द फौज से सम्बन्धित कागज़ातों को प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय की सेवाओं तथा विदेशी स्रोतों का भी उपयोग करने के लिये प्रयत्न करेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० क० गुजराल) : माननीय सदस्य यह जानते हैं कि इस विशेष संदर्भ में वह और मंत्रालय सहयोगपूर्वक कार्य कर रहे हैं और माननीय सदस्य ने जो भी सुझाव भेजे हैं, उन पर हमेशा गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया है क्योंकि हमें देश के सभी लोगों की तरह माननीय सदस्य की नेता जी के प्रति निष्ठा की भावना से अवगत है। माननीय सदस्य निश्चित रूप से अग्रणी है और इसलिए माननीय सदस्य जो सुझाव देते रहे है, हमने हमेशा तत्परता से उनका अनुकरण किया है। इस सुझाव पर भी पहले की तरह विचार किया जाएगा।

श्री समर गुह : पत्र के अनुसार केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को मुख्य रूप से शैक्षणिक फिल्म के रूप में प्रमाणीकृत किया है। इस सम्बन्ध में मैं अपना तुच्छ सुझाव देना चाहता हूं। क्या सभी राज्य सरकारों को यह लिखकर भेजना सम्भव होगा कि वे न केवल नेताजी की जीवन गाथा और उनके कार्यों-बल्कि विशेषकर स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास की फिल्म सभी शिक्षा संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को दिखाए और क्या इसके लिए प्रबन्ध किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिएं।

श्री आई० के० गुजराल : मैंने राज्य सरकारों को पहले ही लिखकर भेजा है कि चूंकि यह मुख्य रूप से शैक्षणिक फिल्म है इसीलिए इसे मनोरंजन कर से मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है। मैं विभिन्न सूचना मंत्रियों और शिक्षा मंत्रालयों को यह लिखकर भेजूंगा कि वे विभिन्न शिक्षा संस्थानों को यह फिल्म दिखाएं क्योंकि यह फिल्म स्वभावतः उत्साहवर्धक होगी।

श्री वसंत साठे : मैंने नागपुर में यह फिल्म देखी थी और यह मुझे न केवल शिक्षाप्रद बल्कि उत्साहवर्धक भी लगी। क्या इस फिल्म की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अन्य फिल्मों की भांति इस फिल्म के लिए फिल्म निर्माता आशीष मुखर्जी को उपयुक्त पुरस्कार देगी ?

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य ने सम्भवतः श्री मुकर्जी द्वारा निर्मित फिल्म का लघु संस्करण देखा है जिसे सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इसका विस्तृत संस्करण भी है।

श्री वसंत साठे : मैंने फिल्म का विस्तृत संस्करण भी देखा है और यह फिल्म लगभग 45 मिनट चलती है।

श्री आई० के० गुजराल : यह एक अच्छी फिल्म है। हमारे देश में पुरस्कार समितियों जैसी संस्थाएं पुरस्कार देती हैं। यदि आशीष मुखजी अपनी फिल्म पुरस्कार के लिए पुरस्कार समिति को भेजें तो पुरस्कार समिति चाहे तो अपना निर्णय दे सकती है। पुरस्कारों के बारे में निर्णय करना सरकार का काम नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने वृत्त चित्र देखा है—लघु अथवा विस्तृत संस्करण के बारे में मैं नहीं जानता। क्या वृत्त चित्र तैयार करते समय नेताजी के निकट सहयोगियों से परामर्श नहीं लिया गया था ? क्या इन लोगों का परामर्श लेकर इस फिल्म में कुछ जोड़ा जाएगा ? क्या यह वृत्त चित्र विदेशों में भी भेजा जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का किस प्रकार मुकाबला किया।

श्री आई० के गुजराल : जहाँ तक परामर्श लेने का सम्बन्ध है, मुझे पूरे तथ्यों का पता नहीं है। मुझे तो केवल इतनी जानकारी है कि जब आशोष मुखर्जी ने फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की थी तो उन्होंने श्री समर गुह से सम्पर्क स्थापित किए रखा था।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह नेताजी के प्रशंसक है। उनके निकट सहयोगियों के बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं ? हम अनुयायी हैं। मैं उनका अनुयायी होने का कभी दावा नहीं कर सकता। . . . (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप श्री समर गुह को भड़का रहे हैं।

श्री समर गुह : मैंने डा० आर० सी० मुजूमदार तथा अन्य सहयोगियों से परामर्श लेने का प्रयत्न किया था।

श्री आई० के० गुजराल : सामान्य तौर पर हम विदेशों में स्थित अपने मिशनों में वृत्त चित्र भेजते है। और हम इसको भी शामिल करने का प्रयत्न करेंगे। मैं अन्य देश की दूरदर्शन संस्थाओं से पेशकश करने की सम्भावना का पता लगाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री नरेंद्र कुमार सालवे : मैं आपके माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि क्या वह संसद सदस्यों से पैसे लेकर उन्हें यह फिल्म दिखाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सदन से बाहर होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। यह फिल्म तीन बार दिखाई जा चुकी है। यदि वह देखना चाहते हैं तो मैं इसको चौथी बार दिखाने की व्यवस्था कर सकता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर : फिल्म पुरस्कार के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है कि फिल्म के निर्माता श्री आशोष मुखर्जी को विहित फार्म में आवेदन करना होगा। क्योंकि हमारे देश में पुरस्कार संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं। क्या सरकार के पास पुरस्कार या श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र देने का कोई अन्य साधन भी है ताकि फिल्म निर्माता को सम्मान दिया जा सके क्योंकि कई बार अच्छा निर्माता ऐसे पुरस्कार के लिए आवेदन-कर्ता नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : जनता द्वारा की गई प्रशंसा ही एक अच्छा पुरस्कार है।

श्री आई० के० गजराल : फिल्म का प्रारम्भ सरकार द्वारा किया गया था और श्री मुकर्जी को यह काम सौंपा गया था। दूसरे कोई भी अच्छा निर्माता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपना नाम भेजने में नहीं हिचकिचाता जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार उपलब्ध हैं।

Shri Jagannathrao Joshi : May I know why not such inspiring film is shown to us while several films are shown to us? The hon. Minister has stated that this film has been shown thrice. We have not seen this film. Will the hon. Minister make arrangement to show the film once again.

Shri I. K. Gujral : The film has been shown thrice. We will show it once again.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Consumption of Power for Agricultural, Industrial and Domestic purposes

***691. Shri B. S. Chowhan:**

Shri K. Lakappa:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the percentage of power being consumed for agricultural, industrial and domestic purposes, separately, in the States which are facing power shortage; and

(b) whether keeping in view the scarcity and the rising prices, Government propose to suggest to the State Governments to utilise 85 per cent of total power available with them for agricultural and industrial purposes?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant): (a) The required information is given in the Annexure.

(b) To secure utilisation of the available power which is in short supply in a manner most beneficial to the national economy, broad guidelines to govern the priorities in allocation of power to various categories of consumers have been indicated to the States. While the energy consumption in the country as a whole for industry, agriculture and essential services like traction and water supply has been of the order of 85% in 1972-73, no suggestion has been made to the States to utilise any specific percentage of the available power for agricultural, industrial or other purposes.

STATEMENT

The percentage of power being consumed for agricultural, industrial and domestic purposes in the States facing power shortage

Sl. No.	Name of the State/ Union Territory	Percentage to total sales		
		Agricultural	Industrial	Domestic
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	21.9	54.5	8.5
2.	Assam	0.4	49.3	11.9
3.	Bihar	2.7	74.1	3.5
4.	Haryana	40.2	46.8	6.1
5.	Jammu and Kashmir	5.8	34.9	37.6
6.	Karnataka	6.7	77.1	8.2
7.	Manipur	Nil	14.4	83.3
8.	Nagaland	Nil	8.6	51.7
9.	Punjab	26.8	59.9	7.7
10.	Tamil Nadu	27.7	54.1	6.9
11.	Tripura	2.8	20.0	54.0
12.	Uttar Pradesh	17.0	63.2	9.2
13.	West Bengal	0.4	69.3	12.9

अहमदपुर कटवा नैरोगज लाइन चलाने वाली मार्टिन बर्न की एक कम्पनी मैकलियोड में सरकार के शेयर

***697. श्री गदाधर साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के अहमदपुर-कटवा (नैरो-गेज) सेक्शन को चलाने वाली और उसका प्रबन्ध करने वाली मेसर्ज मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड की एक कंपनी मेकलियोड में सरकार के कितने प्रतिशत शेयर हैं ; और

(ख) क्या इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए इसके नियंत्रण के और अधिक अधिकार प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) 1-7-1967 से पहले अहमदपुर-कटवा रेलवे (जो एक छोटी लाईन है) अहमदपुर-कटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड के अधिकार में थी और उसी कम्पनी द्वारा चलायी जा रही थी। 1 जुलाई, 1967 से इस रेलवे लाइन के संचालन का काम रेल मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है और इस कम्पनी के लगभग 11.6 प्रतिशत शेयर रेल मंत्रालय के पास है।

(ख) चूंकि रेल मंत्रालय ने इस रेलवे का संचालन अपने हाथ में लेकर पहले ही इसका नियंत्रण सम्हाल लिया है, अतः इस समय कम्पनी के और शेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती।

Medium irrigation schemes for M.P. in Fifth Plan

***698. Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of long term and medium term irrigation schemes in Madhya Pradesh in respect of which work is already in progress; and

(b) the funds provided for these schemes as also for the new schemes to be undertaken?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) There are five major and eight medium approved schemes in Madhya Pradesh in respect of which work is in progress.

(b) An outlay of Rs. 22.94 crores has been provided for these schemes. In addition Rs. 11.40 crores has been provided for schemes which are yet to be approved.

धुवरन बिजली घर की तेल की सप्लाई में कटौती

***699. श्री डी० डी० देसाई** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने धुवरन बिजली घर को अवशिष्ट इन्धन तेल की सप्लाई में कटौती कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसकी सप्लाई में की गई कटौती को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयाली शोधनशाला से आर एफ ओ की सप्लाई के अतिरिक्त धुवारन बिजली घर को अप्रैल तथा मई, 1974 के दौरान 25,000 मीटरी टन अतिरिक्त भट्टी का तेल ले जाये जाने का निर्णय किया गया है ।

आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी की पन-बिजली क्षमता

***700. श्री धरनीधर दास :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी से कितनी पन-बिजली बनाई जा सकती है और अब तक क्षमता के कितने प्रतिशत बिजली बनाई जाती है ;

(ख) क्या सरकार ब्रह्मपुत्र नदी को कुछ सहायक नदियों पर बान्ध बनाकर पन-बिजली पैदा करने के लिए कोई बड़ी योजना बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और इस पर कितना व्यय आएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों को कुल जल विद्युत शक्यता 6.55 मिलियन किलोवाट संतत है । इस कुल शक्यता में से असम में लगभग 0.21 मिलियन किलोवाट शक्यता होने का मूल्यांकन किया गया है । अभी तक असम में इस शक्यता के किसी अंश का समुपयोजन नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) असम राज्य बिजली बोर्ड ब्रह्मपुत्र बेसिन में असम/मेघालय में निम्नलिखित जल-विद्युत परियोजनाओं का अनुसंधान कर रहा है :—

(1) 180 मैगावाट को सम्भावित प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ लोअर उमियम एवं उमखेम स्कीमें जिनकी अनुमानित लागत लगभग 45 करोड़ रुपये हैं ।

(2) तकरीबन 360 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ कोपिलो जल विद्युत परियोजना जिसकी अनुमानित लागत लगभग 75 करोड़ रुपये है ।

अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी भावी जल विद्युत परियोजनाओं के स्थलों के क्षेत्रीय अन्वेषणों को भी हाथ में लेने का प्रस्ताव है ।

जल संसाधनों का अनुमान लगाया जाना

***701. श्री पी० गंगादेव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपलब्ध जल संसाधनों की मात्रा का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या विभिन्न एजेंन्सियों द्वारा किए गए अध्ययन से काफी जानकारी उपलब्ध हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार देश के कुल सतही जल संसाधन औसतन 1673 हजार मिलियन घन मिटर से 1881 हजार मिलियन घन मिटर तथा कुल भूगत जल संसाधन 424 हजार मिलियन घन मीटर हैं । सिंचाई आयोग (1972) द्वारा आंके गए समुपयोज्य सतही और भूगत जल संसाधन 870 हजार मिलियन घन मीटर हैं ।

उड़ीसा की धनेई सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

***702. श्री डी० के० पंडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जिला गंजम स्थित धनेई सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा रहा है, और

(ग) कब तक काम शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने अभी तक धनेई सिंचाई स्कीम के चरण-दो की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को प्रस्तुत नहीं की है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना को राज्य की पांचवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बिछाने का लक्ष्य

***703. श्री वनमाली बाबू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, नई रेलवे लाइनें बिछाने के लक्ष्य को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) रेलवे का विकास किसी राज्य अथवा क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि समग्र राष्ट्रीय हित के आधार पर किया जाता है। इसलिए नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लक्ष्य राज्य अथवा क्षेत्र के आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते। फिर भी, जुलाई, 1973 में उड़ीसा राज्य में चौथी पांचवीं योजना के दौरान 10.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 84.31 किलोमीटर लम्बी कटक-पारादीप रेलवे लाइन के निर्माण का काम पूरा हो गया है।

उड़ीसा के पिछड़ेपन को देखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 176 किलोमीटर लम्बी बांसपानी–जाखापुरा बड़ी लाइन का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव है और इस लाइन के निर्माण के लिए 1974–75 के रेलवे बजट में व्यवस्था भी कर दी गई है।

इसके अलावा, 16.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उड़ीसा राज्य में 135.65 किलोमीटर लम्बी तालचेर-विमलागढ़ बड़ी लाइन बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

टाटा बन्धुओं द्वारा ट्राम्बे तापीय बिजलीघर में अतिरिक्त जनरेटिंग सेट लगाया जाना

***704. श्री के० मालन्ना** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धुओं का विचार ट्राम्बे तापीय बिजलीघर में 87.41 लाख रुपये के मूल्य का 50 मैगावाट क्षमता का अतिरिक्त जनरेटिंग सेट लगाने का हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) टाटा ने 87-41 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अपने ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र में 500 मैगावाट की एक यनिट के प्रतिष्ठापन के लिए एक सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है । सम्भाव्यता रिपोर्ट में उल्लेख किया

गया है कि यह अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पश्चिमी महाराष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इसमें बंगाल/बिहार क्षेत्रों से समुद्र-बोर्न कोयले का समुपयोजन और कन्डेन्सर कूलिंग के लिए समुद्री जल का प्रयोग करना परिकल्पित है।

यह दावा किया जाता है कि इस प्रस्ताव से अन्य भावी परियोजनाओं के प्रयोग के लिए देश में निर्मित होने वाले 500 मैगावाट के सैटों के प्रतिष्ठापन, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी।

इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा उच्च न्यायालय में फाइल की गई अपीलों और फाइल किए गए मामलों की संख्या

*705. **श्री गजाधर माझी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा उच्च न्यायालय में पिछले वर्ष के दौरान फाइल की गई अपीलों और फाइल किए गए मामलों की संख्या क्या थी ; और

(ख) उच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष में औसतन कितने मामले निपटाए गए ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) उड़ीसा उच्च न्यायालय में 1973 के दौरान फाइल किए गए मामलों की कुल संख्या 4786 थी, जिसमें से 2282 अपीलें थीं।

(ख) उच्च न्यायालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की एक वर्ष में औसत संख्या 4890 रही।

रेलों में विद्युतीकरण धीरे-धीरे करने के बारे में सरकार का निर्णय

*707. **श्री राम भगत पासवान :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलों में विद्युतीकरण धीरे धीरे करने और अधिक रेल इंजनों को प्राप्त करने का निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, नहीं। बल्कि और अधिक बिजली रेल इंजन प्राप्त करने का विचार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कास्टिक सोडा उद्योग पर ऊर्जा संकट का प्रभाव

*708. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संकट, भट्टी तेल की कमी और कोयले की अनियमित सप्लाई का कास्टिक सोडा उद्योग पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या देश में सभी एकक ठोस और 'फ्लेक' जैसी किस्मे बनाने के लिए गलाने हेत ईन्धन तेल का प्रयोग करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कास्टिक सोडे का उत्पादन बढाने के लिए भट्टी तेल की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ): (क) जी, हां । कास्टिक सोड़ा उद्योग में क्षमता के उपयोग पर कुप्रभाव पड़ा है यद्यपि 1972 के उत्पादन की अपक्षा 1973 वर्ष में कुल उत्पादन में लगभग 20,000 मीटरी टन की वृद्धि हुई है ।

(ख) उत्पादन में लगे कास्टिक सोडा के 29 एककों में से केवल 12 एकक ठोस और फ्लेक किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं । और वे भट्टी के तेल का प्रयोग कर रहे हैं ।

(ग) भट्टी के तेल की कुल उपलब्धता में से उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रह हैं ।

Irrigation of land in Madhya Pradesh by Chambal Hydro-Electric scheme

6784. Shrimati V. R. Scindia: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the acreage of land which was proposed to be irrigated in Morena and Bhind districts of Madhya Pradesh by Chambal Hydro-electric Scheme;

(b) the acreage of land that is actually irrigated at present; and

(c) the reasons for short supply of water and the efforts being made to make up this shortage?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The Chambal Project envisaged the irrigation of seven lakh acres of land in Morena and Bhind Districts of Madhya Pradesh.

(b) A total irrigation of 4.05 lakh acres has been actually achieved.

(c) The adoption of the high yielding varieties of wheat, which consume higher quantities of water has led to a reduction in the area which can actually be irrigated. The un-utilised potential available is to the extent of about 1 lakh acres during Kharif. This potential is expected to be utilised as a result of the ayacut development programme taken up by the State Government and as a result of which items like field bunding would be completed and other facilities made available to the farmers to enable them to utilise the available waters.

Saving of Agricultural Land from wastage in M.P.

6785. Shrimati V. R. Scindia: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether thousands of acres of agricultural land is becoming waste every year due to stagnation of water flowing out from the canals of Chambal Project in Morena and Bhind Districts of Madhya Pradesh, and

(b) if so, the scheme of Government for saving the said useful agricultural land from becoming waste?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) The Government of Madhya Pradesh have reported that 49,000 acres of agricultural land, where the water table is upto 5 ft. below ground level, has been affected so far from the Chambal canals. The State Government have intimated that 54 Pilot drainage schemes and seepage schemes costing Rs. 44.88 lakhs were started by the State Government to reclaim 40,000 acres. Out of these 17,600 acres have already been reclaimed. It has also been reported that total cost of reclaiming the whole area will be Rs. 898.75 lakhs and this is expected to be completed in the next five years.

A Central Sector Soil and Water Management Pilot Project in the Chambal Command has been set up by the Ministry of Agriculture. That Ministry has also proposals to implement an integrated command area development programme in the Fifth Plan.

Shortage of wax for manufacturing candles in Bastar Region

6786. Shri Lambodar Baliyar: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether wax is not available in Bastar region of Madhya Pradesh for manufacturing candles;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which the position is likely to improve?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c) This Ministry allocates paraffin wax to the States every year on the basis of its estimated production in a particular year and the expected requirement of each State. The equitable distribution of paraffin wax amongst the consumers within the various regions of the State is the responsibility of the "competent authority" of each State under the provisions of the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Order, 1972. The subject matter of the question, therefore, pertains to the Government of Madhya Pradesh. The position is being ascertained from that Government and will be laid on the Table of the House.

मूल्यों के अनुमोदन के लिए अनिर्णित पड़े आवेदन पत्र

6787. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य अनुमोदन के लिए अनिर्णीत पड़े अधिकांश आवेदन पत्र भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा छोटे छोटे पैमाने पर भेषज निर्माता एककों के लिए नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने 1971-72 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था, यदि हां, तो औषध मूल्य नियंत्रण आदेश सम्बन्धी सिफारिशों तथा अन्य सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का इस आशय की अधिसूचना जारी करने का विचार है कि यदि आवेदन पत्र दिये जाने के 45 दिन तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो लघु उद्योग/भारतीय फर्म यह मान ले कि मूल्यों को अनुमोदित कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आवेदन पत्रों का लगभग 60% आवेदन पत्र लघु क्षेत्र उद्योग से सम्बन्धित मूल्य अनुमोदन/मूल्य संशोधन हेतु है ।

(ख) लघु उद्योग अध्ययन दल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में 14 अप्रैल, 1972 को लोक सभा में ता० प्रश्न 417 के उत्तर में बताया गया है ।

(ग) इस समय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) वे यूनिट जिनकी वार्षिक बिक्री 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को पहले ही कुछ शर्तों पर डी० पी० पी० ओ० 1970 के अन्तर्गत अपने सूत्रयोगों के मूल्यों के बारे में सरकार की अनुमति लेने सम्बन्धी आवश्यकताओं से छूट दे रखी है ।

कुछ औषधियों के लागत-मूल्य अध्ययन सम्बन्धी औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों का प्रतिवेदन

6788. **श्री के० एस० चावडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों ने पिकोलिन्स पिरिडीन तथा इसके आधारों मेथेनोल फार्मेल-डिहाइड तथा हैक्सा-भीन के लागत मूल्य अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसको सभा पटल पर रखेगी ;

(ग) उक्त औषधियों के निर्माण के लिए विदेशी प्रभुत्व वाली कितनी फर्मों को लाइसेंस मिला हुआ है उनके पुंजी निवेश लाइसेंस प्राप्त क्षमता किया गया वास्तविक उत्पादन आयातित मदों तथा लाभाशों के स्वदेश भेजने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन मदों के निर्माण के लिए विदेशी फर्मों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो एक सरकारी संस्था है तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अनुरोध पर इसके द्वारा तैयार किये गये लागत मूल्य अध्ययन सरकार के लिए सलाह के रूप में होते हैं । और इसकी रिपोर्ट गोपनीय रखी जाती है । अतः रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

बेकार पडे रेल-इंजन

6789. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंजनों के आवश्यक फालतू पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण कुछ रेल-इंजन बेकार पड़े हैं ;

(ख) क्या बजट के पेश होने के बाद इस कारण रेलवे की आय में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) आवश्यक आयातित पुर्जों की कमी के कारण कुछ रेल-इंजन बेकार पड़े हैं । लेकिन ये पुर्जे विदेशी मुद्रा की कमी के कारण नहीं बल्कि बाहर से जहाजों पर माल की लदान में विलम्ब होने के कारण रुके हुए थे अब ये पुर्जे पहुंचने शुरू हो गये हैं और रेल-इंजनों का उपयोग फिर से किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । लेकिन माल यातायात से होने वाली आमदनी में कमी हुई है जिसका कारण यह है कि रुक रुक कर होने वाले कर्मचारी आन्दोलन और अशान्ति के कारण प्रत्याशा से कम यातायात ढोया गया ।

पांचवीं योजना में बिजली उत्पादन के लिए नियत लक्ष्य

6790. **श्री धामनकर :**

श्री महेंद्र सिंह गिल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में बिजली उत्पादन के नियत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार प्रबंध परियोजना निर्माण, सामग्री व्यवस्था तथा विद्युत् परियोजनाओं के वित्त-पोषण संबंधी प्रक्रिया में परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यवाही कब की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में परिकल्पित विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) पिछली कमियों को दूर करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से विद्युत् सप्लाई उद्योग की पुनर्संरचना करना ।

(2) पद्धतियों एवं प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना ताकि सभी अपेक्षित निवेश, जिसमें धन-राशियां भी शामिल है, को समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके ।

(3) प्रभावी बहुमुखी मानिटेरिंग प्रणालियों का प्रतिष्ठापन करना ताकि निष्पादन एवं सप्लाई पर निगरानी रखी जा सके और जहां आवश्यक हो, ठीक समय पर दोष निवारण की व्यवस्था की जा सके ।

Running of trains in Madhya Pradesh according to Time Schedule

6791. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether trains in Madhya Pradesh, particularly Amritsar-Dadar and Dadar-Amritsar Express train, are running according to time schedule ; and

(b) if so, the action being taken by Government to run them according to time schedule?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The punctuality of trains, including 57/58 Dadar-Amritsar Express, has been affected over all the Railways during the last few months due to general unsettled conditions on account of various staff and public agitations, bandhs etc. and in some cases due to heavy alarm chain pulling.

(b) Besides seeking assistance of State Government to curb incidence of alarm chain pulling and improve law and order, such factors that are found to be of avoidable nature are investigated and taken up to affect improvement in running of trains.

Railway lines in Chhattisgarh region of Madhya Pradesh

6792. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the areas in Madhya Pradesh where new railway lines are proposed to be constructed during the Fifth Five Year Plan period;

(b) whether Government propose to construct a new railway line in Chhattisgarh region (Madhya Pradesh); and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Proposals for new lines to be taken up during the 5th Five Year Plan period have not yet been finalised.

(b) and (c) A survey has been taken up for construction of a line from Dhalli Rajahra to Jagdalpur/Dantewara. A decision on the construction of this line will be taken after the survey is completed.

Electrification of villages in Madhya Pradesh during 1973-74

6793. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the names of the villages in each District of Madhya Pradesh electrified in 1973-74?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): During the year 1973-74 upto 23-2-1974, 526 villages were electrified in Madhya Pradesh. Names of the villages electrified in each District are available for the period from 1-4-1973 to 30-9-1973. These are given in the Statement enclosed. [*Placed in Library. See No. L.T.*-6712/74.]

Non-supply of foodgrains to Government of Madhya Pradesh

6794. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether due to non-availability of railway wagons from the Northern Zone foodgrains are not being supplied to the Government of Madhya Pradesh regularly;

(b) whether Madhya Pradesh Government have requested the Central Government to make an enquiry into this matter;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) the number of wagons allotted to the State during the last four months to carry foodgrains?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) During the months from December 1973 to March 1974, there was no programme for movement of foodgrains from the Northern Zone to Madhya Pradesh. There were, however, 28 piecemeal demands on Government account during this period and they were met in full.

वर्ष 1974-75 में केरलमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वार योजनओं की क्रियान्विति

6795. **श्री वयालर रवि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से केरल राज्य में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी ; और

(ख) इन योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है तथा इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाता है और उनके राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यन्वित किया जाता है। राज्य बिजली बोर्डों की व्यवहार्य स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा योगात्मक ऋण व्यवस्था की जाती है। 31-3-1974 तक, निगम ने केरल राज्य बिजली बोर्ड को 16 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें 712.571 लाख रुपये की ऋण सहायता शामिल है। स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये स्कीमें 3-5 वर्षों की अवधि में पूर्ण होने के लिए अनुसूचित हैं और 1974-75 वर्ष के दौरान इनका कार्यान्वियन जारी रहेगा।

1974-75 के दौरान केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित की जाने वाली स्कीमों का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। सहायता केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित स्कीमों की संख्या और निर्धारित मानदण्डों एवं निर्देशनों के अनुसार निगम द्वारा स्वीकृति पर निर्भर करेगी। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6713/74]**

वर्ष 1973-74 में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूल की गई राशि

6796. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में प्रत्येक रेलवे 'जोन' में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से रेलवे द्वारा कुल कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ख) वर्ष 1972-73 की तुलना में प्रत्येक 'जोन' में बिना टिकट यात्रा में कहां तक कमी हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1972-73 और 1973-74 के दौरान (जनवरी 1974 तक) बिना टिकट पकड़े गये यात्रियों का मासिक औसत दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि 1973-74 में 1972-73 की तुलना में सामान्यत: बिना टिकट यात्रा में गिरावट आयी है, हालांकि केवल इस आधार पर कोई निश्चित परिणाम नहीं निकाला जा सकता।

विवरण

रेलवे	बिना टिकट पकड़े गये यात्रियों की संख्या		1973-74 (जनवरी, 1974 तक) बिना टिकट यात्रियों से वसूल की गयी रकम
	1972-73	1973-74 (जनवरी, 1974 तक)	
मध्य	2,50,400	1,96,555	32,23,097
	(20,867)	(19,655)	
पूर्व . . .	3,28,478	2,61,874	31,72,920
	(27,373)	(26,187)	
उत्तर .	1,92,328	1,47,220	23,99,631
	(16,027)	(14,722)	
पूर्वोत्तर . . .	1,42,603	98,186	12,60,498
	(11,884)	(9,819)	
पूर्वोत्तर सीमा .	72,168	57,736	7,12,600
	(6,014)	(5,774)	

रेलवे	बिना टिकट पकड़े गये यात्रियों की संख्या		1973-74 (जनवरी, 1974 तक)
	1972-73	1973-74 (जनवरी, 1974 तक)	बिना टिकट यात्रियों से वसूल की गयी रकम
दक्षिण . .	1,83,702	1,45,058	22,18,639
	(15,309)	(14,506)	
दक्षिण मध्य	1,35,056	1,20,654	16,88,010
	(11,255)	(12,065)	
दक्षिण पूर्व	1,62,653	1,22,058	14,13,199
	(13,554)	(12,206)	
पश्चिम	2,72,156	2,14,103	26,63,428
	(22,680)	(21,410)	
जोड़ .	17,39,544	13,63,444	1,87,52,022
	(1,44,962)	(1,36,344)	

नोट :—कोष्ठों में आंकड़े मासिक औसत के सूचक हैं।

दिल्ली में डीजल की चोर बाजारी

6797. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में कई पेट्रोल-पम्प मालिक डीजल के लिए सरकारी दर से अधिक कीमत लेते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का डीजल की चोरबाजारी रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दिल्ली में पेट्रोल पम्प डिलरों द्वारा हाई स्पीड डीजल तेल के लिए उच्च मूल्य लेने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) तेल कम्पनियों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे सुनिश्चित करें कि उनके डीलर उचित मुल्य लेते हैं।

4—14 L. S. S./74

Relaying of Railway Lines in Rameshwaram Island

6798. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have received a demand letter from the Tamil Nadu Hindu Temple Protection Committee in regard to relaying of railway line in Rameshwaram. Island; and

(b) the action taken or proposed to be taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) In view of the technical difficulty of maintaining the line on account of sea erosion and tidal waves experienced in this area and the unremunerative nature of the line, it is proposed not to restore the railway line from Pamban to Dhanuskodi.

Attack on Moradabad Railway Station by Students in January, 1974

6799. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether students attacked and set Moradabad Railway station on fire in January, 1974;

(b) if so, the cause thereof; and

(c) the estimated loss suffered as a result thereof and the action taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) The students were agitating for setting up a University at Bareilly.

(c) Rs. 51,803/- approximately. Government Railway police registered a case No. 23 u/s 147/148/426/427/436 IPC and 120 of Indian Railway Act.

Departmental Enquiries against Railway Employees of Northern Railway

6800 Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of employees of the Northern Railway against whom departmental inquiries were instituted on the charges of theft of Railway property;

(b) the number of employees out of them against whom departmental enquiry is pending; and

(c) the number of persons out of them against whom probe was conducted through the C.B.I.?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 111 in 1973.

(b) 99 in 1973.

(c) Nil.

New over-bridges proposed to be constructed in Tamil Nadu during 1974-75

6801. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new over-bridges proposed to be constructed by Government in Tamil Nadu during the financial year 1974-75;

(b) the number of over-bridges for the construction of which the State Government had submitted proposals to the Central Government; and

(c) the expenditure proposed to be incurred by Government during the financial year 1974-75 on the construction of new bridges and over-bridges in the State?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दक्षिण मध्य रेलवे में नेल्लोर पर रेल की पटरियों की फिश प्लेटें, बोल्ट तथा बियरिंग का निकाला जाना

6802. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे में नेल्लोर पर तीन स्थानों से रेल की पटरियों की फिश प्लेटें, बोल्ट तथा बियरिंग निकाली हुई पाई गई थीं ;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों ने अपराधियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) सरकार का सुरक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध अपना कर्त्तव्य निभाने में लापरवाही बरतने के कारण और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ग) इस खण्ड पर 19-2-1974 से 22-2-1974 के बीच फ़िश प्लेटें हटाये जाने की तीन घटनाएं हुई थीं । रेलवे पुलिस ने तुरन्त मामले रजिस्टर कर लिये और जांच शुरू कर दी । रेलवे का कुछ सामान दो बाहरी व्यक्तियों से बरामद हुआ है जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है । जांच जारी है । रेल प्रशासन द्वारा रेल की पटरी की सुरक्षा के लिए विशिष्ट रूप से कोई सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त नहीं किये जाते । ऐसी सुरक्षा राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले कानून और व्यवस्था के सामान्य प्रबन्धों का ही भाग होती है । जहां कहीं अनुरक्षण कर्मचारियों की लापरवाही की ऐसी विशिष्ट घटनाएं नोटिस में आती है, जिनके परिणामस्वरूप पटरी में तोड़-फोड़ हुई हो, वहां मामले की गुण-दोष के आधार पर उनके विरुद्ध हमेशा कड़ी कार्रवाई की जाती है ।

ठेकेदारों द्वारा विभिन्न रेलवे से किये कार्यों के लिए धनराशि की अदायगी

6803. **श्री अम्बेश :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे में ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों के लिए अक्तूबर, 1973 के बाद धनराशि के अभाव में धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अदायगी न करने पर ठेकेदारों द्वारा की गई शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) क्या श्रम और सामग्री मूल्यों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ठेके चालू रखने की असम्भाव्यता के कारण सरकार का विचार ऐसे ठेकों को समाप्त करने का है जिनके लिए वह धनराशि की अदायगी नहीं कर सकती ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) इन भुगतानें को चालू वित्तीय वर्ष में करने का विचार है ।

(ग) चूंकि इस मामले में कानुनी और वित्तीय फलितार्थ निहित हैं इसलिए इसकी विस्तृत जांच आवश्यक है ।

नागपुर क्षेत्र में संतरों की ढुलाई के लिए वैगनों की कमी

6804. **श्री वसंत साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर क्षेत्र में वैगनों की अत्यधिक कमी से संतरों तथा अन्य माल के परिवहन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है तथा इससे संतरा उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं । नागपुर मण्डल के स्टेशनों से संतरों की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे सप्लाई किये गये हैं ।

दिल्ली कैंट-नांगल राय रेलवे फाटक पर रेलवे तथा सार्वजनिक जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया जाना

6805. **श्री वीवीकन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली कैंट-नांगल राय रेलवे फाटक पर रेलवे को तथा सार्वजनिक जमीन पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है जिसके कारण सड़क तथा रेल यातायात के मार्ग में रुकावट पड़ रही है;

(ख) इस क्षेत्र को अनधिकृत कब्जे से मुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या उस स्थान पर यातायात अबाधित रूप से चलने के लिए एक उपरि पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उपरि पुल का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां । इस क्षेत्र में रेलवे भूमि पर पान और बीड़ी की दुकानों के रूप में दो अतिक्रमण हुए हैं । इसके अलावा सब्जी और फल के खोमचे वाले भी रेलवे भूमि पर खोमचा लगा कर बैठते हैं जिससे सड़क यातायात में रुकावट पैदा होती है । लेकिन इससे रेल यातायात में विघ्न नहीं पड़ता ।

(ख) अतिक्रमण करने वालों में से एक के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू की गयी है, दूसरे के खिलाफ भी सरकारी परिसर (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की जा रही है । खोमचे वालों के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस से अनुरोध किया गया है कि वे इस गन्दगी को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठायें ।

(ग) और (घ) दिल्ली कैन्ट के निकट जेल रोड समपार पर एक सड़क ऊपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव अभी नगर निगम दिल्ली के परामर्श से जांच पड़ताल की प्रारम्भिक स्थिति में है । नियम के अनुसार नगर निगम दिल्ली को इसके खर्च के एक भाग को वहन करना होगा । इस समय इस कार्य को शुरू करने की कोई निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है ।

बम्बई वी० टी० तथा मनमाड के बीच तेज चलने वाली गाडी की मांग

6806. **श्री काहन डोले** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद में पर्यटक केन्द्रों के विकास, नासिक के समीप केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अनेक कार्यालयों तथा उद्योगों के खुलने तथा नासिक, जलगांव, धूलिया और अहमदनगर जिलों के कृषि विषयक तथा सामान्य विकास के कारण बम्बई वी० टी० तथा मनमाड के बीच यात्री यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के लोगों ने बम्बई वी० टी० तथा मनमाड के बीच एक नई तेज चलने वाली गाड़ी (बम्बई और सूरत के बीच डैक्कन क्वीन की तरह की) चलाने की मांग की है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी गाड़ी चलाने का है ; और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) बम्बई वी० टी० और मनमाड के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के लिए मांग होती रही है ।

(ग) जी नहीं, मार्ग में लाइन क्षमता का चरम सीमा तक उपयोग होने और बम्बई वी० टी० तथा मनमाड में सीमित टर्मिनल सुविधाओं के कारण ।

Setting up of more Power Plants in M.P.

6807. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government have requested for the setting up of more power plants to meet the requirements of the State; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) The Madhya Pradesh Government have sent proposals for setting up a thermal power station with two 200 MW units at Korin-West and installing two units of 110 MW each as an extension of the existing Korba Thermal Station. The former Scheme has been accepted in principle while the latter is under examination.

देश में कोयले के वैगनों का रोका जाना

6808. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में प्रतिदिन कोयले के 3,000 वैगने रोके जा रहे हैं ;

(ख) क्या जनवरी, फरवरी तथा मार्च 1974 के महीनों में कोयले का लदान 25% से 30% तक कम हो गया है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा उत्तरी क्षेत्रों के अन्य स्थानों और दक्षिण भारत के अतिरिक्त रेलवे को भी भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जब कर्मचारी आंदोलनों, सार्वजनिक उपद्रवों और अन्य बाह्य कारणों से गाड़ियों के संचलन में रुकावट पैदा होती है तो अस्थायी रूप से माल डिब्बों का जिनमें कोयला ले जाने वाले माल डिब्बे भी शामिल होते हैं, संचलन रुक जाता है । देश भर में अलग से कोयले के कितने माल-डिब्बे रुके रहे, इसका अनुमान लगाना कठिन है ।

(ख) जनवरी से मार्च 1974 के बीच 1973 की इसी अवधि की तुलना में कोयले के लदान में लगभग 12 प्रतिशत कमी हुई ।

(ग) विशेष रूप से दिसम्बर, 73 से मार्च, 74 की अवधि में कर्मचारियों के आंदोलनों के कारण कोयले के लदान कम हो जाने से रेलों को कम कोयला मिला । इसलिए, रेलों ने भाप कोयले की आवश्यकताओं को घटाया तथा समान वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कोयले का राशन कर दिया ।

(घ) सरकार इस समस्या से अवगत है और इसलिए रेल परिचालन को प्रभावित करने वाले कर्मचारी आंदोलनों को रोकने तथा कोयले के लदान और ढुलाई में सुधार करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों द्वारा सरकारी मशीनरी का उपयोग

6909. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों द्वारा वायु सेना के विमानों, हैलीकप्टरों तथा अन्य इसी प्रकार की सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाना अनुचित है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्य को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री को भारतीय वायु सेना के विमानों का अ-शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का हक प्राप्त है । यह उन स्थायी अनुदेशों द्वारा विनियमित है, जो यह व्यवस्था करते हैं कि जब कोई वायुयान अ-शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाए, उसके लिए संदाय सरकारी खाते में जमा के लिए किया जाएगा । यह सुविधा प्रधान मंत्री को, उस पद को धारण करने के कारण उपलब्ध है, न कि सत्ताधारी दल के नेता के रूप में ।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित सावधानी बरती है कि उसकी मशीनरी का प्रयोग किसी राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचनों में अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए न किया जाए ।

भारतीय तेल निगम में पूर्वी क्षेत्र के कर्मचारी

6810. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के पूर्वी क्षेत्र (कलकत्ता) के कुल कितने कर्मचारी डी० जी० एंड डी० के बिल बनाने तथा लेखा विभाग में हैं और उनमें कितने व्यक्ति समयोपरि भत्ता ले रहे हैं ;

(ख) दोनों अनुभागों में क्रमशः कुल कितना मासिक वेतन समयोपरि भत्ता दिया जाता है इतनी अधिक समयोपरि भत्ता दिये जाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकारी धन के इस दुरुपयोग की उच्चस्तरीय जांच, विशेषतः या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय तेल निगम की पूर्वी शाखा में डी० जी० एस० एण्ड डी० के बिल बनाने वाले तथा मशीन लेखा विभागों के कुल 95 कर्मचारियों में से, 93 कर्मचारी समयोपरि भत्ता ले रहे हैं ।

(ख) क्रमशः 64,000 रुपये तथा 19,000 रुपये । इस शाखा के ब्यौरे तैयार करने वाले केन्द्र में एक पारी में कार्य होता है । एक पारी में उपलब्ध मशीन घंटे वर्तमान कार्यभार को निपटाने के लिये काफी नहीं है । इसके अतिरिक्त, दरों का बार बार पुनरीक्षण, आई० ए० सी० की तालाबन्दी, रेलवे के इंजन ड्राइवरों की हड़ताल आदि से समस्त पूर्वी शाखा में फैले स्थानों से कागजात के प्रेषण एवं प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो गई थी और इस के कारण डी० जी० एस० एण्ड डी० के बिल बनाने वाले तथा लेखा अनुभागों में बहुत काम जमा हो गया था जिससे समयोपरि कार्य करने की जरूरत पड़ गई थी। इस के अतिरिक्त, बिजली की कमी के लिये पश्चिमी बंगाल में बार बार लौड-शैडिंग के कारण प्रत्येक सप्ताह में 10 से 12 घंटों की हानि हो जाती है ।

(ग) से (ङ) समयोपरि कार्यक्रम करने के लिये, दूसरी पारी शुरू करने, संगणनाकरण ; अतिरिक्त यूनिट रिकार्ड मशीनों की स्थापना अथवा विभिन्न स्टाक केन्द्रों के कागजात की संकेत-पद्धति का विकेन्द्रीकरण किये जाने के बारे में निगम के प्रस्ताव मान्यता प्राप्त यूनियन ने स्वीकार नहीं किये हैं। कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे समयोपरि कार्य की निगरानी निगम के उन अधिकारियों, जिन्हें इस समस्या की जानकारी है, द्वारा की जाती है और समयोपरि कार्य को घटा कर न्यूनतम, जितना कि कार्य करने के लिये अपेक्षित है, करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस बारे में उच्च स्तरीय अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच करवाये जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

उर्जा संकट से रेलवे को लाभ

6811. श्री बी० वी० नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा संकट के कारण रेलवे को प्राप्त अतिरिक्त यातायात के फलस्वरूप इस पर पड़ने वाले लाभकारी प्रभाव का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो रेल यातायात में वृद्धि होने के कारण रेलवे की आय में कुल कितनी वृद्धि होगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन क्षेत्र में विभिन्न टर्मिनल सेवाओं को सुव्यवस्थित किये जाने के बारे में कार्य अध्ययन दल ।

6812. श्री एम० एम० जोजफ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए कोचीन क्षेत्र में विभिन्न टर्मिनल सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रश्न तथा पुराने एर्नाकुलम गुड्स शड क्षेत्र के भावी रूप की जाँच करने के लिए एक कार्य अध्ययन दल गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कार्य अध्ययन पूरा हो चुका है और रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

बड़े व्यापार गृहों के नियंत्रण के अन्तर्गत कम्पनियों की वर्ष 1971–72 तथा 1973–74 के दौरान कुल परिसम्पत्ति, कुल बिक्री तथा लाभ

6813. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक बड़े व्यापार गहों के नियंत्रण के अन्तर्गत कम्पनियों की वर्ष 1971-72 और 1973-74 के वर्षों में कुल परिसम्पत्ति, कुल बिक्री तथा लाभ क्या हैं ; और

(ख) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग देश में एकाधिकारी व्यापार प्रक्रिया की वृद्धि को कहां तक रोक सका है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) फरवरी 1973 की संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसार एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रम बृहद् औद्योगिक गृह समझे जाते हैं एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके लिए वर्ष प्रतिवर्ष अपनी परिसम्पत्तियों व्यापारावर्त एवं लाभों के वार्षिक परिवर्तनों की बाबत सूचना भेजना अपेक्षित नहीं है ।

(ख) सरकार ने एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 31, जिसका उद्देश्य एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं पर नियंत्रण लगाना है, के अनुसरण में जांच के लिए, एकाधिकार एवं निर्बधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को तीन मामले निर्देशित किए हैं ।

एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के विनियमकारी उपबन्धों का मुख्य उद्देश्य, अत्याधिक विस्तार, नवीन उपक्रमों की स्थापना, संविलियनों के विनियम की प्रक्रिया के माध्यम से, जनहित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकना है । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गए पगों का वर्णन एकाधिकार एवं निबंन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्य एवं प्रशासन पर, द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट, जो गत वर्ष लोक सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी, में किया गया है ।

तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग द्वारा अशोधित तेल के अधिक मूल्य की मांग

6814. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने अशोधित तेल के अधिक मूल्य की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने आयातित अशोधित तेल के मूल्यों के अनुरूप अपने अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि करने को कहा है ।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि की गई है :—

(i) 22-8-1973 से 2-11-1973 तक प्रति बैरल 2.38 यू० एस० डालर से 2.48 यू० एस० डालर तथा प्रति वैरल 2.48 यू० एस० डालर से 3.58 यू० एस० डालर ।

(ii) जो 3 नवम्बर, 1973 से प्रभावी है ।

अथसराय (उत्तर प्रदेश) के सहायक स्टेशन मास्टर पर हमला

6815. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सिराद्द स्टेशन से अगले स्टेशन अथसराय के सहायक स्टेशन मास्टर को लगभग 40 व्यक्तियों ने 5 मार्च, 1974 को बांध दिया तथा टेलीफोन का कनेक्शन भी काट दिया ; और

(ख) क्या लूटपाट के मामले भी हुये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 4/5 मार्च, 1974 की रात को लगभग 20-25 सशस्त्र आदमियों ने, जिन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे के इलाहाबादमंडल इलाहबाद-फतेहपुर खण्ड पर स्थित अथसराय रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय को लुटा। बदमाशों ने स्टेशन पर लगे सिगनल गियर और अन्य दूर-संचार उपस्करों को क्षति पहुंचाई। वे पिस्तौल दिखाकर, ड्यूटी कर रहे सहायक स्टेशन मास्टर को तथा एक अन्य सहायक स्टेशन मास्टर को, जो अपनी ड्यूटी समाप्त करके उस कार्यालय में सोया हुआ था, एक कोने में ले गए ड्यूटी कर रहे सहायक स्टेशन मास्टर से रेलवे की नकदी रखने की अल्मारी की चाबी ली; नकदी रखने की अल्मारी, टिकट ट्यूब में से रेलवे के 259.85 रु० लिये और सहायक स्टेशन मास्टरों की हाथ की दो घड़ियां भी छीन लीं।

सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और इसकी छानबीन हो रही है। अभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है।

पहली सितम्बर, 1973 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत लाई गई कम्पनियां

6816. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली सितम्बर, 1973 को कितनी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 लागू होता था;

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत परिभाजित प्राइवेट लिमिटड कम्पनियों की संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने पिछले वार्षिक लेखे में 1 लाख रुपये से अधिक अथवा अपनी चुकता पुंजी की 10 गुना राशि से अधिक, जो भी कम है ; की संचित हानि दिखाई है ; और

(घ) ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्हें चिट फंड तथा ऐसे ही अन्य कार्यों के लिये बनाया गया था तथा जिसका विविध गैर-बैंकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1973 के पैरा 2 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) एक सितम्बर, 1973 तक, कार्यरत एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत, दोनों, पब्लिक लिमिटेड तथा प्राइवेट लिमिटेड, हिस्सों द्वारा सीमित, संयुक्त स्कन्ध कंपनियां 36,167 थी। इनमें से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत यथा परिभाषित, 29221 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां थीं।

(ग) अपेक्षित सूचना सुलभ नहीं है। कथित सूचना के संग्रह के लिये, 29,000 कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं की परीक्षा की आवश्यकता होगी।

(घ) सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

पोलिस्टर रेशे का उत्पादन करने वाली फर्में

6817. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

श्री वयालार रवि :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम और संख्या क्या है जिन्हें पोलिस्टर रेशे के उत्पादन के लिये संयंत्रों और मशीनों का आयात करने की अनुमति दी गई है और इस समय कितने एकक पोलिस्टर रेशे का उत्पादन कर रहे हैं और प्रत्येक एकक की उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से कुछ फर्मों ने इस बारे में सरकारी विनियमों को उल्लंघन किया है और अनुमति प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में मुख्य बातें क्या हैं और ऐसी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ब्यौरे नीचे दर्शाये गये हैं:–

क्रम सं०	फर्म का नाम	लाइसेंसयुक्त क्षमता (मीटरी टनों में)	1973 के दौरान क्षमता (मीटरी टनों में)	क्या संयंत्र तथा मशीनें आयात की गई है अथवा सी जी लाइसेंस दिया गया है ।
1	मैसर्स कैमिकल्स एण्ड फाइवर्स आफ इंडिया लि०	6100	6547	जी हां ।
2	मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	450	913	नायलोन स्टेपल फाइवर के निर्माण के लिये क्षमता के कुछ अंश का विविधिकरण करने से पोलिस्टर स्टेपल फाइवर का निर्माण करने के लिये क्षमता स्थापित की गई थी । फर्म को संतोलन उपकरणों का आयात करने की इजाजत दी गई थी ।
3	मैसर्स इंडियन आर्गेनिक केमिकल्स लि०	6100	3068	जी हां ।
4	मैसर्स स्वदेशी पोलिटैक्स लि०	6100	2572 (अप्रैल से दिसम्बर 1973 तक)	जी हां ।
5	मैसर्स अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एण्ड केलिको प्रिंटिंग कं० लि०	6100	फर्म ने अभी वाणिज्यिक उत्पादन स्थापित करना है ।	जी हां ।

क्रम सं०	फर्म का नाम	लाइसेंसयुक्त क्षमता (मीटर टनों में)	1971 के दौरान क्षमता (मीटर टनों में)	क्या संयंत्र तथा मशीनें आयात की गई है अथावा सी जी लाइसेंस दिया गया है।
6	मैसर्स पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवलेपमेंट कारपोरेशन लि० ।	6,000	—	राज्य उद्योग विकास निगम को 12 अगस्त, 1970 को एक आशय पत्र दिया गया था । सी० जी० तथा एफ आई बी प्रस्तावों को सरकार द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है । इस समय निगम विदेशी मुद्रा ऋण के लिये बातचीत चल रही है ।

(ख) और (ग) पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के यूनिटों को अपनी लाइसेंसयुक्त क्षमता के 125% तक उत्पादन करने की इजाजत दी गई है । मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स ने अपनी क्षमता से बहुत अधिक उत्पादन किया है । सरकार द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है ।

विकास परिषद (भेषज) का गठन

6818. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास परिषद् (भेषज) डी० जी० टी०डी० सरकार द्वारा नियुक्त एक मान्यता प्राप्त निकाय है;

(ख) क्या विकास परिषद् का पदेन सदस्य सचिव डी० जी० टी० डी० का एक विकास अधिकारी है;

(ग) क्या उक्त अधिकारी द्वारा "इण्डियन फर्मास्यूटिकल इण्डस्ट्री, 1973" के प्रकाशन से पूर्व उसमें विदेशी प्रभूत्व वाली फर्मों के बारे में निहित जानकारी की ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल कर ली गई थी, और

(घ) क्या इस पुस्तक के विमोचन समारोह में सदस्य सचिव उपस्थित था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के खण्ड 6 के अन्तर्गत सरकार द्वारा औषध एवं भेषज हेतु विकास परिषद् का गठन किया ।

(ख) डी० जी० टी० डी० के विकास अधिकारी (औषध एवं भेषज निदेशालय), जो औषध एवं भेषज के लिये अंतिम पुर्नगिठत विकास परिषद् के सरकारी सदस्य थे, को इस परिषद् का भी सदस्य सचिव के रूप में नामांकित किया गया ।

(ग) "इण्डियन फर्मास्यूटिकल्स इण्डस्ट्री, 1973" प्रकाशन में निर्दिष्ट फर्मों के बारे में सूचना फर्मो से प्राप्त सूचना के आधार पर दी गई ।

"इंडियन फर्मास्युटिकल इण्डस्ट्री 1973" नामक पुस्तिका का विमोचन

6819. श्री भालजीभाई परमार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री ने "इण्डियन फर्मास्यूटिकल इण्डस्ट्री, 1973" नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका संकलन तथा प्रकाशन विकास परिषद् डी० जी० टी० डी० द्वारा किया गया है;

(ख) क्या इस पुस्तक में निहित डी० जी० टी० डी द्वारा दी गई जानकारी को प्राधिकृत माना जाएगा;

(ग) यदि नहीं तो क्यों ;

(घ) क्या इस पुस्तक को एक गैर-सरकारी व्यक्ति ने प्रकाशित किया है और यदि हां, तो डी०जी०टी० डी० के नाम का उपयोग किये जाने का क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं ; और

(ङ) क्या इस पुस्तक में निहित कुछ ब्यौरे भारत स्थित विदेशी फर्मों की सहायता के लिये हैं तथा क्या पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व उन बातों की जांच नहीं की गई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ) विकास परिषद् के अध्यक्ष द्वारा किये गये आग्रह पर औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा 24 दिसम्बर, 1973 को "इण्डियन फर्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, 1973" प्रकाशन जारी किया गया था। यह प्रकाशन विकास परिषद् द्वारा औषध एवं भेषज हेतु जारी किया गया। प्रकाशन में दिये गये विभिन्न फर्मों के सम्बन्ध में सूचना फर्मों द्वारा प्राप्त हुई है।

मंदिरों में हरिजनों की पुजारी के रूप में नियुक्ति

6820. श्री एम० कतामुतु :
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा है कि मंदिरों में हरिजनों की पुजारी के रुप में नियुक्ति करने के लिये संविधान में संशोधन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार के निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) तमिल नाडु सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह यह बताए कि इन संशोधनों का ठीक ठीक विस्तार और परिधि क्या है।

Wages of Casual Labour in Railways

6822. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railways employ the maximum number of casual labourers and the labourers are getting the wages at the old rates even in these days of soaring prices;

(b) whether Government propose to pay them reasonable wages and to make them permanent; and

(c) if so, the steps proposed to be taken in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) The Railways employ about 3.17 lakhs of casual labour. Large number of casual labour are already being absorbed against regular posts every year.

Casual labour not governed by the Minimum Wages Act receive wages as prevalent in the locality. Casual labour governed by the Minimum Wages Act receive wages as fixed under that Act. Their wages are reviewed from time to time and revision effected as and when necessary.

(c) **Does not arise.**

राजस्थान में पचपदरा, डीडवाना और साम्भर नमक उत्पादन क्षेत्रों को 'सी' और 'ई' श्रेणी के माल डिब्बों की सप्लाई

6823. **श्री लालजी भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पचपडरा, डीडवाना तथा साम्भर नमक उत्पादन क्षेत्रों को समानरूप से समय पर रेलवे 'सी' और 'ई' श्रेणी के माल डिब्बों की सप्लाई नहीं की जाती जिससे उत्पादकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या राजस्थान में विभिन्न नमक उत्पादन क्षेत्रों को समान स्तर पर माल डिब्बों की सप्लाई नहीं की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) डीडवाना नमक के लदान का स्टेशन नहीं है। इस क्षेत्र से नमक का लदान मारवाड़ बलिया से किया जाता है।

राजस्थान में पचपद्रा, मारवाड़ बलिया और साम्भर नमक स्रोतों सहित नमक के लदान के लिये विभिन्न स्टेशनों को माल डिब्बों के सप्लाई स्टेशनों की मांग, उनकी प्राथमिकता और पंजीकरण की तारीख को ध्यान में रखते हुए माल डिब्बों की उपलब्धता के अनुसार की जाती है। इसलिये नमक के लदान के विभिन्न स्टेशनों को माल डिब्बों की सप्लाई का एक समान स्वरूप अपनाना सम्भव नहीं है।

जहां तक समय पर सप्लाई का संबंध है, गाड़ी परिचालन को प्रभावित करने और माल डिब्बों की उपलब्धता की कृत्रिम कमी उत्पन्न करने वाले विभिन्न प्रतिकूल कारणों से इस क्षेत्र से नमक का लदान मांग के अनुरूप नहीं रह सका। लदान बढ़ाने के लिये प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

Facilities afforded to Directors and Senior Officers of F.C.I.

Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4188 on the 11th December, 1973 regarding the facilities provided to Director of Fertilizer Corporation of India and state:

(a) the various types of facilities extended by the Fertilizer Corporation of of India to the Members of its Board of Directors and Senior Officers during the last three years and the expenditure incurred thereon under each head;

(b) the various steps taken in this regard under the economy drive together with the dates on which these steps were taken; and

(c) the economy measures proposed during the next year?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan: (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the **House.**

शिक्षित बेरोजगारों और सहकारी समितियों को दिये गये बुक स्टालों के ठेके

6826. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगारों, सहकारी समितियों तथा पिछले भारत-पाकिस्तान युद्ध शहीदों की विधवाओं को बुक-स्टालों के कितने ठेके दिये गये हैं ; और

(ख) क्या रेल प्राधिकारी उन स्थानों पर, जहां अब तक विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू नहीं की गई है, इन वर्गों के व्यक्तियों को खान पान के ठेकों को भी देने के बारे में विचार कर रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अब तक बेरोजगार स्नातकों की तीन सहकारी समितियों को बुक स्टालों के तीन ठके एक मद्रास बीच, एक मचादा और एक छिंदवाड़ा स्टेशन पर दिये गये हैं । इन में मद्रास बीच वाला बुक स्टाल 10-2-74 से काम करने लग गया है ।

(ख) बेरोजगार स्नातकों को खान पान के ठेके आबंटित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

बम्बई हाई में पाये गये तेल की मात्रा और उस पर किया गया व्यय

6827. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई के क्षेत्र में कितना तेल पाये जाने का अनुमान है और इसका वाणिज्यिक आधार पर कब तक प्रयोग किया जा सकेगा ; और

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और छिद्रण कार्य करने तक कितने धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वाणिज्यिक आधार पर प्रयोग के लिये बम्बई हाई से प्राप्त किए जाने वाले तेल की मात्रा के बारे में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(ख) 28-2-1974 तक किया गया कुल राजस्व व्यय 451.64 लाख रुपये है । एक कुंए में तेल संकेतों के आधार पर यह कहना संभव नहीं होगा कि व्यधन पर कितना और अधिक व्यय आएगा ।

Supply of Oil to Primary Industries at concessional rates

6828. Shri B. S. Chowhan: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a scheme to supply petrol, mobil oil and other oils without levying Government tax or giving concession in Government taxes to semi-developed and primary industries manufacturing essential commodities;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) such a scheme is not considered feasible of implementation.

Increase in Revenue Receipts for Sale of Third Class Railway Tickets during 1973-74

6829. **Shri B. S. Chowhan :** Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether the amount of revenue receipts on account of scales of third class Railway tickets was greater in the year 1973-74 than that for the year 1972-73 ;

(b) if so, whether Government propose to provide additional facilities this year to the passengers travelling by third class since renamed as Second Class ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir. The earnings from the sale of third class Railway tickets during the year 1973-74 are likely to be of the order of Rs. 320 crores (Provisional) as compared to Rs. 299.99 crores during the year 1972-73.

(b) Steps taken to provide additional facilities to passengers during this year include :—

(i) Provision/extension of waiting facilities.

(ii) Provision of water coolers at various stations.

(iii) Opening of additional booking windows wherever considered necessary.

(iv) Setting up of public address systems at stations.

(v) Running of additional trains and extension/augmentation of existing trains services to reduce overcrowding.

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त सहायक अधिकारियों को स्थायी करना

6830. **श्री आर० बी० बडे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अस्थायी रूप में नियुक्त 600 सहायक अधिकारी दस वर्ष की सेवा करने के बाद भी अस्थायी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों को एक साथ स्थायी करने की रेलवे की कोई योजना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1956 से 1968 तक सीधे भर्ती किये गये 1089 अस्थायी सहायक अधिकारियों में से लगभग 400 ऐसे अधिकारी हैं जिनकी 10 वर्ष से अधिक की सेवा है और वे अभी अस्थायी हैं।

(ख) अस्थायी सहायक अधिकारियों को श्रेणी 1 के संवर्ग में स्थायी रूप से आमेलित करने का कोटा समय-समय पर बढ़ाया गया है और इस हेतु वर्तमान कोटा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से वास्तविक रूप से भर्ती किये गये अधिकारियों का 60 प्रतिशत है।

अस्थायी सहायक अधिकारियों को आमेलित करने के लिये कोटे में और अधिक वृद्धि करने का प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है।

कलकत्ता में पटसन उद्योग में हड़ताल से वैगनों के आवागमन पर प्रभाव

6831. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में पटसन उद्योग में हाल ही में हुई हड़ताल का वैगनों के आवागमन पर प्रभाव पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो उसका कितने वैगनों के आवागमन पर प्रभाव पड़ा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) हड़ताल से पहले पर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों के स्टेशनों से सामान्यत: प्रतिदिन औसतन 240 माल डिब्बों में पटसन का जो लदान होता था, उस पर एक महीने से अधिक अवधि-तक के लिये बुरा प्रभाव पड़ा । इसके अलावा, इस अवधि में रेलों पर पटसन से लदे लगभग 4,000 माल डिब्बे रुके रहे ।

पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों में निर्माणाधीन रेलवे लाइनें

6832. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों में कौन-कौन सी रेलवे लाइनों का निर्माण आरम्भ किया गया;

(ख) इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी धनराशि अब तक लाइनवार व्यय की गई है, और

(ग) उक्त लाइनों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों में किसी रेलवे लाइन के निर्माण की मंजूरी नहीं दी गयी थी। लेकिन पहले से स्वीकृत पाश कुडा हल्दिया लाइन (69.41 कि० मी०) के दुर्गाचक्र हल्दिया खण्ड (10.18 कि० मी०) का निर्माण कार्य चालू है। इस लाइन का पांशकुडा दुर्गाचक्र खण्ड (59.43 कि० मी०) 1969 में पूरा हो गया था। इस परियोजना की 8.75 करोड रुपये की स्वीकृत लागत में से 8.05 करोड रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। भूतपूर्व लाइट रेलों द्वारा सेवित क्षेत्रों में हवडा से आमता और हवडा से शियाखाला तक बडी लाइन का निर्माण कार्य भी स्वीकृत हो गया है । इस लाइन की पुंजीगत लागत और परिचालन में राज्य सरकार के सहयोग से सम्बन्धित विवरण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इसके पूरा होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में नई रेलवे लाइनों के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट

6833. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष में रेलवे बोर्ड ने सुन्दर बन क्षेत्र समेत पश्चिम बंगाल में कितनी रेलवे लाइनों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया है;

(ख) किन किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है और इन सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की मुख्य बातें कौनसी है, और

(ग) इन सर्वेक्षणों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पिछले तीन वर्षों से पश्चिम बंगाल में नयी लाइनों के निर्माण, छोटी लाइन को बडी लाइन में बदलने और लाइट रेलों को फिर से बडी लाइन के रूप में विछाने के लिए चार परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण शुरु किये गये जो पुरे हो चुके है ।

(ख) और (ग) प्रस्तावों के स्थानों के नाम और उनकी वर्तमान स्थिति नीचे बतायी गयी है :–

(i) कृष्णनगर सिटी—शान्तीपूर (छोटी लाइन से बडी लाइन में बदलाव) यातायात सर्वेक्षण पुरा हो गया है। अनुमान है कि इस 15 कि० मी० लम्बे छोटी लाइन खंड को बडी लाइन में बदलने पर 1.30 करोड रुपये की लागत आयेगी। चूंकि इस आमान परिवर्तन पर आवर्ती हानि होगी इसलिए रिपोर्ट पर उचित विचार करने के बाद यह प्रस्ताव छोड दिया गया है।

(ii) पुरुलिया कोटशिला—(छोटी लाइन से बडी लाइन में बदलाव) यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इस 35 कि० मी० लम्बे आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत .54 करोड रुपये है।

(iii) एकलाखी—मालदा (नयी बडी लाइन) यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इस 90 कि० मी० लम्बी लाइन की अनुमानित लागत 10.35 करोड रुपये है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनसार इस लाइन से लाभ होने की सम्भावना नहीं है।

(iv) हावडा—आम्ता और हावडा—शियाखाला (भूतपूर्व लाइट रेलों द्वारा सेवित क्षेत्रों में बडी लाइनों का निर्माण)

इस निर्माण कार्य के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण पूरे हो चुक है और इस निर्माण कार्य के लिए 1973-74 की अनुदान की पूरक मांगों के जरिये मंजूरी मिल गयी है। इस लाइन की पुंजीगत लागत और परिचालन में राज्य सरकार के हिस्स की लागत का ब्यौरा अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है। जब इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा उसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 13.5 करोड रुपये है।

जहां तक कि सुन्दरबन क्षेत्र विशेष का प्रश्न है अतीत में इसके लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित बडी लाइनों के लिए यातायात सर्वेक्षण जारी है :

1. लक्ष्मीकांतपुर के कुल्पी होकर काकद्वीप तक।
2. कैनिंग से गोलाबारी तक।
3. हसनाबाद से प्रतापादित्यनगर होकर कैनिंग तक।
4. सोनारपुर/चम्पाघाट से धनखाली तक।

इसके अलावा, बज बज से डायमंड हारबर होकर नामखाना तक बडी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण करन का प्रस्ताव है।

जब सर्वेक्षण पूरे हो जायेंगे उसके बाद इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जायेगा।

राज्यों की राजधानियों को रेलवे लाइनों से जोडने का निर्णय

6834. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे लाइनों से जुडी हुई हैं;

5—14 L. S.S./74

(ख) यदि नहीं, तो कौन से राज्यों की राजधानियां रेल लाइनों से नहीं जुडी हुई हैं; और

(ग) क्या इन राजधानियों को रेल लाइनों से जोडने के लिए कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश (सभी पहाडी राज्य)

(ग) जी नहीं ।

क्विलोन में छात्रों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां

6835. **श्री वयालार रवि :**
श्री रामचन्द्रन कडमापल्ली :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि क्विलोन तथा आसपास के क्षेत्रों के छात्रों को उस क्षेत्र में बहुत सी स्थानीय गाडियों को रोके जाने के कारण कठिनाइयां हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) क्यूलन–त्रिवेंद्रम खण्ड पर चलने वाली 18 नियत गाडियों में से 6 गाडियां कोयले की कठिन स्थिति के कारण रद्द कर दी गयीं है। इस सम्बन्ध में स्थिति सुधर जाने पर इन गाडियों को पुनः चलाने के बारे में विचार किया जायेगा ।

Criminal assault on four women in the Train running between Alwar and Gurgaon

6836. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether certain persons criminally assaulted four women in the running train between Alwar and Gurgaon Stations on the 27th February, 1974;

(b) whether many other passengers were also present in the train at that time but they could do nothing to prevent the crime;

(c) if so, the broad features of the incident; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to prevent the recurrence of such incidents in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No such incident has been reported.

(b) to (d) Does not arise.

कुर्माडांगा हाल्ट को स्टेशन में बदलना

6837. **श्री गदाधर साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदपुर-कटवा (नैरोगेज) रेलवे लाइन पर 'कुर्माडांगा' हाल्ट को सभी सुविधाओं सहित पूरे स्टेशन में बदलने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कार्य कब तक आरम्भ किए जाने और पूरा किए जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां। कुर्माडांगा हाल्ट को क्लैग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव की जांच की गयी है किन्तु आर्थिक दृष्टि से इसका औचित्य नहीं पाया गया है। अतः इस काम को हाथ में लेने का विचार नहीं है।

Selection of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates by Railway Service Commissions for different Classes

6838. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of candidates selected by various Railway Service Commissions for each class during the last two years;

(b) the number of candidates among them of those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(c) whether all the reserved posts for these Castes/Tribes were filled by appointing the candidates belonging to these Castes/Tribes and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) The number of candidates recommended by the Railway Service Commissions for appointment on the Railways in Class III posts is as under:

Year	Total No. recommended	S. C.	S. T.
1971-72	4326	634	145
1972-73	4788	604	166

(c) Vacancies reserved for Scheduled Castes are generally filled, except in a few technical categories where the response is not adequate. In respect of Scheduled Tribes, there is the added difficulty as Scheduled Tribes are available in Tribal belts only and are not evenly spread all over the country so much so that in certain areas their population is very much less than the vacancies reserved for them.

Strike by Railway Employees of different Departments at Jhansi Station

6839. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether six workers of Wagon and Carriage Department were arrested in an unauthorised manner by a R.P.F. Sub-Inspector at Jhansi Railway Station on 16th March, 1974;

(b) whether following their arrest complete strike was observed in the entire workshop, Railway Station, Divisional Office, Loco Workshop, Railway Enquiry, Parcel Office and Catering Department;

(c) whether because of cent per cent strike, no trains could leave and arrive at Jhansi Junction between 10 A.M. to 5 P.M.; and

(d) whether the Railway Divisional Superintendent, Jhansi Stayed in his office the whole day but did not come to Jhansi Station and had he visited the Station, the strike would have ended at that very moment?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) They were rounded up along with some outsiders when a trespass raid against unauthorised persons was arranged in Jhansi Yard and later released.

(b) A large number of railway staff at Jhansi left their work and joined the agitation against the rounding up.

(c) There was heavy detention to trains ranging from one to nine hours.

(d) Although he did not visit the station, he was in touch with the situation and was in contact with the local civil and police officials and the Head Office at Bombay.

इंटग्रेल कोच फैक्ट्री, मद्रास द्वारा फिलीपाइन्स नेशनल रेलवे को रेल डिब्बों की सप्लाई

6840. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्ट्रेग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास को फिलापाइन्स नेशनल रेलवे को 30 रेल कोचों की सप्लाई करने के लिए आशय-पत्र प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या अन्य देशों द्वारा भी रेल डिब्बों की सप्लाई के लिए मांग की गई है;

(ग) क्या ये मांगे पूरी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इंटेग्रल कोच फैक्टरी, की प्रति वर्ष उत्पादन दर क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बंगला देश रेलवे ने भी भारत से 50 सवारी डिब्बे खरीदने की इच्छा व्यक्त की है लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते है जिनकी जांच की जा रही है। फिलिपीन का आर्डर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) पांचवी योजना अवधि में सवारी डिब्बा कारखाने ने 750 सवारी डिब्बे प्रति वर्ष बनाने की योजना बनायी है बशर्ते धन उपलब्ध हो।

कोयले से तेल निकालने संबंधी परियोजना

6841. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की एक फर्म ने कोयले को पेट्रोलियम के रूप में तरल बनाने के संयंत्र लगाने की ओर रुचि दिखायी है;

(ख) तेल के स्थान पर कोयले से चलाए जा सकने वाले उद्देश्यों का पता लगाने के लिए क्या सरकार ने डी० जी० टी० डी० के अधीन एक समिति का गठन किया है, और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जापान की दो फर्मों मितसुई कम्पनी तथा मित्सुबिशो कम्पनी ने कोयले को तरल बनाने का संयंत्र स्थापित करने के बारे में खान विभाग को अपने विचार व्यक्त किये है। इन दोंनो कम्पनियों के विशेषज्ञों की सहायता से भारतीय कोयले के परीक्षण किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) भट्टी के तेल पर तकनीकी विकास के सचिव तथा महानिदेशक की अध्यक्षता में तथा पेट्रोलियम और रसायन रलवे इस्पात एवं खान मंत्रालयों तथा केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग के प्रतिनिधियों से युक्त एक स्थाई समिति का गठन किया गया है। तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार इस समिति के सदस्य सचिव हैं। यह समिति और बातों के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन पर रोक लगाये बगैर देश में भट्टी के तेल की खपत करने के उपायों की सिफारिश करेगी, भट्टी के तेल के आबंटन के लिये सिद्धांत निर्धारित करेगी, भट्टी के तेल की खपत पर रोक लगाने संबंधी उपायों की कार्यान्विति का निरीक्षण करेगी, उन उद्योगों, जो प्रौद्योगिकी तथ्यों पर भट्टी के तेल के खान पर कोयले का प्रयोग कर सकते हैं, को कोयले की उपलब्धता की प्रगति पर निगरानी रखेगी तथा भट्टी के तेल के लिये उपभोक्ताओं की नई मांगों की जांच करेगी। इस समिति ने भट्टी के तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग किये जाने पर एक उप-समिति बनाई है।

तल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और ईराक के एन० ओ० सी० के बीच करार

6842. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 20 अगस्त, 1973 को किए गए ठेके के अधीन ईराक नेशनल आयल कम्पनी को किसी प्रकार की सहायता देगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या ईराक नेशनल आयल कम्पनी पूरा खर्च वहन करेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या रियायती दर पर कुछ निर्धारित मात्रा में अशोधित तेल खरीदने के अधिकार के रूप में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सेवाओं के बदले भुगतान किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) 22 अगस्त, 1973 को हस्ताक्षर किये गये ठेके के अन्तर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ईराक नेशनल आयल कम्पनी (आई० एन० ओ० सी०) को ईराक में 4175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम के अन्वेषण तथा उपयोग तथा उनसे उत्पादित पेट्रोलियम के विपणन के सम्बन्ध में विशिष्ट तकनीकी, वित्तीय एवं वाणिज्यिक सेवाएं देगा। वाणिज्यिक रूप में खोज तथा उत्पादन होने पर आई० एन० ओ० सी० से समस्त लागत की वसूली की जायेगी तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अपने अधिकारों के माध्यम से क्षेत्र से उत्पादित अशोधित तेल की कुछ विशिष्ट मात्रा की खरीद को "गारण्टीकृत विक्रय मूल्य" की रियायत पर अपनी सेवाओं के लिए परिश्रमिक के रूप में दिया जायेगा।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा उडीसा में बडी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना

6843. **श्री डी० के० पंडा : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1974 तक उडीसा में ऐसी बडी परियोजनाओं के विशेषकर कि जिला गंजम में ऐसी परियोजनाओं के नाम तथा संख्या क्या है जिनकी स्वीकृति केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा अभी दी जानी है तथा नयी परियोजनाएं कौन सी हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) क्या उडीसा में गंजम जिले की जरान-हाराभंगी सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है;

(ग) यदि हां तो कब, और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वियन के हेतु केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से स्वीकृति दिलाने के लिए कोई समय सीमा तथा मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मार्च, 1974 के अन्त में केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के पास उड़ीसा को निम्नलिखित दो बृहत् सिंचाई परियोजनाएं निलम्बित पड़ी थीं :—

परियोजना का नाम	लाभान्वित जिला
बाध	फूलबनी
बडानाला	कोरापुट

मार्च, 1974 के अन्त में गंजम जिले से संबंधित कोई भी बृहत सिंचाई परियोजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए निलम्बित नहीं पडी थी।

सूचना मिली है कि उडीसा में इस समय 26 परियोजनाओं का अन्वेषण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के नामों की सूची संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा योजना आयोग को तकनीकी सलाहकार समिति को 1970 में स्वीकृति-प्राप्त समेकित जोरों-हरभंगी परियोजना का अन्वेषण उडीसा सरकार द्वारा पुन: किया जा चुका है। राज्य सरकार ने अब इस परियोजना को तीन मध्यम सिंचाई स्कीमों नामत: जोरा, हरभंगी, और पद्मा में विभाजित कर दिया है। जोरों और हरभंगी की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में प्राप्त हो चुकी है और राज्य सरकार के साथ परामर्श करके उनको जांच की जा रही है। पद्मा परियोजना की परियोजना रिपोर्ट उडीसा सरकार से केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए कोई विशेष निर्देश अथवा समयावधि नियत नहीं की गई है। आयोग द्वारा हर संभव प्रयत्न किया जाता है कि तकनीकी-आर्थिक और अन्य ब्योरों के संबंध में परियोजनाओं के पूर्ण होने पर निर्भर करते हुए उनको न्यूनतम संभव समय में स्वीकृति दे दी जाए।

विवरण

उन परियोजनाओं के नाम जिनका अनुसंधान किया जा रहा है

1. औनलो
2. तिकारा
3. सिंगदजोर

4. सुंखराई
5. लोदानी
6. कंसाबहल
7. बरासुआ
8. गुमण्डी
9. तेलंगरो
10. उत्कापादु
11. लिल्लीवादी
12. बांगरो बांध परियोजना
13. सुण्डल
14. सुन्दर (इन्द्रा चरण-एक)
15. नोर्ला
16. सगदा
17. लोअर लांट
18. तितलागढ़
19. हरहराजोर
20. गजेंद्रधर बांध परियोजना
21. भालुझोरी
22. बुधारी
23. महेंद्रतनय
24. रामनदी और गोदाहडो सिंचाई परियोजना
25. लोहारखंडी
26. भिरोल ।

उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े मामले

6844. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :**
श्री गजाधर माझी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में, राज्य-वार, कितने मामले पांच वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े है; और

(ख) गत दो वर्षों में प्रति वर्ष औसतन कितने मामले निपटाये गए है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) ओर (ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

उच्च न्यायालय का नाम	पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	गत दो वर्षों के दौरान मामलों के वार्षिक निपटारे की औसत
1. इलाहाबाद .	13,766	34,736
2. आंध्र प्रदेश	33	37,574
3. बम्बई .	8,037	28,028
4. कलकत्ता .	19,526	41,739
5. दिल्ली	2,633	15,565
6. गोहाटी . .	307	2,803
7. गुजरात .	561	12,906
8. हिमाचल प्रदेश	256	1,499
9. जम्मू-कश्मीर	76	1,683
10. कर्नाटक .	29	19,806
11. केरल .	41	30,723
12. मध्य प्रदेश .	2,395	17,623
13. मद्रास	959	48,347
14. उड़ीसा .	219	5,090
15. पटना . . .	2,507	9,406
16. पंजाब और हरियाणा.	5,889	28,856
17. राजस्थान . .	942	8,572

उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों का लक्ष्य

6845. **श्री वनमाली बाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों का निर्माण लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और कितनी कमी रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेल सुविधाओं के विकास के लक्ष्य राज्यवार नहीं निर्धारित किये जाते। फिर भी कटक-परादीप रेलवे **लाइन** (84.31 कि० मी०) जो कि उड़ीसा में पड़ती है, का निर्माण चौथी योजना में पूरा किया गया है।

चौथी योजना में सिंचाई परियोजनाओं का लक्ष

6846. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं का लक्ष्य सरकार ने पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) चौथी योजना में 951 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बृहत् तथा मध्यम स्कीमों से 4.8 मिलियन हैक्टेयर को अतिरिक्त शक्यता का सृजन परिकल्पित था। बहरहाल, इस योजना के दौरान वास्तव में लगभग 1170 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है। वास्तविक अतिरिक्त शक्यता लगभग 3.1 मिलियन हैक्टेयर होने की संभावना है। आवर्धित वित्तीय व्यय के प्रति वास्तविक उपलब्धि में कमी मुख्यतया बहुत सी परियोजनाओं को लागतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुई है। सामग्री तथा श्रम की लागत में वृद्धि के अलावा बहुत से मामलों में अन्य महत्वपूर्ण सहायक कारण ये है—अपर्याप्त अनुसंधान और परियोजनाओं को उचित रूप में तैयार न करना, परियोजनाओं के कार्यान्वियन के दौरान उनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन और भूमि के मुआवजे तथा पुनर्वास की ऊंची लागत। परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण उनकी वास्तविक प्रगति धीमी हो गई है और कुछ परियोजनाएं पहले जिनके चौथी योजना में काफी हद तक पूर्ण होने की संभावना थी अब पांचवी योजना के दौरान ही लाभ दे पाएंगे।

कम संख्या में वैगनों के उपलब्ध होने के कारण सौराष्ट्र में लवण पटलों में बड़ी मात्रा में लवण जमा हो जाना

6847. **श्री के मालन्ना** :
श्री सी० के० जाफरशरीफ :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम संख्या में वैगनों के उपलब्ध होने के कारण सौराष्ट्र में लवण पटलों में लवण बड़ी मात्रा में जमा हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे अधिकारियों ने सौराष्ट्र में लवण एककों को 'बाक्स रेक्स' उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे वहां जमा स्टाक शीघ्र ही ले जाया जा सके ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) नागरिक उपद्रवों, कर्मचारी आन्दोलनों आदि के कारण, रेलों के संचलन में अक्सर बाधा पड़ती रही और इस से माल डिब्बों की उपलब्धता में कृत्रिम अभाव पैदा हो गया। अत: सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित स्टेशनों से नमक का लदान मांग के अनुरूप नहीं किया जा सका। इन बाधाओं के बावजूद कार्यक्रम वाले तथा औद्योगिक नमक जैसे उच्चतर प्राथमिकता वाले नमक की ढुलाई संतोषजनक स्तर पर बनाये रखी गयी। बिना कार्यक्रम वाले नमक की ढुलाई श्रेणी ई० को निम्नतम प्राथमिकता के अंतर्गत की जाती है। आयातित अनाजों और उर्वरकों जैसे उच्चतर प्राथमिकता वाले यातायात की ढुलाई तरजीही आधार पर करने के रेलों के दायित्व को देखते हुए बिना कार्यक्रम वाले नमक का अधिकतम लदान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कोयले के लदान की जरूरतों को पूरा करने के बाद जितने बाक्स माल डिब्बे फालतू बचाये जा सकते है उनमें भी नमक लदा जा रहा है।

गुजरात में सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना

6848. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में तीन सिंचाई योजनाओं को जिनमें से एक कच्छ जिले में है, तथा दो जूनागढ जिले में है, स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) इन योजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार का विचार कितनी सहायता देने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है :—

स्कीम का नाम	जिला	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	सिंचाई लाभ (हैक्टेयर में)
नारा	कच्छ	77.97	1100
रावल	जूनागढ	207.78	4050
मच्छन्दुरी . . .	जूनागढ	173.09	4460

(ग) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि इन सभी स्कीमों के 1976 के मध्य तक पूर्ण होने की संभावना है।

(घ) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी सम्पूर्ण विकासात्मक योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की जाती है । राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष विकास सैक्टर अथवा परियोजना से संबंधित नहीं होती ।

निर्माण लेखा कार्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली (उत्तर रेलवे) में ठेकेदारों के बिलों से संबंधित कार्य कर रहे कर्मचारियों का स्थानांतरण

6849. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण लेखा कार्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली में, 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक ठेकेदारों के कितने बिल प्राप्त हुए तथा कितने उसी दिन पास कर दिए गये;

(ख) निर्माण लेखा कार्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली में ठेकेदारों के बिलों से संबंधित कार्य कितने लेखापाल, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के लिपिक 1 जनवरी 1974 को 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे है; और

(ग) भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निर्माण लेखा कार्यालय में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को बदलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 28 बिल

(ख) लेखापाल . . . . . . कोई नहीं
लिपिक ग्रेड I 3
लिपिक ग्रेड II 4

(ग) ठेकेदारों के बिलों पर कार्यवाई करने वाले कर्मचारियों को सामान्यतः बारी बारी से बदल दिया जाता है और ऐसा करते समय इस बात का समुचित ध्यान रखा जाता है कि काम अस्तव्यस्त न हो।

उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के दिल्ली क्षेत्र के सब-हैडों को पुनरीक्षित वेतनमानों के कारण पूर्ण अदायगी

6851. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के दिल्ली क्षेत्र के सब-हैडों को पुनरीक्षित वेतनमानों की पूर्ण अदायगी नहीं की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रशासन ने उसकी शीघ्र अदायगी के लिए क्या कार्यवाही की है और उन्हें अदायगी के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं, सब-हैड के लिए संशोधित वेतनमान के आबंटन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जब उनके वेतनमान अधिसूचित किये जायेंगे तब संशोधित वेतनमान अपनाने के लिए कर्मचारियों को विकल्प देने हेतु तीन महीने का समय दिया जायेगा। उनका विकल्प प्राप्त होने पर संशोधित वेतनमान में उनका वेतन निश्चित किया जायेगा और बकाया राशि के बिल बनाये जायेगें। अभी से बकाया राशि के भुगतान के लिए कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती।

तेल के संबंध में नई नीति बनाना

6852. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारस की खाडी वाले देशों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि कर देने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई नई नीति बनाई है; और

(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों में उत्पादन स्तर बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार ने एस० चक्रवर्ती सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक ईंधन नीति समिति गठित की है। आशा है कि यह समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। इस रिपोर्ट में तेल सहित समस्त उर्जा स्त्रोतों का सप्तक का उल्लेख होना चाहिए। सरकार को यह रिपोर्ट मिलने तथा उस पर विचार किए जाने पर ही इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित की जायेगी।

(ख) सरकार ने कई अन्तरिम उपाय किए है जिनमें अन्य बातों के साथ साथ ये भी सम्मिलित है :—

(1) तेल उत्पादों की गैर आवश्यक खपत में यथा संभव अधिक से अधिक कमी की जा रही है,

(2) अर्थ व्यवस्था के अनिवार्य क्षेत्रों को सप्लाई जारी रखने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है,

(3) तेल उत्पादक देशों से द्विपक्षीय सम्पर्क स्थापित किए गए है ताकि कच्चे तेल के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि के प्रभावों को कम किया जा सके

(4) देश में भूमि तथा समुद्र तट से दूर कच्चे तेल के उत्पादन के सम्बन्ध में समन्वेषण तथा उसके विकास के लिए सघन प्रयास किए जा रहे हैं,

(5) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए एक समन्वित योजना तैयार की जा रही है ।

अपमिश्रण रोकने के लिये पेट्रोल पम्पो पर इश्तहार लगाया जाना

6853. **श्री रणबहादुर सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया था कि अपमिश्रण का पता लगाने में उपभोक्ताओं की सहायता करने के विचार से तेल कम्पनियों के खुदरा डिपुओं पर थोडे से शब्दों वाले इश्तहार लगाने चाहिए;

(ख) क्या विभिन्न पेट्रोल विक्रेता संघों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और अपने सदस्यों से कहा है कि वे इस प्रकार के इश्तहार न लगायें; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने के बारे में सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास तथा बम्बई के पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने पोस्टर लगाने के बिरोध में अभ्यावेदन भेजे है ।

(ग) देश में बहुत से डिलरों द्वारा सर्विस स्टेशनों पर पोस्टर लगाये जा रहे है । तेल कम्पनियों द्वारा डीलरों को स्पष्ट किया जा रहा है कि पोस्टर लगाने का यह आशय नहीं है कि उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे किन्तु इसका आशय मोटर चलाने वालों को मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिट्टी के तेल की संभाव्य मिलावट के बारे में सूचित करना है ।

उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाना

6854. **श्री सरजू पांडे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की वर्तमान रेल लाईनों का विद्युतीकरण करने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में अंशत: या पूर्णत: पडने वाली निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनें/उखाडी गयी लाइनों को फिर से बिछाने का काम शुरू किया गया है :—

(1) भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में बडी लाइन का निर्माण। प्रस्तावित नयी बडी लाइन की लम्बाई 161 कि० मी० होगी जिसकी अनुमानित लागत 17.42 करोड रुपये (लगभग) है। राज्य सरकार निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने को सहमत हो गयी है।

(2) मुरादाबाद और रामपुर से रामनगर और काठगोदाम तक बडी लाइनों का निर्माण (लागत 15 करोड रुपये)

(3) डलमउ से दरयापुर तक उखाडी गयी लाइनों को फिर से बिछाना (लम्बाई 26 कि० मी० (बडी लाइन) लागत 1.48 करोड रुपये)

(4) छितौनी से बगहा तक उखाडी गयी लाइन को फिर से बिछाना (लम्बाई 28.41 कि० मी० लागत 6.74 करोड रुपये)

(ग) और (घ) इस समय 22.19 करोड रुपये की लागत से टुंडला-दिल्ली खण्ड का विद्युतीकरण हो रहा है जो हबडा-दिल्ली ट्रंक मार्ग पर 259 रूट कि० मी० दोहरी लाइन का खण्ड है। टुंडला-दिल्ली खण्ड का बडा भाग उत्तर प्रदेश में आता है।

Electrification of Harijan Bastis in Fourth Plan

6856. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a 5 crore rupee scheme was formulated to electrify 20,000 Harijan Bastis during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the number of Harijan Bastis electrified under this scheme together with the names of the States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) In 1971, a scheme was introduced for providing concessional loan assistance to the State Electricity Boards for electrification of Harijan Bastis adjacent to the villages already electrified. An outlay of Rs. 5 crores was provided in the Fourth Plan to cover 20,000 such Harijan Bastis.

(b) The schemes for electrification of Harijan Bastis under the above programme are formulated and executed by the State Governments/State Electricity Boards. The loan assistance is provided by the Rural Electrification Corporation in accordance with the prescribed guidelines. On the basis of the schemes sponsored by the State Electricity Boards, the Corporation has up to 31-3-1974 sanctioned a loan assistance of Rs. 367.305 lakhs for providing 49,523 street lights in 8,617 Harijan Bastis. The schemes sanctioned by the Corporation are at various stages of implementation. 1,816 Harijan Bastis are reported to have been electrified. State-wise details of the schemes sanctioned by the Corporation and achievements made so far are given in the Statement attached.

STATEMENT

Statement showing the details of Schemes sanctioned and achievements made in respect of electrification of Harijan Bastis adjoining the villages already electrified.

Sl. No.	Name of State	No. of schemes up to 31-3-74	No. of Harijan Bastis	No. of street lights	Amount of loan sanctioned (Rs. in lakhs)	No. of Harijan Bastis electrified (As on 16-3-74)
1.	Andhra Pradesh	19	966	4878	34,090	48
2.	Bihar	1	207	1474	11,948	..
3.	Gujarat	3	513	3021	15,736	92
4.	Haryana	6	673	3611	33,584	..
5.	Kerala	4	61	520	4,254	..
6.	Madhya Pradesh	7	1248	8759	50,088	135
7.	Maharashtra	10	2419	12699	88,774	682
8.	Karnataka	5	406	1638	19,017	158
9.	Orissa	4	475	1653	19,824	35
10.	Punjab	4	394	2491	26,767	51
11.	Rajasthan	1	141	1245	9,298	136
12.	Tamil Nadu	4	477	2730	19,819	383
13.	Uttar Pradesh	4	514	3969	27,836	76
14.	West Bengal	3	123	835	6,270	20
	TOTAL	75	8617	49523	367,305	1816

Postponement of scheme to change Refreshment Contractors and Tea Stall owners functioning for the last six years

6857. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the scheme drawn up by the Railways for changing such refreshment contractors and tea-stall owners as have been functioning in the Railways for last six years, has been postponed ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the time for which it has been postponed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) There is no such scheme for changing refreshment/vending contractors who have been functioning for the last six years. There is however a scheme to call for fresh applications for refreshment/vending contracts which have been continuing for more than 6 years. Under this, the existing contractor is also eligible to apply and there is no bar to the contract being allotted to him if the Selection Committee finds him most suitable of all the applicants. The system has not been postponed.

(b) & (c) Do not arise.

आगामी गर्मी के मौसम में और अधिक रेल गाड़ियां चलाना

6858. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे ने आगामी गर्मी के मौसम के दौरान और अधिक रेल-गाडियां चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेलगाडियों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां को जायेंगी ; और

(ग) क्या भारी यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियमित रेलगाडियों में भी कुछ और डिब्बे लगाये जायेंगे ; और यदि हां, तो दिल्ली से अहमदाबाद तक मीटर गेज लाइन पर ऐसी कितनी रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहमद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) 1974 के गर्मी के मौसम में, अतिरिक्त यातायात को सम्हालने के लिए, पश्चिम रेलवे पर, निम्नलिखित विशेष गाड़ियां चलाए जाने का प्रस्ताव है :—

बड़ी लाइन

बम्बई सेंट्रल — जम्मु तवी . . .	प्रत्येक ओर 7
बम्बई सेंट्रल — नयी दिल्ली . . .	प्रत्येक ओर 2
बम्बई सेंट्रल — गांधीधाम . . .	प्रत्येक ओर 7
बम्बई सेंट्रल — वीरमगांव . . .	प्रत्येक ओर 31
अहमदाबाद — हवड़ा . . .	प्रत्येक ओर 2

मीटर लाइन

अहमदाबाद — अजमेर . . .	प्रत्येक ओर 2
अहमदाबाद — आबू रोड़ . . .	प्रत्येक ओर 29
वीरमगांव — राजकोट . . .	प्रत्येक ओर 31

इसके अतिरिक्त, जहां औचित्य तथा प्रचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक होगा, विभिन्न मार्गों पर वर्तमान गाडियों के डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है । दिल्ली—अहमदाबाद मीटर लाइन पर अहमदाबाद और अजमेर/आबू रोड के बीच प्रस्तावित विशेष गाडियां चलाए जाने के अतिरिक्त 3 अप /4 डाउन अहमदाबाद—दिल्ली एक्सप्रेस गाडी में एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा जोडा जा रहा है ।

भारतीय रेलवे में नई किस्म का दूसरा दर्जा

6859. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने दूसरे दर्जे के डिब्बों के स्थान पर नई किस्म के दूसरे दर्जे के डिब्बों को चलाया जाने लगा है; और

(ख) नए बनाये गये दूसरे दर्जे के डिब्बे वर्तमान डिब्बों की अपेक्षा कहां तक लाभप्रद सद्ध होंगे और रेलवे के यातायात की आवश्यकता को कहां तक पूरा कर सकेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। 1-4-1974 से गाडियों में पूर्ववर्ती तीसरे दर्जे का नाम बदलकर दूसरा दर्जा कर दिया गया है।

(ख) पुराने दूसरे दर्जे के डिब्बों को तीसरे दर्जे के डिब्बों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था जिसका नाम बदलकर अब दूसरा दर्जा कर दिया गया है। इससे दूसरे दर्जे के डिब्बों की निर्धारित वहन क्षमता लगभग 25 प्रतिशत बढ गयी है। इस दर्जे की यात्रा के बेहत्तर उपयोग और वहन क्षमता में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद इस सवारी डिब्बों की राजस्व उपार्जक क्षमता में कोई बहुत अन्तर होने की संभावना नहीं है हालांकि पुराने दूसरे दर्जे का किराया अधिक था। नये दूसरे दर्जे के अनुरक्षण पर भी खर्च कम आता है।

दिल्ली तथा बम्बई के बीच मुख्य ब्रॉड गेज लाइन को दोहरी लाइन बनाना

6860. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा बम्बई के बीच मुख्य ब्राड गेज लाइन को दोहरी करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो रायगंज मंडी के बीच की शेष लाइन के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस पर कितनी राशि व्यय की जायेगी;

(ग) क्या दिल्ली बम्बई ब्राड गेज लाइन के मुख्य जंक्शनों पर को मीटरगेज लाइनों के जंक्शनों से मिलाने वाली कुछ ब्रांच लाइनों को भी दोहरा किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या है तथा जयपुर-सवाई माधोपूर मीटर लाइन जो जयपुर तक सवाई-माधोपूर के बीच सम्पर्क बनाती है, को दोहरा बनाने संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) दिल्ली-बम्बई लाइन (पश्चिम रेलवे) पर 1030 कि० मी० दोहरी लाइन पहले से मौजूद है 352 कि० मी० में दोहरी लाइन बिछाने का काम हो रहा है, जिसके, कई चरणों में-1977-78 तक पूरे हो जाने की संभावना है बशर्तें अपेक्षित धन और सामान उपलब्ध हो। इस दोहरी लाइन को बिछाने पर 30.46 करोड रुपये की रकम खर्च होने की आशा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा कोयले से तेल निकालना

6861. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, भारत में कोयले से तेल निकालने के काम में लगा है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो वह संयंत्र कहां स्थापित किया जायेगा तथा उस पर कितना व्यय आयेगा तथा इसमें तेल का उत्पादन कब से आरंभ होगा;

(घ) इस तरह से निकाला गया तेल देश की आवश्यकताओं को कहां तक पूरा करेगा तथा आयातित तेल की तुलना में यह कितना सस्ता होगा; और

(ङ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ) कोयले से तेल निकालने के लिए इस समय इंजीनियर्स इंडिया लि० संयंत्र स्थापित करने में व्यस्त नहीं है । कोयले से एक मिलियन मीटरी टन तेल निकालने के लिए संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं की जांच करने हेतु इंजीनियर्स इंडिया लि० केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई है। अब यह समिति इस उद्देश्य के लिए प्रमाणित प्रौद्योगिकीयों की उपलब्धता की खोज कर रही है । इस समय स्थान अनुमानित पुंजी और परिचालन लागत या कोयले से तेल निकालने के लिए वाणिज्यिक संयंत्र से विदेशी मुद्रा की बचत की मात्रा के बारे में कहना कठिन है ।

मेयार रेलवे स्टेशन (मध्य प्रदेश) उपरि पुल का निर्माण

6862. **श्री नरेंद्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मेयार रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1974–75 में निर्माण कार्य आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का आशय मध्य रेलवे पर कटनी और मेहेर स्टेशन पर दो प्लेटफार्मों को जोडने के लिए एक उपरी पैदल-पुल की व्यवस्था से है, यदि ऐसा है तो स्थिति इस प्रकार है :—

यात्रियों के उपयोग के लिए एक प्लैटफार्म को दूसरे से जोडने के लिए उपरी पैदल-पुलों की व्यवस्था एक कार्यक्रम के आधार पर की जाती है बशर्ते धन उपलब्ध हो और ऐसा करते समय वहां के यातायात और परिचालन की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। इस तरह के कामों के लिए धन के अभाव के कारण अभी तक मेहर स्टेशन पर उपरी पैदल पुल की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाया है।

विदेशी फर्मों की एकाधिकार तथा निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में जांच संबंधी प्रतिवेदन

6863. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया की गतिविधियों में लगे विदेशी कम्पनियों के बारे में 26 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 886 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैडबरी फ्राई लिमिटेड के सम्बन्ध में निरीक्षकों की रिपोर्ट पर यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है; और

(ख) अन्य सभी कम्पनियों के बारे में जांच प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कैडबरी फ्राई (इण्डिया) प्राईवेट लि० की बाबत निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का विवरण, दिनांक 2 अप्रैल 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5401 के उत्तर में सदन को दिया गया था ।

(ख) जैसा कि दिनांक 2 अप्रैल 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5400 के उत्तर में दोहराया गया था कि आयोग ने, अपनी 31 दिसम्बर 1972 की वर्ष समाप्ति की अपनी कार्य कलापों की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अध्याय 4 के पैरा 5 में यह बतलाया था कि आयोग कथित अध्याय में यथार्वाणित, विभिन्न क्षेत्रों में, निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं की स्थिति की विद्यमानता के लिये कुछ अन्वेषण अध्ययन कर रहा है। तथापि, आयोग ने विनिर्दिष्ट किया है कि इन अध्ययनों में पर्याप्त समय लगेगा एवं पर्याप्त सामग्री के संग्रह होने व आयोग द्वारा औपचारिक कार्यवाहियों करने के निर्णय होने तक, इन अध्ययनों की बाबत ब्यौरे प्रकट करना, जांच के हित में नहीं होगा ।

सरकार ने कालगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लि० के विषय में एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 31 की उप धारा (1) के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग की, जांच एवं रिपोर्ट के लिए, 28 मार्च 1974 को निर्देश दिया था, क्योंकि सरकार को प्रतीत हुआ है कि यह कम्पनी कुछ अन्यों सहित कुछ व्यापार प्रथाओं में निरत है, जैसे कि : –

(1) बिक्री पर 31 प्रतिशत के लगभग, बहुत उच्च सकल लाभ दर एवं बिक्री की लागत पर 5 प्रतिशत की यथोचित प्रत्यावृत्त की तुलना में बिक्री की लागत पर 42 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक सकल लाभ-दर कमाना,

(2) लगाई गई पुंजी पर 1970 में लगभग 118 प्रतिशत व 1971 में 158 प्रतिशत से उपर की दर पर लाभ की अत्याधिक लाभ-दर कमाना,

(3) उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध कम्पनीं द्वारा लगाई गई माध्य पूंजी पर, करों की अदायगी के पश्चात 1970 में 50 प्रतिशत व 1971 में 46 प्रतिशत से उपर अनुचित शुद्ध लाभ कमाना,

(4) भारत में भवन आदि में स्थिर ब्लाक के रूप में बृहद नियोजन किये बिना लाभ प्राप्त करते रहना व उपभोक्ताओं के लाभार्थ सस्ती दर पर बढिया किस्म की उपभोग की वस्तु उत्पादन करने की दृष्टि से भारत में, अन्वेषण एवं विकास पर अत्याधिक व्यय न करना,

(5) केवल अपने उत्पादनों को न बेचकर कुछ अन्य एककों में बनाये गए उत्पादों को बेचना, एवं इन उत्पादों को अपनेक स्वयं के ब्राण्ड नाम के अन्तर्गत बेचे जाने की अनुमति देना, जबकि ये उत्पाद कालगेट के लिए बाहर की एजेंसियों द्वारा अपने देशी कच्चे माल व जानकारी से तैयार किये जाते है, कम्पनी एवं छोटे एकक जो इन्हें पैदा करते है, उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध अनुचित लाभ कमाते है। यह एकाधिकारक व्योपार प्रथायें समझी जानी चाहिये, जिनके परिणाम स्वरूप कम्पनी द्वारा उत्पादित माल के उत्पादन, पूर्ति व वितरण से सम्बन्धित लागत, अनुचित रुप से बढ़ी है ।

सियालदह–डायमंड हार्बर लक्ष्मीकांतपुर लाइन (सियालदह डिवीजन) पर समाज-विरोधी तत्व

6864. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पूर्व रेलवे की सियालदह डिवीजन में सियालदह–डायमंड हार्बर, लक्ष्मीकांतपुर लाईन पर समाज विरोधी-तत्व बहुत अधिक सक्रिय है;

(ख) क्या ये समाज-विरोधी लोग यात्री डिब्बों में घुस कर यात्रियों से दिन-दहाड़े उनका रुपया पैसा छीन ले जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकने तथा यात्रियों को पुनः विश्वस्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इस खण्ड में दिन के समय यात्रियों को सम्पत्ति की लूट/ डकैती के कुछ मामले हुए हैं। इस समस्या पर पश्चिम बंगाल की सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है और इनके द्वारा किये गये उपायों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में एसे मामले की संख्या 1972 में 41 से घट कर 1973 में 26 हो गयी।

(ग) अपराध नियंत्रण के पुराने तरीकों के अलावा राज्य पुलिस प्राधिकारियों ने जो स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की रोक थाम के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाये हैं :—

(1) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कुख्यात अपराधियों को हिरासत में लिया जा रहा है।

(2) रात को चलने वाली सवारी गाडियों में रक्षा के लिए पुलिस के साथ चलने की यथासंभव व्यवस्था की जाती है।

(3) जघन्य अपराध के महत्वपूर्ण मामलों में जांच-पड़ताल करने का काम राज्य सरकार के खुफिया विभाग के नियंत्रण में होता है।

(4) विशेष रेलवे आसूचना कक्ष के कर्मचारी अपराधियों की गतिविधियों को सुराग लगाते है और उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं।

राज्यों के समक्ष बिजली सप्लाई की कमी की स्थिति

6865. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री राज्यों के समक्ष बिजली सप्लाई की कमी की स्थिति के बारे में 19 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक प्रत्येक राज्य ने प्रत्येक माह बिजली की कुल कितनी-कितनी कमी का सामना किया; और

(ख) क्या इस मामले से युद्धस्तर पर निपटने के सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने पर भी बिजली की निरन्तर कमी चल रही है;

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) बहुत से राज्यों को विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विद्युत की उपलब्धता उसकी मांग की अपेक्षा कम है जब कि इस स्थिति से निपटने के लिए, जिसमें विद्युत ताप केन्द्रों से विद्युत उत्पादन को अधिकतम करना एवं अंतर्राज्यीय विद्युत विनिमय करना शामिल है, बहुत से उपाय हाथ में लिए गए हैं। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को चालू करके ही इस कमी को दूर किया जा सकता है। इसमें समय लगता है परन्तु इसमें यथासंभव तेजी लाई जा रही है।

विवरण

अगस्त-दिसम्बर 1973 के दौरान महसूस की गई विद्युत की कमी

(मिलियन यूनिटों में)

राज्य	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा . .	3.10	3.00	..	51.00	37.82
पंजाब . .	..	9.90	..	16.20	63.24
उत्तर प्रदेश . .	155.00	180.00	186.00	210.00	120.91
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश . .	46.50	36.00	31.00	14.10	2.48
कर्नाटक . .	31.00	41.10	62.00	66.00	66.96
तामिलनाडु .	..	79.80	62.00	101.10	50.14
पूर्वी क्षेत्र					
प० बंगाल . .	25.42	37.50	38.75	29.10	88.35
दामोदर घाटी निगम	13.95	..	30.69	..	16.42

आल इण्डिया अलेम्बिक एम्पलाईज फेडरेशन से ज्ञापन

6866. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आल इंडिया अलेम्बिक एम्पलाइज फैडरेशन, सोमानी भवन, स्टेशन रोड, जैयपूर 6 से 8 सितम्बर 1973 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें कम्पनियों के अलेम्बिक ग्रुप के विरुद्ध अत्याचार, कुप्रबन्ध तथा श्रमिक विरोधी आचरण के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित बातों का सारांश क्या है; और

(ग) उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) आल इण्डिया अलेम्बिक एम्पलाईज फैडरेशन से दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) फैडरेशन ने साथ साथ आरोप लगाया है कि अलेम्बिक कैमिकल वर्क्स कम्पनी लि० एवं अलम्बिक ग्लास इन्डस्ट्रीज लि० के ऊपर नियंत्रण होने से श्री रमनभाई एवं उसके पारिवारिक सम्बन्धी (1) सहायक कम्पनियां खोल रहे है, (2) इन दोनों कम्पनियों के धन को अन्य कम्पनियों जिनमें उनक हित हैं, मे लगा रहे है, (3) अपने सम्बन्धियों की फर्मों के माध्यम से अधिक मूल्य पर, बिना टेंडर आमंत्रित किए, कच्चे माल की खरीद करना, एवं (4) कच्चे माल, सत्र व औद्योगिक लाइसेंस को नई स्थापित कम्पनियों को व्यवर्तन कर देना।

(ग) 1970 में प्राप्त कुछ परिवादों के आधार पर अलैम्बिक कैमिकल वर्क्स कम्पनी लि० एवं अलैम्बिक ग्लास इन्डस्ट्रीज लि० की लेखा-बहियों का निरीक्षण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत हाथ में लिया गया था। फैडरेशन द्वारा अब आन्दोलित कुछ विनिर्देशों की निरीक्षण के समय जांच कर ली गई थी। फैडरेशन द्वारा अब उठाये गये कुछ अन्य विनिर्देश जिन पर उक्त निरीक्षण के दौरान जांच नहीं हुई थीं पर अब जांच की जायेगी।

फैडरेशन ने माननीय श्रम, रोजगार एवं पुनर्वास मंत्री महोदय को, अलैम्बिक कैमीकल वर्क्स कम्पनी लि० द्वारा की गई आरोपों युक्त, श्रमिकों के विरुद्ध प्रक्रियाओं की बाबत, दिनांक 1-9-73 का एक अभ्यावेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

फैडरेशन के दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 के ज्ञापन में दी गई श्रमिकों के विरुद्ध प्रक्रियाओं के आरोपों से युक्त सम्बन्धित विनिर्देशों का उद्धरण भी श्रम मंत्रालय को भेजा जा रहा है।

आल इण्डिया स्विचमैन एण्ड लीवरमैन एसोसिएशन, धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) का बीमारी के आधार पर बड़ी संख्या में छुट्टी लेने का आन्दोलन

6867. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल अथारिटी, धनबाद द्वारा ऐसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ, उनकी मांगों के बारे में बातचीत करने से इन्कार किये जाने पर आल इंडिया स्विचमैन एण्ड लीवरमैन एसोसिएशन धनबाद डिवीजन पूर्वी रेलवे ने 1 दिसम्बर, 1973 से 8 दिसम्बर 1973 तक बीमारी के आधार पर बड़ी संख्या में छुट्टी लेने सम्बन्धी आन्दोलन चलाया गया था।

(ख) यदि हां, तो अधिकांश रेल कर्मचारियों की एसोसिएशन/कौंसिल के बारें में सरकार की नीति क्या है;

(ग) धनबाद डिलीजन में स्विचमैनों और लीवरमैनों की कुल संख्या कितनी है और उपरोक्त आन्दोलन में कितने कर्मचारी भाग ले रहे है; और

(घ) सम्बन्धित मांग पर क्या कार्यवाही की गई है और प्रादेशिक सेना को तैनात करने अन्य डिवीजनों से कर्मचारी प्रतिनियुक्त करने और वफादार श्रमिकों को पुरस्कार देने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) धनबाद मंडल के स्विचमैनों और लीवरमैनों ने सितम्बर, 1973 में मंडल अधीक्षक, धनबाद को एक ज्ञापन दिया था। 26-10-73 को वे मंडल अधिकारियों से मिले भी थे। जब उनकी मांगों पर कार्रवाई की जा रही थी, कर्मचारियों ने 1-12-1973 से रेल का काम ठप्प कर देने की धमकी दी। उन्हें 29-11-73 को मंडल कार्यालय में बातचीत के लिए आने को कहा गया। दुर्भाग्यवश वे पहुंच नहीं पाये और इसकी बजाय 1-12-73 से सामूहिक रूप से बीमार होने की रिपोर्ट कर दी।

गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों सहित किसी भी स्रोत से आने वाले अभ्यावेदनों पर समुचित विचार किया जाता है और उस पर जो कार्रवाई उपयुक्त समझी जाती है, की जाती है।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठि की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय रेलवे में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और आस्टेरिटी टाइप प्राइमरी स्कूल

6868. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कितने हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और आस्टेरिटी टाइप स्कूल कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इन स्कूलों के स्थापना स्थलों का राज्यवार/जोनवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 31-3-1973 को भारतीय रेलों पर 54 उच्च/उच्चतर माध्यमिक, 33 मिडिल, 116 परम्परागत प्रारंभिक एवं 545 कम खर्चीले प्रारंभिक विद्यालय थे।

(ख) रेलवे विद्यालयों के विवरण निम्न प्रकार हैं :--

रेलवे	रेलवे विद्यालयों की संख्या			
	उच्च/उचतर माध्यमिक विद्यालय	मिडिल स्कूल	प्रारंभिक विद्यालय	
			परम्परागत	कम खर्चीले
मध्य . . .	1	1	10	38
पूर्व . . .	6	7	12	109
उत्तर . . .	2	कुछ नहीं	4	95
पूर्वोत्तर .	3	,,	3	49
पूर्वोत्तर सीमा . . .	7	,,	2	40
दक्षिण .	5	5	11	22
दक्षिण पूर्व . . .	14	9	25	94
दक्षिण मध्य . . .	6	10	5	26
पश्चिम . . .	5	1	26	72
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना .	4	कुछ नहीं	14	कुछ नहीं
डीजल रेल इंजन कारखाना .	1	,,	4	,,

नोट : सूचना रेलवे-वार रखी जाती है, राज्य-वार नहीं। राज्य-वार सूचना इकट्ठी करने में बहुत समय और श्रम लगेगा।

Assurance given on under-ground bridge/over-bridge at Motihari station (N.E. Railway)

6869. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether in his speech on Railway Budget he had given an assurance to the effect that either an underground bridge or an over-bridge would be constructed at Motihari station on North-Eastern Railway; and

(b) if so, the time by which the construction work is likely to commence?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Yes; according to the extant procedure, the proposals for construction of road over/under bridges in replacement of existing busy level crossing are to be sponsored by the State Government/Road Authority together with an undertaking to bear their share of cost. The Government of Bihar have already proposed construction of two road over-bridges, one on either side of Motihari Station, in replacement of existing level crossing No. 159 between Motihari Court and Motihai and No. 163 between Motihari and Semra stations. Estimates for both these works have been submitted by the North Eastern Railway Administration to the State Public Works Department for acceptance. Further action can be taken by the Railway only after the estimates are accepted by the State Government indicating the year in which the State Government would be able to allocate funds towards their share of the cost as well as take up their portion of the work on approaches.

As far as the question of a through foot over-bridge at Motihari station is concerned, the cost of the additional facility so required for the general public to cross from one side of the yard to the other is to be borne by the local Civil authority according to extant rules. No such proposal has been received by the Railway so far.

Scheme for even Power Production and Uniform Rates of Electricity Charges

6870. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state whether any scheme is being drawn up by Government to ensure an even power production and uniform rates of electricity charges in various parts of the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): No, Sir.

Petrol and Kerosene oil supplied to various States

6871. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the quantity of petrol and kerosene oil supplied to various States by the Central Government in 1973 and upto 23rd March, 1974, separately;

(b) whether Government have fixed any price for its sale to general public by various States;

(c) if so, the broad outlines thereof; and

(d) the extent to which sale at fixed price has been enforced?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Actual despatches of kerosene oil to different States during 1973 and allocations made during January to March 1974 are attached. [*Placed in Library. See No. L.T.*6714/74.] State-wise statistics about supplies of Motor Spirit (Petrol) are not maintained.

(b) to (d) Government lays down from time to time the basic ceiling selling prices of Bulk Refined Petroleum Products (including motor spirit and kerosene) ex oil companies storage/refinery points. The oil companies detemine retail selling

prices on the basis of the norms laid down, taking into account rail/road freight, dealer's/agent's commission, sales tax, octroi local levies etc. The State Governments/Union Territory Administrations determine and enforce the selling prices of kerosene statutorily under the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970 under the Essential Commodities Act, 1955. There is no statutory control on the retail selling price of petrol. Cases of overcharging in the case of kerosene oil can be taken up by State Governments under Essential Commodities Act. No information is maintained regarding the extent of sale at fixed prices.

गत तीन वर्षों के दौरान बंगाल को सिंचाई के लिये सहायता

6872. **श्री एस०एन० सिंह देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा योजना-वार पश्चिम बंगाल को सिंचाई के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) किन योजनाओं में अब तक पूरी स्वीकृत राशि नहीं लगाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) चतुर्थ योजना में राज्यों को सम्पूर्ण केन्द्रीय वित्तीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी गई थी और यह किसी विशेष परियोजना अथवा विकास शीर्ष के लिए नहीं थी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास बेकार पड़े हुये जनित्र एकक

6873. **श्री ई० वी० विख पाटिल** :

प्रो० मधु दण्डवते :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड के पास 56 जनित्र एकक बेकार पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इन एककों को प्रभावी रूप से उपयोग में लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से पता चला है कि उनके पास 56 पुरानी व अप्रचलित लघु विद्युत् जनन यूनिटें हैं जिनमें 300 कि० वा० का एक बाष्प टर्बो विद्युत जनन सेट और 55 लघु डीजल उत्पादन सेट हैं और इनका बोर्ड द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का यह विचार है कि अब इन सेटों की न तो मरम्मत की जा सकती है और न ही इनका प्रचालन किफायती तौर से किया जा सकता है। अत: राज्य बिजली बोर्ड इन सेटों को राज्य सरकार की स्वीकृति से बेच रहा है। इनमें से पांच पहले ही बेचे जा चुके हैं ।

विद्युत के प्रजनन और वितरण को केन्द्रीय नियंत्रण में लिया जाना

6874. **श्री एस० एन० मिश्र** :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् प्रजन और वितरण को केन्द्रीय नियंत्रण में लिये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किन राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और किन ने विरोध किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत सरकार देश में विद्युत् आपूर्ति उद्योग को युक्तिसंगत बनाने एवं उसके पुनर्गठन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों के प्रयासों के, मूलतया, पूरक के रूप में विद्युत् जनन केन्द्रों को स्थापित करने में केन्द्र की भूमिका की परिकल्पना की गई है । विद्युत् वितरण राज्य सरकारों के अधीन यथावत रहेगा ।

(ख) बिजली की अधिक आवश्यकता अनुभव करने वाले राज्यों में बिजली की कमी को समाप्त करने और किफायती ढंग से विद्युत् जनन सुविधाओं का बृहत् पैमाने पर निर्माण करने में विद्युत् प्रणालियों के समेकित प्रचालन के अनुपूरक केन्द्रीय विद्युत् जनन से बड़ी सहायता मिलेगी ।

(ग) इस मामले में राज्यों से परामर्श किया जा रहा है ।

हरदुआगंज तापीय बिजली घर को क्षति

6875. **श्री धामनकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि जानबूझ कर लापरवाही करने और आधुनिकतम मशीनों को ठीक प्रकार से न चलाये जाने के कारण हरदुआगंज तापीय बिजली घर में अधिकांश खराबियां पैदा होती है और बिजली बन्द होती है ;

(ख) क्या दिल्ली का अत्यधिक अर्हता प्राप्त इंजीनियरों का एक दल इस बिजलीघर को पहुंची क्षति का अनुमान लगाता रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के सलाहकारों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज ताप विद्युत् केन्द्र का दौरा किया था, के विचार से विद्युत् केन्द्र में बिजली उत्पादन बन्द होना और उनमें खराबियों का कारण अधिक परिष्कृत मशीनों को ठीक प्रकार से न चलाये जाना और जान-बुझकर लापरवाही बरतना नहीं कहा जा सकता है ।

(ख) और (ग) मजबूरन बन्द किये जाने के उपरांत केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के वरिष्ठ अभियंताओं ने 15 मार्च, 1974 को विद्युत् केन्द्र का दौरा किया था । उन्होंने सूचित किया है कि यह केन्द्र ऐश पम्प हाऊस में अनजाने अधिक राख भर जाने के कारण बन्द हुआ था । विद्युत् केन्द्र के पुनः प्रचालन हेतू विभिन्न उपायों को, जिनमें केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के सुझाव भी शामिल हैं, तत्परता के साथ कार्यान्वित किया जा चुका है ।

औषध उद्योग में उत्पादन पर आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्युटिकल्स प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया के सुझाव

6876. **श्री धामनकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है कि नये कारखाने स्थापित करने तथा विद्यमान कारखानो का विस्तार करने के सम्बन्ध में परिष्कृत लाइसेंस नीति को ध्यान में रखते हुए औषध निर्माण उद्योग अपने अनिवार्य निर्यात लक्ष्य को पूरा करे ;

(ख) क्या आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटीकल प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया ने उत्पादन में बाधक प्रतिबन्धों को हटाने की आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया के सुझावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वर्तमान आयात व्यापार नियंत्रण निति में उद्योग के लिये 5% की अनिवार्य निर्यात पाबन्दी की व्यवस्था है। लेकिन यह पाबन्दी छोटे पैमानेके यूनिटों तथा अन्य यूनिटों जिन्होने उत्पादन में 5 वर्ष पूरे नहीं किये हैं, पर लागू नहीं होगी। उन यूनिटों जो अपने उत्पादन के 5% से कम का निर्यात करते हैं, पर वर्ष 1974–75 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण और नीति जिल्द 1 के परिशिष्ट 10 के अनुबन्ध में दर्ज उत्पादों के निर्माण के लिये अपेक्षित आयातित कच्चे माल के लिये उनकी हकदारी पर कटौती लगाई जाति है। यह कटौति इस उद्योग में अन्य अन्तिम उत्पादों के लिए अपेक्षित कच्चे माल पर लागू नहीं होगी । तथापि, इन उद्योग का कोई यूनिट अपने उत्पादन का कम से कम 10% का निर्यात करने में असमर्थ है तो वह सपलाई के तरजीही संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं का आयात करने का हकदार नहीं होगा ।

(ख) और (ग) ओ० पी० पी० आई को सम्मिलित करते हुए विभिन्न संस्थाओं ने इस उद्योग के कार्यकरण में सुधार करने के संबंध में सुझाव दिये हैं। अपनी औद्योगिक नीति की रुपरेखा के अन्तर्गत सरकार उन बाधाओं जिन से उत्पादन में रुकावट होती है, को दूर करने का सतत प्रयत्न करती है ।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स के गोदाम से इस्पात के पाइप की चोरी के मामले की जांच

6877. श्री प्रबोध चन्द्र :

श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने "हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल" के गोदाम से इस्पात के पाइप चोरी हो जाने के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) इस चोरी के कारण कुल कितनी हानि हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) लगभग 1.5 लाख रुपये ।

भारतीय तेल निगम द्वारा विद्युत प्रजनन के लिये नई किस्म के इंधन तेल की सप्लाई

6878. श्री प्रबोध चन्द्र :

श्री राम प्रकाश :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा सप्लाई किये गये नये भट्टी तेल से विद्युत् मशीनरी को क्षति पहुंची है और इसके परिणास्वरूप देश के कुछ भागों में विद्युत प्रजजन कार्य को धक्का पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) ताप-विद्युत् केन्द्र चालू करने एवं लपटों के स्थिरीकरण हेतु एल० डी० ओ०/फर्नेस तेल को गौण ईंधन के रूप में प्रयोग करते थे। इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए फर्नेस तेल में 500–600 रेडवुड सेकण्ड की विस्कासिता होती है। अपेक्षित विस्कासिता के फर्नेस तेल की अनुपलब्धता के कारण भारतीय तेल निगम (आई० ओ० सी०) 1500 रेडवूड सैकेण्ड विस्कासिता वाला फर्नेस तेल सप्लाई कर रहा है। इस उच्चतर विस्कासिता वाले फर्नेस तेल के प्रयोग में कुछ समंजन एवं अतिरिक्त हैंडलिंग सुविधाओं की आवश्यकता होती है। बहरहाल, इसके प्रयोग से विद्युत् उत्पादन मशीनरी को हुई किसी हानि की सूचना नहीं मिली है। विद्युत् उत्पादन पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

मार्च, 1974 में बिहार में उपद्रवों के कारण गाड़ियां बन्द किया जाना

6879. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

श्री तरुण गोगोई :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1974 में बिहार में उपद्रवों को दृष्टि में रखते हुए पूर्व रेलवे ने 13 अप अपर इंडिया एक्सप्रेस सहित अनेक गाड़ियां बन्द कर दी थीं ;

(ख) यदि हां, तो गाड़ियां कितने समय तक बन्द रहीं ;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे पुलिस तथा सुरक्षा दल के कर्मचारियों की सहायता से गाड़ियां चलाने का निर्णय किया था, परन्तु वह व्यर्थ रहा ;

(घ) बिहार में उपद्रवों के दौरान कितनी गाड़ियों पर हमला किया गया ; और

(ड.) गाड़ियां सामान्य रूप से पुनः कब से चलाई गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) बिहार में उपद्रवों के कारण पूर्व रेलवे पर कुछ विशेष शाखा लाइन गाड़ियों के अलावा 13 अप अपर इण्डिया एक्सप्रेस सहित 7 जोड़ी डाक एक्सप्रेस गाड़ियों को 19-3-1974 से 24-3-1974 तक किसी-किसी दिन रद्द कर दिया गया था।

(ग) जी नहीं। रेलवे सुरक्षा दल के साथ गश्ती स्पेशलें चलाकर तथा अन्य सुरक्षात्मक ऊपायों से महत्वपूर्ण सेवाएं चालू रखी गयीं और सुरक्षा सुनिश्चित की गयी।

(घ) 29 गाड़ियां।

(ङ) 26-3-1974 से।

एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार, प्रक्रिया आयोग द्वारा 'हिन्दुस्तान टाइम्ज' और 'टाइम्ज आफ इण्डिया' को जारी किये गए नोटिस

6880. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री निहार लास्कर :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने 'हिन्दुस्तान टाइम्ज' को कथित निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं हेतु नोटिस जारी किए हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या पहले ऐसे नोटिस कुछ अन्य कम्पनियों को, जैसे 'टाइम्स आफ इण्डिया' आदि को भी दिए गए थे,

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य बातें क्या हैं, और

(घ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (घ) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

विवरण-पत्र

एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने 'टाइम्स् आफ इण्डिया' तथा 'हिन्दुस्तान टाइम्स्' के दो वाचकों से दो, अलग अलग शिकायतें प्राप्त हुई थीं । टाइम्स आफ इण्डिया, बम्बई से सम्बन्धित शिकायत में कहा गया था कि इसके प्रकाशक मे० बेनेट कालमैन एण्ड कम्पनी, अपने नियमित सैटरडे टाइम्स् आफ इण्डिया सहित, अपने 'टाइम्स् विकली' की 'संयोजित बिक्री' जैसी प्रथा में निरत है । इस प्रकार सैटरडे 'टाइम्स आफ इण्डिया' के नियमित खरीददारों को, टाइम्स् वीकली के लिये 12 पैसे अतिरिक्त देने पड़ते हैं ।

दिल्ली के एक वाचक से भी इसी प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई थीं, जहां यह कहा गया था कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स के वाचकों को भी हिन्दुस्तान टाइम्स के रविवारीय संस्करण सहित, 'सन्डे वर्ल्ड मैगजिन' के लिये अदायगी करना अपेक्षित है, जबकि पिछली मैगजिन की कीमत अलग से 12 पैसे है ।

इन दो शिकायतों के प्राप्त होने पर, मै० बैनट कालमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई तथा मै० हिन्दुस्तान टाइम्स लि०, दिल्ली को, आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की बाबत अपनी टिप्पणियां देने की मांग करते हुए, दो पत्र प्रेषित किए गए थे । इस प्रकार आयोग द्वारा इन दोनों कम्पनियों को कोई नोटिस नहीं भेजा गया था ।

टाइम्स आफ इण्डिया से प्राप्त उत्तर के पश्चात, इसके प्रतिनिधि, 28 मार्च, 1974 को आयोग से मिले थे, एवं उन्होंने यह मान लिया कि 'टाइम्स आफ इण्डिया' एवं 'टाइम्स वीकली,' दो भिन्न अखबार हैं, एवं उनकी बिक्री एक साथ नहीं की जा सकती । उनके विचार से किसी वाचक को दोनों पत्र खरीदने को विवश नहीं किया गया था ।

तथापि उन्होंने सम्पूर्ण देश में अपने एजेंटों एवं बम्बई में समाचार-पत्र हाकर्स की संस्था को यह अनुदेश देना स्वीकार कर दिया था कि वे वाचक को दोनों पत्र साथ-साथ बेचने को विवश न करें । उन्होंने अपने एजेंटों को दोनों अखबारों के लिए अलग-अलग ग्राहक बिल बनाने का सुझाव देना भी मान लिया था । ये भी स्वीकार कर लिया था कि 'टाइम्स आफ इण्डिया' तथा 'टाइम्स वीकली', में इस आशय की घोषणा भी कर दी जायेगी ।

इस अनुबंध के अनुसरण में मै० बैनट कालमैन एण्ड कम्पनी लि० ने दिनांक 1 अप्रैल, 1974 को अपने सभी एजेंटों को एक परिपत्र भेजा था ।

कम्पनी ने टाइम्स आफ इण्डिया, बम्बई के दिनांक 7 अप्रैल, 1974 के रविवार प्रेषण एवं टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली के दिनांक 9 अप्रैल, 1974 के मंगलवार प्रेषण में घोषणा प्रकाशित कर दी है ।

क्या कोई घोषणा टाइम्स आफ इण्डिया व टाइम्स वीकली मैगजिनों के अहमदाबाद प्रेषण में भी की गई है, का पता नहीं है। यदि इन पत्रों में भी ये घोषणायें कर दी गई हैं, तो आयोग की ओर से इस विषय में आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

हिन्दुस्तान टाइम्स की टिप्पणीयां आयोग को 29 मार्च, 1974 को प्राप्त हुई थी। इस समाचार-पत्र के प्रतिनिधि आयोग से 16 अप्रैल, 1974 को मिलने वाले हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रुमानिया से तेल की खुदाई करने वाले रिंगों को खरीदना

6881. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

श्री तरुण गोगोई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने रुमानिया सरकार से तेल की खुदाई करने वाले रिंगों को खरीदने का आग्रह किया है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई समझोता हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंन्धी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रुमानिया के प्रदापकों को 6 ड्रिलिंग तथा 3 'वर्कओवर' के रिंगों की खरीद के लिये आर्डर दे दिये गये है।

रेलवे जोनों का गठन और रेलवे सेवा आयोगों के मुख्यालय

6882. श्री चन्दु लाल चन्द्राकर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे इंजीनों का गठन किस आधार पर किया जाता है और रेलवे सेवा आयोग के मुख्यालय किस आधार पर नियत किये जाते हैं ;

(ख) इस समय कौन-कौन से रेलवे जोन है और रेलवे सेवा आयोगों के मुख्यालय कहां-कहां पर हैं और उनके अधीन कितनी लम्बी रेलों का प्रबन्ध है ;

(ग) प्रत्येक रेलवे जोन और रेलवे सेवा आयोग के अन्तर्गत कितने-कितने मीटर रेलवे लाइने हैं ;

(घ) मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व रेलवे की लम्बाई कितनी है ; और

(ङ.) मध्य प्रदेश में रेलवे जोन न बनाने और रेलवे सेवा आयोग का कोई मुख्यालय न बनाने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) परिचालनिक आवश्यकता और प्रशासनिक कुशलता के आधार पर रेलवे क्षेत्रों का गठन किया गया था। रेल सेवा आयोगों का मुख्यालय निश्चित करते समय उस क्षेत्रीय रेलवे को ध्यान में रखा जाता है जिसकी आवश्यकताएं उसे पूरी करनी होती हैं।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय रेलों और उनके मुख्यालयों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

क्षेत्रीय रेलवे का नाम	मुख्यालय	मार्ग किलोमिटर
1. मध्य .	बम्बई	6,013
2. पूर्व .	कलकत्ता	4,299
3. उत्तर .	नयी दिल्ली	10,687
4. पूर्वोत्तर	गोरखपुर	4,977
5. पूर्वोत्तर सीमा . .	मरलीगांग/गुवाहाटी	3,628
6. दक्षिण	मद्रास	7,452
7. दक्षिण मध्य	सिकन्दराबाद	6,175
8. दक्षिण पूर्व .	कलकत्ता	6,842
9. पश्चिम . . .	बम्बई	10,147

रेल सेवा आयोगों और उनके मुख्यालयों के नाम और विभिन्न आयोग जितनी दूरी तक की रेलवे के लिए काम करते हैं, उसका उल्लेख सन्निधान के अनुसार नीचे दिया गया है :—

रेल सेवा आयोग का स्थान	सम्बन्धित रेलवे और मार्ग किलोमिटर	
1. इलाहाबाद	उत्तर और डीज़ल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी	10,687
2. बम्बई	मध्य, पश्चिम और दक्षिण मध्य रेलवे का शोलापुर मण्डल	16,971
3. कलकत्ता	पूर्व, दक्षिण-पूर्व और चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन	11,141
4. मद्रास	दक्षिण, दक्षिण-मध्य (शोलापुर मण्डल को छोड़कर और सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर (मद्रास)	12,816
5. मुज़फ्फरपुर .	पूर्वोत्तर	4,977

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की आवश्यकताओं के लिए, इस समय गुवाहाटी में ही सेवा आयोग के अनुरूप एक भर्ती समिति काम कर रही है।

दक्षिण मध्य रेलवे के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सिकन्दराबाद में एक अलग रेल सेवा आयोग की स्थापना करने का विचार है।

(घ) मध्य प्रदेश में दक्षिण-पूर्व रेलवे की लम्बाई 1,993 मार्ग किलोमिटर है।

(ड़) मध्य प्रदेश का कोई रेलवे क्षेत्र नहीं है क्योंकि रेलवे क्षेत्रों का गठन राज्य की सीमाओं के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक और परिचालनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। इसी तरह से हर राज्य में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भी नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा, रेल सेवा आयोग न केवल आयोग के मुख्यालय में बल्कि उन सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कार का आयोजन करते हैं जहां से उम्मीदवार अपना आवेदन-पत्र भेजते हैं।

प्रभागीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता समितियों में छात्रों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व

6883. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रभागीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता समितियों में विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के छात्रों और शिक्षकों को प्रतिनिधित्व देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों/परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन रेल उपयोगकर्ताओं के विभिन्न सर्वमान्य दलों, अर्थात् चेम्बर्स आफ कामर्स, व्यापार संघों, उद्योगों, कृषि संघों, यात्री संघों, राज्य सरकारों , राज्य विधान सभाओं और संसद् सदस्यों के यथा-व्यवहार्य अधिकतम प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर निर्भर करता है । ऐसे अन्य हितों को, जो इन निर्दिष्ट व्यवस्थाओं में नहीं आते, "विशेष हित" के अन्तर्गत नामित किया जाता है । इन में शैक्षणिक संस्थाओं सहित जनता के अलग-अलग वर्ग होते हैं ।

रेल उपयोग कर्ता सलाहकार समितियों/परिषद में छात्रों और अध्यापकों को विशिष्ट प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कांगड़ा घाटी रेलवे के लिये ज्वाली और गुलेर स्टेशनों के बीच वैकल्पिक मार्ग

6884. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि कांगड़ा घाटी रेलवे के लिये ज्वाली और गुलेर स्टेशनों के बीच वैकल्पिक मार्ग के निर्माण कार्य में शीघ्रता की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस नये मार्ग का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) 30 जून, 1975 ।

पांचवी योजना में जम्मू काश्मीर, पंजाब और हरियाणा के लिये विद्युत् परियोजनाओं की स्वीकृति

6885. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में पांचवीं योजना में सम्मिलित करने के लिए सरकार ने कौन-कौन सी जल एवं अन्य विद्युत् परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी हैं अथवा किन-किन पर विचार हो रहा है ; और

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और उनके पूरा होने की समयावधि क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6715/74**]

Loss suffered by Railways during disturbances in Bihar in March, 1974

6886. **Shri Shankar Dayal Singh:**

Shri Sukhdeo Prasad Verma:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the trains were mainly damaged in the violent agitations that were launched in Bihar in March, 1974;

(b) the number of Railway stations of Bihar damaged and the amount of loss incurred by Railways as a result thereof;

(c) whether he had toured those areas, for an on-the-spot study and if so, his reaction in regard thereto; and

(d) whether some political party also had a hand in causing damage to the Railway property in a planned manner and if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) 83 Railway Stations.

Rs. 9 lakhs approximately.

(c) No. However, the Minister of Railways, accompanied by Senior Officials of the Railway Board, visited Patna and discussed with the State Government the situation arising out of the agitation and measures to be adopted for safeguarding the Railways property and the employees.

(d) Not yet known.

Railway accident at Rajgir in Bihar on 6th March, 1974

6887. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a railway accident took place on the 6th March, 1974 at Rajgir in Bihar wherein 9 persons were killed; and

(b) if so, the causes of the accident and the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) An accident involving a light engine and a motor truck took place at level crossing gate No. 63-A between Rajgir and Biharsharif stations of the Eastern Railway on 5-3-1974. In this accident 10 persons travelling in the truck were killed.

(b) The cause of the accident is under investigation.

Charging of Re. 1/- for Car Parking at New Delhi Station

6888. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the reasons for charging Re. 1/- for parking of cars at New Delhi Railway Station; and

(b) the date from which this rule relating to car parking charges was made effective and the income accrued so far to the Railways on this account?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The parking fee is levied to discourage unauthorised parking of private vehicles in the station premises.

(b) This system has been introduced with effect from 1-7-1973. The value of the contract awarded is Rs. 1,51,000 for a period of two years.

जनवरी, 1974 में वैस्ट्रन कोसी नहर के उदघाटन पर हुआ खर्च

6889. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जनवरी, 1974 को ग्राम खोजपुर में बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा वैस्ट्रन कोसी नहर का उद्घाटन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उद्घाटन संबंधी हुई रैलो के कारण फसलों को हुई क्षति के लिए दिये गये मुआवजे-सहित इस उद्घाटन के लिए विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कुल कितना खर्च हुआ ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) शस्य प्रतिपूर्ति समेत विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत केवल 68,012 रुपये ही व्यय हुए हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 और 31 के कटाव का खतरा

6890. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे के मानसी जंक्शन के निकट गंगा द्वारा राष्ट्रीय राजपथ संख्या 21 और 31 के कटाव का खतरा है क्योंकि कटाव के स्थान से यह कुछ ही गज की दूरी पर है ;

(ख) क्या बिहार सरकार द्वारा नियुक्त बाढ़ नियंत्रण समिति ने आगामी वर्षा ॠतु के दौरान-राजपथ तथा रेलव जंक्शन को कटाव से बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने हेतु केन्द्रीय सरकार को एस० ओ० एस० भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) मानसी के निकट गंगा द्वारा कटाव की समस्या का अध्ययन करने और उपचारी उपायों की सिफारिश करने के लिए बिहार सरकार ने अक्तूबर, 1973 में एक तकनीकी समिति का गठन किया था । दिसम्बर, 1973 में राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने उल्लेख किया है कि राजपथ संख्या 31 और गंगा की मुख्य चनल के बीच न्यूनतम दूरी लगभग 125 मीटर है तथा राजपथ संख्या 31 और बूढ़ी गंडक नदी पर राजपथ, पूल, रेलव लाइन और खगरिया नगर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के शीघ्र कार्यान्वियन करने की सिफारिश की है ।

बिहार सरकार ने तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर गंगा द्वारा कटाव से मानसी के निकट क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 3.52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक स्कीम तयार की है । इसे गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा अब योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

राजपथ विभाग ने पहले ही एक अस्थायी व्यपवर्तन पूरा कर दिया है और कटाव द्वारा प्रभावित रोच में राजपथ संख्या 31 के स्थायी व्यपवर्तन हेतु भूमि अधिग्रहण कर चुका है । आवश्यकता पड़ने पर मुख्य संचार व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए, नदी से दूर एक रिटायर्ड एलायनमेंट भी रेलवे द्वारा पूण किया जा चुका है ।

राजपथ संख्या 21 मानसी स्टेशन के निकट नहीं है ।

बिहार में विद्युत जनित्र संयंत्रों का स्थापित किया जाना

6891. **श्री भोगन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा जिलों की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मधुबनी के निकट किसी विद्युत् जनित्र संयंत्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में तेल की खोज क लिये सोवियत संघ के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना

6892. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल की खोज तथा तेल शोधन कार्यों को विकसित करने के लिये हाल में ही सोवियत संघ के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के विशिष्ट उद्देश्य क्या है ;

(ग) विशेषज्ञों के नाम क्या है और इस मामले में विशेषज्ञों के रूप में उनकी अर्हताओं संबंधी तथ्य क्या है ; और

(घ) भारत में उनकी सेवाओं की शर्तें क्या है तथा देश में उन्हें जो सुविधायें मिलेगी, उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी हां ।

(ख) (i) भारत विभिन्न तलछटी बेसिन में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रत्याशित संचयों के अनुमान पर वज्ञानिक जांच कार्य करने तथा उन बेसिनों में अन्वेषण कार्य हेतु योजना तैयार करने के लिए सहायता हेतु ; और (ii) अशोधित तेल के उपयोग एवं इसके योगजों का शोधनशाला ईंधन के रूप में उपयोग; भारतीय तेल निगम के गोहाटी, बरौनी तथा कोयली परिष्करणशाला में शोधित अशोधित तेल की प्रक्रिया में हानि का अध्ययन करने हतु ; विशेषज्ञों की सेवाए की गए हैं ।

(ग) 15 विशेषज्ञों में से भारत में अभी तक केवल चार विशेषज्ञ आये । उनके विवरण निम्नलिखित ह :—

क्रम सं०	नाम एवं पद	विशेषज्ञ के रूप में अर्हताएं
1	श्री वी० पी० मोर्कवीच, भूविज्ञानक परामर्शदाता	भूविज्ञान तथा खन्जि विज्ञान में डाक्टर जिन्हें तेल उद्योग में 43 वर्ष का अनुभव है ।
2	श्री एस० वी० कुजनेट सोव, तेल एवं प्राकृतिक गस के प्रत्याशित संचय के अंकन पर भूविज्ञान परामर्शदाता	तेल उद्योग के क्षेत्र में 43 वर्ष का अनुभव ।
3	श्री एल० आई० मोरोजोव, हाइड्रो भूविज्ञान परामर्शदाता	हाइड्रो भूविज्ञान के क्षेत्र में 16 वर्ष का अनुभव के साथ हाइड्रो भूविज्ञान तथा तेल भूविज्ञान के क्षेत्र में उच्च-शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञ ।
4	श्री यू० एम० लवोव स्काइ, अन्वेषण कार्य हेतु योजना तैयार करने में भूविज्ञान परामर्शदाता	तेल उद्योग के क्षेत्र में 22 वर्ष का अनुभव सहित उच्च-शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञ ।

शेष 11 विशेषज्ञों, जिन्हें अभी भी भारत में पहुंचना है, के ब्यौरे अभी रूसी अधिकारियों से प्राप्त नहीं हुये हैं।

(घ) निशुल्क सुसज्जित आवास, निशुल्क मार्ग व्यय, निशुल्क चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त रूसी विशेषज्ञों को 391 रूबल से 638 रुबल तक भिन्न भिन्न वेतन देय है। विभिन्न विशेषज्ञों का नियत कार्य अवधि 45 दिन से 2 वर्ष के समय तक भिन्न भिन्न है।

1976-77 में होने वाले साधारण निर्वाचनों में अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन-जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की शर्तें

6893. श्री शंकरराव सावन्त : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए 1976 और 1977 में होने वाले साधारण निर्वाचनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थान आरक्षित करने की शर्तें कौन सी हैं; और

(ख) इन शर्तों से महाराष्ट्र में इन निर्वाचनों के लिए कौन-कौन से स्थानों के आरक्षित अथवा अनारक्षित घोषित किये जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबन्ध संविधान के अनुच्छद 330 और 332 तथा परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 9(i) (ग) और (घ) में हैं।

(ख) परिसीमन आयोग द्वारा महाराष्ट्र राज्य के संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अवधारण अभी नहीं किया गया है और अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि 1976 और 1977 के साधारण निर्वाचनों के लिए राज्य में कौन से निर्वाचन-क्षेत्र अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

कुकिंग गैस के सिलेण्डरों की कमी

6894. श्री शंकरराव सावन्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुकिंग गैस के संचय करने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले सिलेंडरों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी है और इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस उद्देश्य के लिए अनुमानित देशी इस्पात की उपलब्धता में कमी के कारण एल० पी० गैस के लिए सिलेंडरों की कुछ कमी रही है। एल० पी० गैस सिलेंडरों के निर्माण के लिए विशेष कोटि के इस्पात का प्रयोग किया जाता है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान अनुमानित आवश्यकता की अपेक्षा इस्पात उपलब्धता निम्नलिखित है :—

वर्ष	अनुमानित आवश्यकताएं	उपलब्धता
1972 .	12,500 मीटरी टन	9,722 मीटरी टन
1973 . .	12,500 मीटरी टन	10,933 मीटरी टन

(ग) 1973-74 के दौरान एल० पी० जी० सिलेंडरों के निर्माण के लिए 5,000 मी० टन इस्पात के आयात की अनुमति दी गई थी। देशी उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए 1974-75 में इस्पात के आयात करने का प्रस्ताव है।

रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन का प्रस्ताव

6895. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि यह दल न केवल यात्रियों के जान माल और रेलवे की रक्षा करने में बल्कि रेलवे में होने वाले अपराधों का पता लगाने के लिए प्रभावी माध्यम बन सके ; और

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा दल को ये कार्य सौंपने पर कोई आपत्तियां की गई हैं ; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) संविधान के अनुसार यात्रियों के जान माल की सुरक्षा का दायित्व सरकारी रेलवे पुलिस का है जो राज्य पुलिस का एक भाग है। इस प्रयोजन के लिए रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान रेल वैगनों तथा यात्री डिब्बे (कोचों) का निर्माण

6896. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान रेल के यात्री डिब्बे (कोचों) तथा माल डिब्बों (वैगनों) का कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ख) इन में से कितने डिब्बों का निर्यात किया गया और निर्यात किन-किन देशों को किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

डीजलीकरण के संबंध में खान मंत्रालय का प्रस्ताव

6897. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को खान मंत्रालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि डीजलीकरण के लिये पग न उठाये जायें ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) रेलवे की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हैं ?

रल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इंधन नीति समिति ने रेलों के बिजलीकरण की प्रगती पर विचार किया था और यातायात के घनत्व के अनुमानों को देखते हुए इसे उपयुक्त समझा था। लेकिन, समिति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि इंधन की बढ़ती हुई मांगो को ध्यान में रखते हुए, कर्षण उपस्कर और बिजली सप्लाई के उपलब्धता आदि पर बारीकी से विचार करना होगा और मुख्य मार्गों का जहां तक सम्भव हो अधिक से अधिक बिजलीकरण किया जाना चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

कार्यरत डीजल इंजन और उनका उत्पादन

6898. **श्री ए०के०एम०इसहाक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने नये डीजल इंजन रेलवे स्टाक में जोड़े गये ; और

(ख) देश में इस समय डीजल इंजनों का कितना उत्पादन होता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों में 395 डीज़ल रेल इंजनों की वृद्धि की गयी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	बड़ी लाइन	मीटरलाइन	छोटी लाइन
1971-72 .	84	29	10
1972-73 . . .	101	33	—
1973-74	99	39	—
(फरवरी '74 तक अनन्तिम) . .	284	101	10

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डीज़ल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन द्वारा डीज़ल रेल इंजनों का जितना उत्पादन किया गया वह इस प्रकार है :—

	मुख्य लाइन कै डीजल/ बिजली रेल इंजन		डीजल रेल इंजन	
	बड़ी लाइन	छोटी लाइन	बड़ी लाइन डीजल शंटर	छोटी लाइन डीजल रेल इंजन
	डीजल रेल इंजन कारखाने से		चितरंजन रेल इंजन कारखाने से	
1971—72 . . .	70	35	35	5
1972—73 . . .	60	35	46	—
1973—74 (अनन्तिम) . .	54	33	50	—

उत्पादन आंकड़ों में वे रेल इंजन भी शामिल हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए तैयार किये गये ।

गत तीन महीनों में सियालदह डिवीजन में रेल गाड़ी सेवाओं का अस्त-व्यस्त होना

6899. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में सियालदह डिवीजन में रेल गाड़ी सेवाएं कितनी बार अस्त-व्यस्त हुईं ;

(ख) कितनी रेल गाड़ी सेवाएं अस्त-व्यस्त हुईं ; और

(ग) सरकार ने इस अवधि के दौरान सियालदह स्टेशन से सामान्य रूप से गाड़ियां चलाने के लिए क्या कार्यवाही की और उसके अब तक क्या परिणाम रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) इकतीस बार।

(ख) औसतन हर बार 22 जोड़ी गाड़ियां ।

(ग) रेलवे सामानों की चोरी रोकने के लिए ताकि गाड़ी सेवाएं अस्त-व्यस्त न होने पायें, भेद्य स्थानों पर रेलवे सुरक्षा दल की टुकड़ियों तथा गश्त की व्यवस्था की गयी है और यथा संभव गाड़ियों में मार्ग रक्षियों की व्यवस्था भी की गयी हैं। रात्रि में पुलिस के साथ गश्त लगाने का काम चालू है। सियालदह और कुछ अन्य स्टेशनों पर सरकारी रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा दल के मजबूत दल तैनात किये गये हैं। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक और मुख्य सचिव की राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस मामले पर विचार किया गया था । समन्वित उपायों के अपनाय जाने के फलस्वरूप स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ।

सियालदह स्टेशन पर उपद्रवों के कारण गाड़ियों को बन्द करना

6900. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 मार्च, 1974 को सियालदह रेलवे स्टेशन पर उपद्रवों के कारण गाड़ियां बन्द किये जाने के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) उपद्रवों के कारण क्या थे और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ग) यदि कोई जांच की गई हो तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लगभग 37,000 रुपये ।

(ख) दमदम जंक्शन पर सिगनल केबुलों की चोरी के कारण, गाड़ियों को विलम्ब से चलाना पड़ गया था । परिणामस्वरूप सामान्य रेल सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गयीं और दमदम और सियालदह स्टेशनों के बीच समय सारणी में तालमेल समाप्त हो गया । इससे सियालदह स्टेशन पर यात्री क्रुद्ध हो गये जिन्होंने आंदोलन आरम्भ कर दिया और रेलवे कर्मचारियों से हाथा पाई की, साथ ही रेल सम्पत्ति को भी क्षति पहुंचायी । कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया ।

(ग) रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है और परिणाम की प्रतीक्षा है ।

गत 6 महीनों में पूर्वोत्तर रेलवे में दुर्घटनाएं

6901. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों में पूर्वोत्तर रेलवे में कितनी दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई ;

(ग) कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए ; और

(घ) घायलों तथा मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1-9-1973 से 28-2-1974 तक की अवधि में पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ियों की टक्कर होने, पटरी से उतरने, समपारों पर दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 27 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई ।

(ख) अनुमान है रेलवे सम्पत्ति को लगभग 94,000 रुपये की क्षति हुई ।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 3 व्यक्ति मारे गये और 10 व्यक्ति घायल हुए ।

(घ) इन दुर्घटनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । फिर भी घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है ।

आंध्र प्रदेश में पीथापुरम् से राजामुंद्री मुख्य लाइन को काकीनाड़ा होकर ले जाया जाना

6902. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीथापुरम् से राजामुन्द्री मुख्य लाइन को काकीनाड़ा, जो आंध्र प्रदेश में, समुद्री पत्तन वाला शहर है, होकर ले जाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस लाइन के मार्ग परिवर्तन के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से रेल मंत्रालय को एक प्रस्ताव मिला था ।

(ख) इस प्रस्ताव की जांच की गयी थी लेकिन इसका औचित्य नहीं पाया गया ।

आंध्र प्रदेश में रेलवे द्वारा माने गये पिछड़े क्षेत्रों के नाम

6903. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा आंध्र प्रदेश में कौन-कौन क्षेत्र पिछड़े हुए माने गये हैं ; और

(ख) इन क्षेत्रों को रेलवे मानचित्र पर रखने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय मलतः राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्णय को ही ध्यान में रखता है ।

(ख) 1974-75 में नडिकुडी से बीबीनगर तक एक नयी रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव है ।

दक्षिण मध्य रेलवे में बिना चौकीदार क रेलवे फाटक

6904. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे (साउथ सेन्ट्रल) में बिना चौकोदार के कितने रेलवे फाटक हैं ; और

(ख) ऐसे फाटकों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 'सी' दर्जे के बिना चौकीदार वाले 2051 समपार है ।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं में कमी करने के उद्देश से निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं :—

(i) रेल पथ को सावधानीपूर्वक पार करने में सड़क-उपयोगकर्ताओं को सचेत करने के उद्देश्य से रेलव सीमा के भीतर बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच-मार्गों पर रोक-पट्ट स्पष्ट रूप दिखायी देने वाले स्थानों पर लगाये गये हैं ।

(ii) सड़क उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त चेतावनी देने के रूप में सीटी पट्ट गाड़े गये हैं जिनमें यह आदेश दिया गया है कि जैसे ही गाड़ी बिना चौकीदार वाले समपार के पास पहुंचे, उस गाड़ी का ड्राइवर सीटी दे ।

(iii) राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि सभी बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर सड़क-संकेतों की व्यवस्था की जाय ।

(iv) मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने यह कानून भी बना दिया है जिसमें यात्री बसों के ड्राइवरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बिना चौकीदार वाले समपारों से पहले अपने वाहनों को रोकें और बस के कंडक्टर को आगे-आगे पैदल चलाकर रेलवे लाइन को पार किया जाय ।

(v) मोटर संघों आदि से अपीलों के रूप में सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा परक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से सैच्छिक अभियान भी चलाया जा रहा है ; तेज चलने वाले वाहनों के मालिकों/ड्राइवरों को पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से प्रादेशिक भाषाओं में इश्तहार बांटे जाते हैं; आकाशवाणी के ग्रामीण कार्यक्रम, सिनेमा स्लाइडों आदि के माध्यम से प्रचार किया जाता है ।

उन समपारों पर जहां सड़क और रेल दोनों का भारी यातायात होता है और/या दृश्य क्षेत्र सीमित होता है, यातायात की गणना के आधार पर या राज्य सरकार/सड़क अप्राधिकरण से अनुरोध प्राप्त होने पर, चौकीदार भी रखे जा रहे हैं जो एक सतत प्रक्रिया है ।

गाज़ियाबाद स्टेशन (उत्तरी रेलवे) पर कार्य करने वाले भारवाहक कुलियों के वेतन वृद्धि का बकाया

6905. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद स्टेशन (उत्तरी रेलवे) पर कार्य करने वाले कुछ भारवाहक कुलियों को वर्ष 1963 से वेतन वृद्धियों के बकायों का भुगतान नहीं किया गया है :

(ख) यदि हां, तो असाधारण विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय म उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Suspension of Drilling for Oil at Baramura

6906. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**

Shri Nihar Laskar :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether drilling for oil has been stopped at Baramura ; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps being taken by Government to resume drilling ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir. Drilling has only been held up due to some complications.

(b) Drilling has been held up, due to the drill string getting stuck on 8-3-1974. The same is being fished out and it is hoped that normal operations will be resumed shortly.

Generation of Power and Consumption in States during 1973-74

6907. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether power generation capacity has been lower than the power consumption during 1973-74; and

(b) if so, the main features of the power generation and power consumption, State-wise and the steps being taken by Government to make up the difference?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b) It is true that power generation was lower than the requirements in many States during 1973-74. A statement showing the average daily surplus/deficit of energy in the States in the different months during 1973-74 is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T. 6716/74.]

The following steps have been taken to make up the difference between the demand and availability to the extent possible :—

(i) The utilisation of existing power installations is being maximised by monitoring and arranging for supply and transport of coal and fuel oil, spare parts etc.

(ii) The programme of constructing inter-State lines and setting up of load-despatch stations is being expedited.

(iii) The projects which are nearing completion are being expedited to ensure early commissioning of the generating units.

(iv) Exchange of power between neighbouring States is being encouraged so as to achieve optimum utilisation of generating capacity.

तेल की खुदाई संबंधी "रिगस" की खरीद के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों का अमरीका का दौरा

6908. श्री राम सहाय पांडे : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों ने हाल में तेल की खुदाई संबंधी 'रिग्स' की खरीद के लिये अमरीका का दौरा किया था;

(ख) क्या ये अधिकारी वहां से इनकी कोई खरीद करने में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों का एक दल ड्रिलिंग रिगों तथा उपकरणों की खरीद करने के लिए अमरीका गया था। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० के चेअरमैन सहित दल ने भारत में इस प्रकार की रिगों का निर्माण करने के लिये उपयुक्त सहयोग की संभावनाओं के बारे में भी बात-चीत की थी। विनिर्माताओं के साथ की गई बात-चीत के परिणामस्वरूप, उन में से कुछ निर्माताओं ने ड्रिलिंग रिगों के लिये पेशकश देने तथा भारत में निर्माण करने के लिये उपयुक्त सहयोग करार करने के संबंध में बात-चीत करने के लिये भी अपनी इच्छा व्यक्त की है। कोटेशनों के निकट भविष्य में प्राप्त होने जाने की संभावना है।

रेलवे में भर्ती के लिये क्षेत्रीय आयोग

6909. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में रेलों में भर्ती के लिये क्षेत्रीय आयोगों की स्थापना का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सभी रेलों के लिए विद्यमान एक आयोग की व्यवस्था को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले युवकों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि इस तरह की योजना बनायी जाये कि एक रेल सेवा आयोग का अधिकार-क्षेत्र एक क्षेत्रीय रेलवे के क्षेत्राधिकार के समकक्ष रहे।

Setting up of a fertiliser plant at Singrauli in Madhya Pradesh

6910. **Shri Shri Krishna Agrawal :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to set up a new fertilizer plant based on the huge deposits of coal field at Singrauli in Sidhi District of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the time by which it is likely to be set up?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) At present no such proposal is under consideration of the Government.

(b) and (c) Do not arise.

Mining Industry in Madhya Pradesh facing wagon shortage

6911. **Shri Shri Krishna Agrawal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether due to non-availability of adequate number of railway wagons, the mining industry in Madhya Pradesh had to face great difficulties during the recent months;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the efforts made by the Railway Administration in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) Although Indian Railways have adequate number of railway wagons, their availability has been affected during the recent months due to reasons very often beyond the control of Railways. A spate of agitations by the railway staff and public, civil disturbances and bundhs in different parts of the country and industrial unrest have created an atmosphere of artificial scarcity of wagons.

(c) As soon as normalcy is restored, every endeavour will be made to meet the demands for wagons from the mining industry in Madhya Pradesh.

सम्भल-मुरादाबाद सड़क पर उपरि पुल बनाने का प्रस्ताव

6912. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्भल-मुरादाबाद सड़क पर एक उपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) मुरादाबाद में समपात्र नं० 417–स्पेशल की जगह ऊपरि सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव जून, 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार ने यह इच्छा भी प्रकट की थी कि प्रस्तावित पुल के पास ही एक नये समपात्र की भी व्यवस्था की जाये। प्रस्ताव के स्वरूप को देखते हुए राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि नियमों के अनुसार ऊपरि सड़क पुल का समूचा खर्च उसे वहन करना पड़ेगा। सारा खर्च वहन करने के संबंध में राज्य सरकार की स्वीकृति अभी नहीं मिली है।

मुरादाबाद में इंडियन आयल की निर्माणाधीन टंकी का टूट जाना

6913. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद में इंडियन आयल की एक टंकी उस समय टूट गई जब वह बनाई जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या टंकी बनाने में आयातित चद्दर (शीट) का प्रयोग करने के स्थान पर स्वदेशी चद्दर का प्रयोग किया गया और आयातित चद्दर गुम पाई गई; और

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, मुरादाबाद में 5–6–72 को इण्डियन आयल कारपोरेशन की भूमि के ऊपर दो टंकियां निर्माणाधीन अवस्था में टूट गईं।

(ख) 5–6–72 को आंधी और तूफान के कारण जो टैंक-वेल्डेड प्लेटें थीं वह टूट गईं और नष्ट हो गईं। ठेकेदार ने अपने खर्च पर टूटे हुए भाग को फिर से बनाया और उन्हीं शीटों का प्रयोग किया।

(ग) और (घ) टैंक के निर्माण के लिए आयात की हुई शीटें इस्तेमाल की गई थीं और इण्डियन आयल कारपोरेशन मुरादाबाद के डिपो अधीक्षक के नियंत्रण में थी। कोई भी शीट गुम नहीं हुई।

नेफ्था के मूल्य में वृद्धि होने के कारण कलकत्ता में पेट्रो-रसायन एककों को हो रही कठिनाइयां

6914. **श्री निहार लास्कर :**

श्री तरुण गोगोई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नेफ्था के मूल्य में वृद्धि के कारण कलकत्ता में पेट्रो-रसायन एककों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन उद्योगों की सहायता करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कलकत्ता में मूल पेट्रो-रसायन का उत्पादन करने वाला कोई एकक नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Report submitted by FCI to set up a Rock-phosphate based fertilizer factory in Rajasthan

6915. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Fertilizers Corporation of India has submitted its report on setting up of a rock-phosphate based fertilizer factory in Rajasthan; and

(b) if so, the decision taken by Government in regard to setting up of such a project?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) The Fertilizer Corporation of India has made no proposal for establishing a fertilizer factory in Rajasthan based on rock-phosphate. Any decision regarding the setting up a fertilizer complex in Rajasthan can be taken only on receipt of firm data on the economic availability of the basic raw materials like pyrites and rock-phosphate and essential utilities. The Feasibility Report on Saladipura pyrites deposits prepared by M/s. RTZ has been received. A Committee has been set up to evaluate the technical and other aspects of the development of the rock-phosphate mines in Jhamarkotra area of Rajasthan in the context of the Feasibility Report prepared by M/s. Parsons at the instance of the World Bank.

प्रत्येक उच्च न्यायालय में प्रशासकीय बैंच की स्थापना का प्रस्ताव

6916. श्री एम० सुदर्शन :
श्री राम प्रकाश :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के अपर महासालिसिटर के हाल ही के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें सेवा सम्बन्धी मामलों का निपटारा करने के लिये प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रशासकीय बैंच की स्थापना का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, हां ।

(ख) अपर महासालिसिटर द्वारा व्यक्त किया गया मत उनका निजी मत था और सरकार ने उसे नोट कर लिया है ।

चौथी योजना के दौरान केरल में ग्राम विद्युतीकरण

6917. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान केरल राज्य में हुआ ग्रामीण विद्युतीकरण पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु की जाने वाली ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चतुर्थ योजना के दौरान केरल राज्य में पर्याप्त ग्राम विद्युतीकरण कार्य किया गया है। यहां 1573 ग्राम हैं। 28-2-1974 तक 1368 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके थे। उर्जित पम्प सैटों की संख्या 37543 है।

(ख) पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, राज्य बिजली बोर्ड ने इस योजना के दौरान सभी ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव किया है।

गत दो वर्षों में केरल की सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं

[6918. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने गत दो वर्षों में राज्य में सिंचाई और विद्युत के विकास के लिए केन्द्र को कितनी बड़ी एवं मंझले सिंचाई योजनाएं और विद्युत योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) केन्द्र द्वारा स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) इस अवधि में इन स्वीकृत परियोजनाओं में से कितनी पूरी कर ली गई हैं और स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान अवस्था क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) गत दो वर्षों के दौरान केरल सरकार द्वारा एक बृहत् सिंचाई तथा पांच विद्युत स्कीमें प्रस्तुत की गई थीं। इनमें से अब तक दो विद्युत स्कीमें जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, स्वीकृत हुई हैं :—

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
सायलेंट बैरुलो जल विद्युत स्कीम . .	3×40	24.88
इदामलायार जल विद्युत स्कीम . . .	2×37.5	18.75

इन दो विद्युत स्कीमों पर कार्य प्रारंभिक अवस्था में है। इदामलायार परियोजना को प्रथम यूनिट के पांचवीं योजना के अंत तक चालू होने की संभावना है जबकि सायलेंट बैलों से लाभ छठी योजना में ही मिलने आरंभ होंगे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत राशि

6910. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा केरल की ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितना धन स्वीकृत किया गया;

(ख) राज्य के लिए 1974-75 पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वर्ष-वार कितने धन की स्वीकृति दी गई है; और

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान जिलेवार कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है और उनके राज्य बिजली बोर्डों के जरिये उनके राज्य योजना परिव्ययों में से कार्यान्वित किया जाता है। चतुर्थ योजना के दौरान केरल में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 4.5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए सरकारी उपक्रम ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अतिरिक्त ऋण सहायता दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य बिजली बोर्ड को निगम द्वारा स्वीकृत राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

लाख रुपयों में

1971–72	203.236
1972–73	214.640
1973–74	139.255

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में ग्राम विद्युतीकरण के लिए राज्य योजना में 25 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ग्राम विद्युतीकरण निगम से ऋण ले सकेगी। 1974–75 वर्ष तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान निगम से ऋण सहायता केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित और निगम द्वारा, उनके द्वारा विहित मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत स्कीमों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(ग) केरल में 1573 ग्राम हैं। इनमें से 28–2–1974 तक 1368 ग्राम विद्युतीकरण किए गए। केरल राज्य बिजली बोर्ड पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष सभी ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव रखता है।

केरल में पुलों एवं उपरि पुलों का निर्माण

6920. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा वर्ष 1973–74 में कितने नये उपरि-पुलों का निर्माण किया गया;

(ख) राज्य सरकार ने कितने उपरि-पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) सरकार का वित्तीय वर्ष 1974–75 में राज्य में नये पुलों और उपरि पुलों के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कोई नहीं।

(ख) वर्तमान समपारों के स्थान पर ऊपरि पुल बनाने के 19 प्रस्ताव इन पुलों पर होने वाला खर्च रेलवे और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा। दो प्रस्ताव निक्षेप निर्माण कार्य के रूप में हैं जिनका खर्च पूर्णतः राज्य सरकार/सड़क परिवहन द्वारा वहन किया जायेगा।

(ग) 1974–75 में केरल राज्य में ऊपरि सड़क पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में रेलों द्वारा अपने हिस्से के 2.60 लाख रुपये खर्च किये जाने की संभावना है।

केरल में काल्लदा सिंचाई परियोजना से भूमि की सिंचाई

6921. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में काल्लदा सिंचाई परियोजना के संबंध में और कितनी प्रगती हुई है;

(ख) इस परियोजना से क्विलोन जिले में कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई किये जाने की संभावना है; और

(ग) समय पर इस परियोजना को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल सरकारने सूचित किया है कि परप्पर में बांध का निर्माण हो रहा है और औट्टाकल में एक बियर तथा दक्षिण तट नहर शोर्ष नियामक का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि नहर कार्यों के लिए विस्तृत अनुसंधान भी लगभग पूरे हो गये हैं।

(ख) इस परियोजना से क्विलोन जिले में 52.600 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है।

(ग) केरल सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना की समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं।

Export of Cement in exchange of Oil

6922. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government of India propose to import oil from other countries in exchange of cement in view of the present petroleum and oil crisis; and

(b) if so, the salient features in this regard and whether the export of cement to other countries would not hamper construction work in the country?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) Cement is one of the commodities proposed for export under bilateral arrangements with some of the oil producing countries, but no final agreement has been reached so far in this regard.

It is, however, proposed to export 3 lakh tonnes of cement by the end of December, 1974 and another 5 lakh tonnes during 1975 to Iran as a part of bilateral trade negotiations between India and Iran. The indigenous availability of cement will be reduced to the extent it is exported. The impact on internal availability is proposed to be mitigated by better utilisation of the installed capacity and the creation of additional capacity in the country.

लोको रनिंग कर्मचारियों के लिये दस घंटे तक काम के सम्बन्ध में कुरेशी समिति के प्रतिवेदन का पूरा किया जाना

6923. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरेशी समिति ने लोको रनिंग कर्मचारियों के लिये दस घंटे तक काम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या कुरेशी समिति के लोको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अलग से भी विचार व्यक्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) रेल मंत्री ने 29-11-1973 को लोक सभा में घोषणा की थी कि 1-12-1973 से 10-घंटे ड्यूटी की योजना लागू करने का काम शुरू किया जायगा और इसे तीन वर्षों में पूरा किया जायेगा। कुरेशी समिति की 20 जनवरी 1974 को हुई बैठक में रेलव के चुने हुए मण्डलों का मार्च-अप्रैल में दौरा करने और 10 घंटे ड्यूटी के सम्बन्ध में क्षेत्रीय रेलों की योजनाओं पर विचार करने का विनिश्चय किया गया था जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि क्या कार्यान्वियन की अवधि 3 वर्ष से कम की जा सकती है। दुर्भाग्यवश लोको रनिंग कर्मचारी एसोसियेशन ने 10-घंटा ड्यूटी को एक तरफा लागू करने के लिए 15 अप्रैल से अखिल-भारतीय स्तर पर आंदोलन करने का फैसला किया है। इससे कुरेशी समिति को अपना 20 जनवरी 1974 का विनिश्चय कार्यान्वित करने में रुकावट पड़ गयी है।

फिर भी 1-12-1973 से 10-घंटे डूयटी की योजना लागू करने का काम शुरू किया गया था जबकि सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां 100 से ज्यादा सवारी गाड़ियां और 22 खण्डों चुनी हुई माल गाड़ियां 10-घंटे ड्यूटी की योजना के अन्तर्गत लायी गयी थीं। आशा है इस वर्ष के अन्त तक सभी सवारी गाड़ियां इस योजना के अन्तर्गत आ जायेंगी।

इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास में श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार के पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी

6924. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटेग्रेल कोच फैक्टरी मद्रास में एक, दो, तीन और चार की प्रत्येक श्रेणी के पदों पर काम कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(ख) वहां कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) और (ख) 30-9-1973 को सवारी डिब्बा कारखाने मद्रास में अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या और प्रत्येक श्रेणी की सेवा में कुल कर्मचारियों से उनका प्रतिशत इस प्रकार है :—

श्रेणी	कुल	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जन जाति	प्रति शत
श्रेणी I . .	44		..	..	..
श्रेणी II . .	37	3	8.1	..	..
श्रणी III	9415	1458	15.5	28	0.3
श्रेणी V (सफाईवालों को छोड़कर) .	3410	777	22.8	2	0.1
श्रेणी IV (सफाई वाले)	162	144	88.9	..	..

आंध्र प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण का निर्धारित लक्ष्य

6925. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश में नयी लाइनों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे का विकास-कार्यक्रम किसी राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि समग्र राष्ट्रीय हित के आधार पर तैयार किया जाता है और रेल सुविधाओं के विकास के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के चौथी योजना के लक्ष्य

6926. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश मे ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) चौथी योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे । 50,000 पम्पसेटों के ऊर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । जनवरी, 1974 तक 133,583 पम्पसेट ऊर्जित किए गए थे । अतः लक्ष्य से अधिक पम्प को ऊर्जित किया गया ।

पम्पसेटों का ऊर्जन मुख्य कार्य है और ग्राम विद्युतीकरण इसी के साथ साथ हो जाता है । चौथी योजना के दौरान 4,500 ग्रामों के विद्युतीकृत होनें की संभावना थी बहरहाल, 31-1-1974 तक 4,552 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ।

आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनों का लक्ष्य

6927. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में, विशेष रूप से इस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लक्ष्यों को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे का विकास कार्यक्रम किसी राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि समग्र राष्ट्रीय हित के आधार पर तैयार किया जाता है और रेल सुविधाओं के विकास के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते । फिर भी, नड्डिकुडे से बीबी नगर तक रेलवे लाइन का निर्माण 1974-75 में शुरू करने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा निर्मित "रिगों" से शिवसागर में तेल के लिए खुदाई

6928. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा डिजाइन किये गये और तैयार किये गये और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सप्लाई किये गये तेल की खुदाई करने वाले तीन बहुत बड़े 'रिगों' में से पहले रिग से शिवसागर में 3,314 मीटर गहराई पर 75 दिन के रिकार्ड समय में तेल निकला है ;

(ख) क्या देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये देश में तेल की खुदाई करने वाले 'रिगों' का उत्पादन पर्याप्त है ; और

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा डिजाइन किये गये और तैयार किये गये तेल की खुदाई करने वाले 'रिग' आयात किये गये 'रिगों' की तुलना में कैसे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कुछ अयान्त्रिक संरचनात्मक हिस्सों को छोड़ कर, भारत इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा सप्लाई की गई रिगें इसी डिजाइन तथा विनिर्माण की थीं। शिवसागर क्षेत्र में इन रिगों में से एक रिग से खोदे गए कुएं में तेल पाया गया है हालांकि वेधन रिकार्ड समय में नहीं किया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) क्योंकि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा सप्लाई की गई रिग इसी डीजाइन एवं विनिर्माण की थीं, तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तेल का उत्पादन करने वाले देशों में तेल परिशोधक कारखानों में इक्विटी अंश खरीदने के भारत के प्रयास

6929. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान और तेल का उत्पादन करने वाले अन्य देशों में इक्विटी अंशों की खरीद से अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की निर्विघ्न सप्लाई के प्रबन्ध को प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) संयुक्त उद्योगों के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया गया है और वे जब भी अन्वेषणात्मक स्थिति में हैं । इस प्रकार के प्रस्तावों का विवरण देना जनहित में नहीं होगा ।

बंगलो-चपड़ासी के पद पर लगे प्रतिबन्ध में ढील

6930. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद बंगलो-चपड़ासी के पद पर लगे प्रतिबन्ध में ढील दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को समाप्त करने सम्बन्धी वेतन आयोग की सिफारिशों को बदलने अथवा उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय रैलों में बंगलो-चपड़ासियों की संख्या क्या है तथा रेलवे को प्रति वर्ष इन पर कितना धन व्यय करना पड़ता है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बंगलो-चपड़ासियों के नये पदों के सर्जन पर 7-2-73 को जो विशिष्ट प्रतिबन्ध लगाया गया था वह 3-11-1973 से हटा दिया गया था। किन्तु खर्च में किफायत बरतने के संदर्भ में पदों के सर्जन और रिक्तियों के भरे जाने पर जो सामान्य प्रतिबन्ध लगा हुआ है वह इस कोटि पर भी लागू होता है।

(ख) सरकार ने अभी तृतीय वेतन आयोग की इस सिफारिश पर निर्णय नहीं लिया है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्यस्थता के पंचाट (मियाभाई और अन्य न्यायाधिकरण) को स्वीकृति

6931. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, मियाभाई और अन्य न्यायाधिकरणों के पंचाटों विशेषकर दफ्तरियों के ग्रेड और वर्कशाप कर्मचारियों के अवकाश अर्जित करने सम्बन्धी पंचाटों को दृष्टि में रखते हुए, तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मध्यस्थता के पंचाट को स्वीकार करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग ने दफ्तरियों के वेतन-मान और कारखाना कर्मचारियों की छुट्टी पात्रता के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश करते समय पंचाट बोर्ड के सम्बन्धित निर्णय को ध्यान में रखा था। दफ्तरियों के वेतन-मान से सम्बन्धित सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है और उनके संशोधित वेतन-मान अधिसूचित कर दिये गये हैं। रेलों में कारखाना कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी देने से सम्बन्धित सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

अहमदाबाद से कोचीन तक सीधी रेलगाड़ी चलाने की मांग

6932. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में रह रहे केरल वासियों ने अहमदाबाद से कोचीन तक एक सीधी रेलगाड़ी चलाने के बारे में कोई मांग की है ;

(ख) क्या उन्हें तथा गुजरात के राज्यपाल को इस बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अहमदाबाद और कोचिन के बीच केवल सीध डिब्बे चलाने के लिए अहमदाबाद केरल समाजम और नायर कल्याण एवं सांस्कृतिक संघ, अहमदाबाद से अभ्यावेदन मिले हैं।

(ग) मार्गवर्ती कुछ खंडों पर लाइन क्षमता के अभाव के कारण अहमदाबाद और कोचिन के बीच सीधी गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। दादर में शंटिंग की कठिनाई होने और बम्बई-मदरास गाड़ियों में गुंजाइश न होने के कारण सीध डिब्बा चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

ऐल्यूमिनियम उद्योग के लिये स्नेहक तेलों की कमी

6933. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री बसन्त साठे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नेहक तेलों की हर स्थान पर कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण तथा तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इसके कारण ऐल्यूमीनियम उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) स्नेहक तेल ल्यूब बेस स्टाक और योगजों से तैयार किए जाते हैं। अधिकांश आवश्यकताओं को देशज उत्पादन से पूरा किया जाता है। हाल ही में हुए तेल संकट के दौरान कुछ कमी वाले तेलों के लिए कुछ बेस स्टाकों और योगजों का विश्व व्यापी अभाव हो गया था जिसका मुख्य कारण यह था कि कुछ संकट पूर्ण रसायनों की उपलब्धि कम थी। इस के फलस्वरूप स्नेहक तेलों का अभाव हो गया था। इन अभावों की जानकारी सरकार को है और इसीलिए विभिन्न उद्योगों के लिए निरन्तर सप्लाई को सुनिश्चित करने के वास्ते सरकार ने पहले से ही अनेक कार्रवाईयां की हैं।

(ग) ऐल्यूमिनियम उत्पादकों से सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है कि स्नेहक तेलों के अभाव के कारण धातु के उत्पादन पर अलग अलग हानि पहुंची है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे गार्ड आन्दोलन के दौरान ब्रेक वैन के गार्डों के बिना चलने वाली गाड़ियों की दुर्घटनायें

6934. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या रेल मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के रेलवे गार्ड आन्दोलन के कारण कुछ गाड़ियां 'ब्रेक-वेन' के गार्डों के बिना चली थीं ;

(ख) क्या ब्रेक-वेन के गार्डों के बिना चलने वाली कुछ गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थीं और यदि हां, तो उन गाड़ियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर घाटी को बिजली की सप्लाई

6935. **श्री सैयद अहमद आगा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने वर्तमान बिजली संकट को पूरा करने के लिए शीघ्र ही 15 किलोवाट बिजली सप्लाई करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) कश्मीर घाटी में भी शेष उत्तरी क्षेत्र की तरह बिजली की कमी है। राज्य सरकार ने कश्मीर घाटी के लिए अतिरिक्त विद्युत की सप्लाई के लिए अनुरोध किया है किन्तु जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच पारेषण सम्पर्क के न होने से ऐसी कोई भी सहायता देना असंभव हो गया है। पारेषण सम्पर्क का निर्माण हो रहा है। घाटी को अतिरिक्त विद्युत सप्लाई के प्रश्न की जांच सम्पर्क के पूर्ण होने पर और उत्तरी क्षेत्र में विद्युत स्थिति तथा उपलब्धता को रोशनी में की जा सकती है।

नानपाडा गुरुपुर "नैरो गेज लाइन"

6936. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान रेलवे लाइनों में सुधार करने तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए नानपाडा-गुरुपुर 'नैरो गेज लाइन' बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 1972-73 में 33-80 किलोमीटर लंबी पूरी पटरी के नवीकरण का कार्यक्रम बनाया गया है। यह काम चल रहा है और आशा है 1974-75 में पूरा हो जायेगा। 56.20 किलोमीटर लंबे रेल पथ पर पूरे स्लीपरों के नवीकरण का काम 1974-75 के कार्यक्रम में शामिल किया गया है और सामान मिलते ही काम शुरू कर दिया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी योजना में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि का नियतन

6937. श्री गिरिधर गोमांगो: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ;

(ख) देश के आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ; और

(ग) राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई विकास का स्तर क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों से संबंधित पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। बहरहाल, योजना में सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत 2401 करोड़ रुपयों का परिव्यय परिकल्पित है। उम्मीद है कि कई नई स्कीमों को हाथ में लेने के अतिरिक्त 64 चालू बृहद् स्कीमों (75 में से) और सभी 155 चालू मध्यम स्कीमों पर कार्य पूर्ण हो जाएगा।

उन नई स्कीमों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है जिनसे चिर सूखा-ग्रस्त जनजातीय तथा पिछड़े क्षत्रों को लाभ होता है।

वर्ष 1974 से 1976 तक अतिरिक्त बिजली पैदा करने का लक्ष्य

6938. श्री नरेन्द्रकुमार सांघी: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974, 1975 तथा 1976 के दौरान अतिरिक्त बिजली पैदा करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने में एक बाधा बिजली उपकरणों की कमी की भी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस अवधि में होने वाली कमी के बारे में मूल्यांकन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आशा है कि 1974-75 के दौरान 2.37 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता चालू की जा सकेगी। जबकि 1975-76 और 1976-77 के वर्षों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, प्रारंभिक मूल्यांकन से पता चलता है कि इन वर्षों के दौरान क्रमशः 2.76 मेगावाट और 3.59 मेगावाट क्षमता का योग होगा।

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के पूरा होने में साधारणतया कम से कम लगभग 5 वर्ष लग जाते हैं। तदनुसार, 1974, 1975 और 1976 के वर्षों में जोड़ी जाने वाली प्रतिष्ठापित क्षमता के लिए विद्युत उपस्कर की सारी आवश्यकताएं देशी अथवा विदेशी स्रोतों से पूरी करने की व्यवस्था की जा चुकी है और इस संबंध में किसी प्रकार की कमी की प्रत्याशा नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के एककों में बिजली की कमी

6939. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की कमी के कारण सरकारी क्षेत्र के एककों को हानि हुई है ; और

(ख) इन एककों की बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यह सत्य है कि देश में विद्युत की कमी है जिसने सरकारी क्षेत्र में यूनिटों सहित अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है।

(ख) विद्युत सप्लाई की कमी को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

1. वर्तमान विद्युत केन्द्रों से विद्युत की उपलब्धता को अधिकतम करना ;
2. नई उत्पादन यूनिटों के प्रचालन तथा पारेषण लाइनों के निर्माण में तेजी लाना।
3. फालतू विद्युत वाले अथवा अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता वाले क्षेत्रों से राज्यों तथा क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर कमी वाले क्षेत्रों को बिजली का पारेषण।

इन उपायों के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में यूनिटों सहित, औद्योगिकी तथा कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्य से, विद्युत की कमी की परिस्थितियों में, विद्युत का राशन करने की एक युक्तिसंगत स्कीम तैयार की गई है। ऐसा करते समय प्रत्येक राज्य में कमी की प्रकृति (ऊर्जा अथवा पीक क्षमता आदि), अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्येक उद्योग के सापेक्ष महत्व, उसको रोजगार शक्यता, निर्यात संबंधी प्रयत्न इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है।

हरियाना में कटवाल में पेट्रोलियम का पता लगाना

6940. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के सोनीपत जिले के कटवाल गांव में कुछ समय पहले गांव वालों को कुआं खोदते हुए किसी प्रकार का पैट्रोलियम मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र का तेल तथा प्राकृतिक गैस के विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण कराने का है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार को इस की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स सैण्डोज द्वारा ब्राइनरडाइन का निर्माण

6941. श्री मालजीभाई परमार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सैण्डोज को 'ब्राइनरडाइन' तथा अन्य फार्मुले बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) क्या 'ब्राइनरडाइन' का मुख्य अंश डाई-हाइड्रो-एरगो-क्राइस्टाइन है और यह 'हाइपरटेंशन' के उपचार में काम आता है जिसके लिए भारतीय बाजार में अनेक ऐसी ही औषधियां उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या सरकार सैनडोज को इस औषधि को 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक की दर पर आयात करने की अनुमति दे रही है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य ऐसी ही औषधियां लगभग 4,000 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो मैसर्स सैनडोज के प्रति इस विशिष्ट व्यवहार के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मैसर्स सेन्डोज् इंडिया लि० को ब्राइनरडाइन का निर्माण करने के लिये अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया है । तथापि, उन्हें कई अन्य सूत्रयोगों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है ।

(ख) सिनरडाइन के उत्पादन के लिये डिहाइड्रोएरगोक्रिस्टाइन मेथेन सल्फोनेट एक सक्रिय सामग्री है। यह एक नई औषधि है। बताया जाता है कि इसे सेन्डोज ने उच्चरक्तचाप का इलाज करने के लिये तैयार किया है । उच्चरक्तचाप के इलाज के लिये बनाई गई अन्य औषधियां भारतीय बाजार में भी उपलब्ध हैं ।

(ग) ब्राइनरडाइन के निर्माण के लिये कच्चे माल का आयात किये जाने पर विचार फर्म द्वारा औद्योगिक लाइसेंस ले लिये जाने के बाद ही किया जायेगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Oil exploration at Baramura in Tripura

6942. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there are huge oil reserves in Baramura area of Tripura, which is larger than the sea area at Bombay ;

(b) whether the first oil well was dug 1½ years after the scheduled time in that area; and

(c) the extent of digging done in 1973?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) It is too early to say as to what are the oil reserves in Baramura. The structure at Baramura is much smaller than the structure at Bombay High.

It is, only after drilling has been completed and various tests carried out that an idea of reserves in an area can be formed. Drilling at Baramura has not yet been completed.

(b) Yes, Sir. The well was spudded on 19-7-1972 in Baramura.

(c) During 1973, 734 metres were drilled in the Baramura structure.

बिहार में उपद्रवों के कारण रेल गाड़ियों के रद्द किये जाने का आसाम राज्य पर प्रभाव

6943. **श्री तरुण गोगोई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार में उपद्रवों के कारण रेलगाड़ियों के रद्द किये जाने से आसाम राज्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था ; और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : जी नहीं ।

Pilferage from Goods Train at Sasni station on the 4th January, 1974

6944. **Shri Chandra Shailani :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any incident of pilferage from the goods train occurred on the 4th January, 1974 at Sasni station (near Hathras Junction) of Northern Railway;

(b) the names of the articles pilfered and the approximate value thereof and whether some of the articles pilfered have since been recovered;

(c) the names of the R.P.F. men who were on duty on that day; and

(d) the names of the persons arrested in connection therewith and the steps taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No such incident occurred on 4-1-1974. However, on 8-1-74, a theft from a stabled load of Up Super Goods Express occurred at Sasni Railway Station.

(b) 62 packages containing Bata shoes and Electrical goods, mostly orient fans, all valued at about Rs. 20,000/ were stolen. Stolen goods worth about Rs. 10,000/- have since been recovered.

(c) RPF Rakshaks Dhan Bahadur and Seodan Singh were on duty at the station on the day of the occurrence, and they have since been placed under suspension.

(d) Three railway employees of the Engineering Department, viz. Puran Mal, Sunhari Lal and Ram Singh, and one outsider named Har Parshad have been arrested under section 3 of the Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966 by RPF Aligarh Jn. The case is under investigation.

States which have not achieved target of Electrification in 1973-74

6945. **Shri Sukhdeo Prasad Verma :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the States which have not achieved the target of electrification of villages fixed for the year 1973-74; and

(b) the reasons for not achieving the target and the steps Government propose to take in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) and (b) During the Fourth Plan targets had been fixed only for energisation of pumpsets. No targets had been fixed for village electrification. The number of villages electrified during 1-4-1973 to 28-2-1974 is, however, 11902.

औषध फर्मों को "की इण्डस्ट्री श्रेणी" के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करना

6946. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी औषध कम्पनियों को "की इण्डस्ट्रीज" श्रेणी के अन्तर्गत लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी है कि ये कम्पनियां गैर-औषध वस्तुएं बना रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो औषध (मूल्य और नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अधीन इन फर्मों पर नियन्त्रण लगाने का क्या सरकार का विचार है और यदि नहीं ; तो क्यों ?

पेट्रोलियन और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) फरवरी, 1970 में घोषित की गई संशोधित औद्योगिक लाइसेसिंग नीति के अधीन औषध और भेषज उद्योग को मूल उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस नीति के अधीन विदेशी और भारतीय दोनों कम्पनियों को औषध और भेषज का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। फरवरी, 1973 में भी की गई घोषित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अधीन औषधों और भेषजों को उद्योग सूची में शामिल कर लिया जाता है जिसके लिए विदेशी कम्पनियां और बृहत हाउस पात्र हो। इसके साथ एक विवरण पत्र संलग्न है जिसमें पिछले तीन साल के दौरान विदेशी कंपनियों के नाम और उनके दिए गए लाइसेंसों की संख्या (सी० ओ० बी० लाइसेंसों से भिन्न अन्य) दी है।

(ग) कुछ विदेशी फर्मास्युटिकल कंपनियां भी अन्य निर्माण कार्यों में व्यस्त हैं।

(घ) औषध से भिन्न मदें औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 के अन्त में नहीं आती है। तथापि वह आदेश औषध की मदों के लिए समस्त औषध निर्माण कंपनियों पर लागू है।

विवरण

विदेशी कंपनी का नाम	वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या
1. मैसर्स मर्क शार्प एण्ड थोम आफ इण्डिया लि०	1
2. मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज लि० . . .	3
3. मैसर्स रेकिट एण्ड कोलमेन आफ इण्डिया लि० . . .	1
4. मैसर्स सिबा आफ इण्डिया लि०	2

विदेशी कंपनी का नाम	वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या
5. मैसर्स सायनामिड इण्डिया लि०	1
6. मैसर्स बूटस कंपनी (इण्डिया) लि०	2
7. मैसर्स ई मॅक लि०	1
8. मैसर्स फाइजर लि०	1
9. मै० बुरोस वेल्कम एण्ड कं० इण्डिया प्रा० लि०	1
10. मैसर्स वोरिंगर नाल लि०	1
11. मैसर्स बेयर (इण्डिया) लि०	1

कोयले की कमी के कारण गाड़ियों के रद्द होने से रेलवे को हुई हानि

6947. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान कोयले की कमी के फलस्वरूप रद्द की गयी गाड़ियों के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकार द्वारा नई लाइनों के लिये किया गया अनुरोध

6948. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1972 से आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में नई लाइनें बिछाने के लिये अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन लाइनों का प्रस्ताव किया गया था ; और

(ग) रेलवे मंत्रालय ने उस पर क्या निर्णय लिये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पिछले कुछ समय से आन्ध्र प्रदेश सरकार राज्य में कुछ नयी लाइनों के निर्माण के लिए अभ्यावेदन देती आ रही है । ये प्रस्ताव और इनसे सम्बन्धित वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

लाइन का नाम	वर्तमान स्थिति
1. नागार्जुन सागर के रास्ते ओंगोल से हैदराबाद	सिकन्दराबाद (बीबीनगर) से नडिकुडे तक नयी लाइन और गुंटूर-मचरेला खण्ड के आमान परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण का काम

लाइन का नाम	वर्तमान स्तिति
	पूरा हो चुका है । यह लाइन नागार्जुन सागर क्षेत्र से गुजरेगी । इस सम्पूर्ण परियोजना को 1974-75 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।
2. बेनाडिल्ला से कोड़ेगोदाम (भद्राचलम रोड)	पहले किये गये सर्वेक्षणों से पता चला था कि यह लाइन तभी औचित्यपूर्ण होगी जब दण्डकारण्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हो जिसके बारे में अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है ।
3. भद्राचलम-कव्वूर रोड	कुछ समय पहले जो व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययन किये गये थे और हाल में उनके जो अद्यतन आंकड़े तैयार किये गये थे, उनसे पता चला था कि यह रेलवे लाइन बड़ी अलाभप्रद होगी । इसलिए इस लाइन पर विचार नहीं किया जा रहा ।
4. निज़ामाबाद-पेड्डपल्लि	पहले की गयी जांच-पड़ताल से पता चला था कि यह लाइन वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं होगी । फिर भी, पहले किये गये इंजीनियरिंग सर्वेक्षण को अद्यतन बनाने और रामगुडग से निजामाबाद तक की लाइन के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है । इस सर्वेक्षण को 1974-75 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।

आंध्र प्रदेश के कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल की खोज

6949. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल की खोज करने हेतु कोई परियोजना चालू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ वर्ष पहले रूस के एक तटदूर अभियान दल ने इस क्षेत्र में समुद्री भू-कंपन सर्वेक्षण किया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त दल के कार्य का क्या परिणाम रहा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1959-60, 1960-61 तथा 1965-66 में जारी क्षेत्रीय मौसम में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल अन्वेषण हेतु भूगर्भीय गुरुत्वाकर्षण से चुम्बकीय तथा भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये थे । जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यधन कार्य भी किये गये । भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) मई, जुलाई 1966 के दौरान प्रारम्भिक भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये इनके परिणामों में सामान्य रूप में जैन्टिल संरचनाओं का दक्षिण-पूर्व का की और होमोक्लाइजल डिप का पता चला । इन सर्वेक्षणों से समीपस्थ संरचनात्मक आकृति की स्थापना नहीं की गई ।

हैदराबाद-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी की गति बढ़ाना

6950. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हैदराबाद-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी की गति तेज करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह एक्सप्रेस गाड़ी जिस गति से चलती है, वह एक्सप्रेस गाड़ियों की अखिल भारतीय औसत गति से बहुत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दूसरी एक्सप्रेस गाड़ियों की भांति 45/46 हावड़ा-हैदराबाद एक्सप्रेस गाड़ियों की औसत गति यातायात एवं परिचालन सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुरूप है। मार्गवर्ती ठहरावों की बहुत बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए और इन गाड़ियों की समय सारिणी में परिवर्तन करने में होने वाली कठिनाईयों के कारण इनकी गति और तेज करना सम्भव नहीं है क्योंकि ये गाड़ियां उड़ीसा में दिन की सुविधाजनक सेवा और आन्ध्र क्षेत्र में रात की सेवा उपलब्ध करती हैं ।

सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) के बड़ानगर में सिगनल तथा दूर संचार विभाग सम्बन्धी इन्स्टालेशन

6951. श्री भोला मांझी :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के बड़ानगर सी० सी० लिंक सेक्शन में अप और डाउन दोनों लाइनों पर सिगनल और दूरसंचार विभाग द्वारा लगाये गये इन्स्टालेशन स्वीकृत नक्शों के अनुसार नहीं है ;

(ख) क्या पुराने इन्स्टालेशनों को, स्वीकृत नक्शों के अनुकूल बनाने के लिये सुधारा जा रहा है ;

(ग) क्या इस सेक्शन में जनवरी, 1973 में कोई दुर्घटना हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो योजना को वहां लागू करने वाले उत्तरदायी डिवीजनल सिगनल तथा दूरसंचार इंजीनियर तथा अन्य अधिकारियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं । बड़ानगर सी० सी० सम्पर्क खंड पर सिगनल और दूर संचार विभाग से संबंधित संस्थापन अनुमोदित योजनाओं के अनुरुप तैयार किये गये है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए उन्हें अनुकूल बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ;

(घ) यह दुर्घटना सिगनल को गलत ढंग से लगाने के कारण नहीं हुई । इसलिए, मंडल सिगनल और दूर संचार इंजीनियर तथा अन्य अधिकारियी के विरूद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी ।

सियालदेह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में एब्सोल्यूट परिमिसिव ब्लाक सिस्टम के लागू करने सम्बन्धी लागत

6952. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सिगनल तथा टेलीकम्यूनिकेशन इन्जीनियर तथा डिवीजनल सेफ्टी अफिसर, सियालदेह, पूर्व रेलवे ने अभी हाल में पूर्व रेलवे के सियालदेह डिवीजन में कंकीनारा और नैहाटी के बीच सांझी लाइन पर एब्सोल्यूट परिमिसिव ब्लाक सिस्टम लागू किया है ;

(ख) इस सिस्टम को लागू करने पर क्रमशः विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में कितनी लागत आयी है ;

(ग) क्या एसिस्टेंट स्टेशन मास्टरों ने सुरक्षा के आधार पर इस सिस्टम को लागू करने पर आपत्ति की है; और

(घ) उक्त सेक्शन पर आने जाने वाली गाड़ियों को चलने के लिये नैहाटी और कंकीनारा के बीच डाउन मेन लाइन को क्यों नहीं उपयोग में लाया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 78,000 रुपये है और इसमें कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी ।

(ग) जी हां । लेकिन असुरक्षा सम्बन्धी बात ठीक नहीं है ।

(घ) नैहाटी और कंकीनारा के बीच डाउन मुख्य लाइन का उपयोग पहले ही केवल माल यातायात के लिये किया जा रहा है क्योंकि इस लाइन पर यात्री प्लेटफार्म की सुविधा नहीं है ।

फिल्मी गीतों के रिकार्डों को बजाने सम्बन्धी रेल मंत्रालय के निदेश

6953. **श्री भोला मांझी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने जोनल रेलवे के डिवीजनल सुप्रिन्टेन्डेंटों को दिन में तीन बार डी० एस० भवनों में फिल्मी गीतों के रिकार्डों को बजाने के बारे में कोई निदेश जारी किये है और यदि हां, तो इसकी उपयोगिता क्या है और इस पर आने वाले व्यय के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गयी है ;

(ख) क्या उत्तर-पूर्व सीमा रेलवे के किसी डी० एस० कार्यालय पर इस प्रकार के रिकार्ड बजाने शुरू किये गये है और यह व्यय किस स्त्रोत से किया जाता है; और

(ग) क्या गत कुछ महीनों से कटिहार स्थित डी० एस० भवन में फिल्मी रिकार्ड बजाए जा रहे हैं और यदि हां, तो किस आधार पर तथा किसकी अनुमति से ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) केवल कटिहार स्थित मण्डल अधीक्षक कार्यालय भवन में ही गत वर्ष कुछ समय के लिये देशभक्ति पूर्ण गानों के रिकार्ड बजाए गये थे । यह कार्य काफी अरसा हुआ बन्द कर दिया गया है । रेलवे द्वारा इस संबंध में कोई खर्च नहीं किया गया क्योंकि सभी रिकार्ड दान स्वरुप प्राप्त हुए थे ।

Reasons for not realising parking charges from buses at Dhanbad station

6954. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether hundreds of buses are parked at the Dhanbad Railway bus Stand but the bus conductors have never paid the parking charges to the Railways so far despite the fact that the Railways have fixed the parking rates at Rs. 10 per bus and Rs. 5 per taxi; and

(b) if so, the reasons for not realising the parking charges?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) No parking charges are realised by the railway direct from bus conductors and taxi drivers at Dhanbad Railway Station. A lumpsum amount of Rs. 1650/- and Rs. 805/- per annum is paid by the Bus Owners' Association and the Taxi Owners' Association respectively for parking of buses and taxis in the station premises at Dhanbad. However, there are arrears to be paid and they are being pursued to pay them.

Development of Asansol and Howrah Stations

6955. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Bhartiya Railway Yatri Sangh (Indian Railway Passengers Association) has asked the Railway Ministry to construct about 20 retiring rooms over the Third Class waiting Room in Asansol which will result in an additional income of about more than Rs. 1,000 per month to the Railways; and

(b) whether a demand has also been made that the lavatory in third class waiting hall at Asansol and Howrah be modernised?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) No such requests have been received by the Eastern Railway Administration.

Arrangement for reservation of berths at Asansol

6956. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government propose to make arrangements to reserve 10 third class berths in 5 Up train, 20 berths in 1 Up train, 15 berths on Deluxe train and 10 berths in South Bihar train at Asansol keeping in view the difficulties about availability of seats to lakhs of passengers at Asansol, a key coal-belt town?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : A quota of 9 third class sleeper berths by 5 Up Howrah Amritsar Mail, 12 third class sleeper berths and 14 seats by 1 Up Howrah-Delhi-Kalka Mail and 9 third class sleeper berths and 13 A.C. Chair Car seats by 81/103 Up A.C. Express trains is already allotted to Asansol station. No quota has been allotted to Asansol by 87 Up/88 Dn. South Bihar Expresses as the run between Asansol-Patna/Tatanagar is very short for which passengers are reluctant to pay a sleeper surcharge of Rs. 5.50.

Demand for improvement in the sanitation arrangements

6957. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the President of Bhartiya Railway Yatri Sangh (Indian Railway Passengers Association) had sent representation to the Railway Passengers Association) had sent representation to the Railway Board for improving the sanitation arrangements at Asansol, Dhanbad, Howrah, Patna and Moghulsarai

stations, including a demand for the transfer of old Inspectors working there for about 10-15 years, augmentation of scavenging staff strength, and a protest against laying of pitch over the concrete-plaster at these stations; and

(b) the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) No representation has been received. However, a special programme has been launched by the Railway to improve the standard of sanitation at all important stations including Asansol, Dhanbad, Howrah, Patna and Mughalsarai. A copy of the representation is being obtained from the Association and suitable necessary action will be taken on the matters raised therein.

Abolition of Sanitation wing of Road side Station carriage and wagon mechanical department of Indian Railways

6958. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to abolish Sanitation Wing under the Road side Station Carriage and Wagon, Mechanical Department of the Indian Railways and to form such a wing under the Medical Department to ensure convenience to the Railways and benefit to the passengers; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) There is no proposal to transfer the sanitation work at road-side stations to the Medical Department as the existing arrangements are more conducive for effective control and supervision.

Proposal to run trains from Ahmedabad to Marwar Junction

6959. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether many of the trains running from Ahmedabad go upto Mount Abu or Palanpur only and if so, the particulars thereof;

(b) whether Government are aware that, except Ahmedabad-Delhi Mail and Janta trains, most of the other trains do not go beyond Mount Abu while a larger number of passengers travelling by these trains have to go Siroi, Jawai, Bandh, Falna Rani Marwar Junction and if so, the particulars of those trains; and

(c) whether Government propose to extend these trains upto Marwar Junction?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) No train starting from Ahmadabad terminates at Palanpur or Abu Road. In addition to 1/2 Ahmadabad-Delhi Mail and 31/32 Ahmadabad-Delhi Janta Express, Ahmadabad—Falna-Marwar section is served by another two pairs of trains viz., 3/4 Delhi-Ahmedabad Express and 5/6 Agra Fort Fast Passenger. The only other train running between Ahmadabad and Palanpur is 65A/66A Ahmadabad-Bhuj Fast Passenger which also is not terminating at Palanpur.

(c) Does not arise.

Installation of Telephone at Sarai Rohilla Station

6960. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to install a telephone at Sarai Rohilla Station so that passengers may get facility to make enquiries over telephone;

(b) if so, the time by which it will be provided there by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) A P. & T. Telephone is already available with Station Master Sarai Rohilla with an extension telephone in the Reservation and Booking Office at this Station.

(b) Does not arise.

Trains cancelled in Rajasthan due to coal shortage during the last six months

6961. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number and particulars of trains cancelled in Rajasthan during the last six months due to shortage of coal and the date on which each of them was cancelled;

(b) the names of the trains, among them, which are proposed to be restarted and the time by which these would be restarted; and

(c) if there is no proposal for re-starting these trains, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

मसर्ज कृषि विकास केन्द्र रिवाड़ी को उर्वरकों का व्यापार करने सम्बन्धी अनुमति

6962. **श्री पन्नालाल बारुपाल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम, नया नंगल, ने मैसज कृषि विकास केन्द्र रिवाड़ी को उर्वरक का व्यापार करने की अनुमति दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितनी मात्रा में उर्वरक सप्लाई किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाजखां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शेयरों के आवेदन कर्ताओं की मांगी गई राशि अथवा ब्याज देने में विफलता पर जुर्माना

6963. **श्री मधु दंडवते :** क्या **विधी, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयरों के आवेदन कर्ताओं की मांगी गई राशि की अदायगी में विफलता पर कुछ जुर्माना लगता है :

(ख) क्या सरकार ने उन कम्पनियों पर, जो शेयर प्राप्त करने में विफल रहे आवेदकों को निर्धारित अवधि में ब्याज नहीं देती है, कोई जुर्माना लगाया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम में, इन विषयों से सम्बन्धित कोई उपबन्ध नहीं है, क्योंकि यह सम्बन्धित कम्पनी के प्रविवरण अथा पार्षद नियमों जैसा भी विषय हो, के निबन्धनों के द्वारा विनियमित होने के लिए छोड़ दिया गया । अत: सरकार द्वारा कोई जुर्माना करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पांचवी योजना के दौरान संश्लिष्ट धागे का उत्पादन

6964. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के दौरान पोलिस्टर, नाइलोन जैसे संश्लिष्ट धागे के उत्पादन के लिये कोई नीति निर्धारित की गई है;

(ख) क्या फैन्सी रंग वाले कपड़े के उत्पादन के लिये पैट्रो-रसायन पर आधारित संश्लिष्ट रंगो की कोई मांग है; और

(ग) नेफ्था के स्थान पर कोयले से अधिक कार्बनिक रसायनों की प्राप्ति के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सिन्थेटिक फाईबर के लिये पांचवी योजना के प्रारूप प्रलेख में निम्नलिखित क्षमताओं और उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है :—

उद्योग	क्षमता ('000 मिटरी टनों में)	उत्पादन
(1) नाइलोन फिलामेन्ट यार्न . . .	23	21
(2) नाइलोन टायर कोर्ड और अन्य औद्योगिक यार्न .	10	9
(3) पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न और स्टेपल फाईबर	59	45
(4) ऐक्रिलिक फाईबर	16	14

(ख) रंग निर्माता अधिकतर कोलतार उत्पादन पर आधारित है। उत्पादन का बहुत थोड़ा अंश पेट्रोलियम पर आधारित **है** । रंगो के अधिकतम उपयोगकर्ता वस्त्र उद्योग वाले है ।

(ग) कोल आधारित कार्बनिक रसायनों का विकास करने के लिये अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।

उर्वरक बचाव योजना

6965. **श्री मधु दंडवते :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "उर्वरक बचाव योजना" अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बाते कौन सी है; और

(ग) क्या सरकार तत्काल आधार पर कच्चे माल का आयात करने सम्बन्धी उर्वरक उद्योग की मांग से सहमत हो गयी है ताकि वह अपना उत्पादन बढ़ा सके ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) कृषि मन्त्रालय के अनुसार उर्वरकों का कुशलता से प्रयोग करने के लिये एक दस सूत्री योजना तयार की गई है। योजना की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा निम्नलिखित है।

(1) अधीनस्थ क्षेत्रों; सिंचित क्षेत्रों और वर्षा वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषण तत्वों, खादों कीटनाशी और खर पतवार नियन्त्रण सहित उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए गहन अभियान चलाना ताकि उनसे अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

(2) एन० पी० और के० अर्थात् उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग को बढ़ावा देना ताकि उससे प्रति यूनिट क्षेत्र पर अधिकतम उत्पादन और लाभ उठाया जा सके।

(3) निक्षालन और विनाइट्रीकरण के माध्यम से नाइट्रोजन की हानि पर काबू पाने के लिए यूरिया के प्रयोग की वैज्ञानिक प्रणाली।

(4) इन उर्वरकों के वितरण को आवश्यकतानुकूल बनाया जाता है कि भू परीक्षण के आधार पर फास्फेट और पोटाश के अपूर्ण और समृद्ध क्षेत्रों का वर्णन करना।

(5) जस्त की कमी वाले इलाकों का वर्णन करना ताकि इस प्रकार के इलाकों को जिंक सल्फेट की सप्लाई कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये की जाए।

(6) भूमि के पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने और आवश्यकतानुसार उर्वरकों का इस्तेमाल करने के लिये भू परीक्षण कार्यक्रम को सघन बनाना।

(7) भू उर्वकता, जल धारण क्षमता को बनाने के लिये और अनुपूरक रसायन उर्वरकों के अनुसार सूक्ष्म पोषण तत्वों की सप्लाई करने के लिये भी कार्बनिक खाद के प्रयोग को सघन बनाना।

(8) खरचतवारों का नियन्त्रण करना, जो फसल को दिए गए लगभग 30-40 प्रतिशत तक पौधों के पोषकतत्वों को खा डालते हैं।

(9) निवेशों का प्रयोग करने के लिये किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देना।

(10) उर्वरकों के कुशल प्रयोग की आवश्यकता के सम्बन्ध में किसानों को उसकी पूर्ण रीति से जानकारी कराने के लिये रेडियों, टेलिविजन, समाचार पत्र, पोस्टर, लीफलेट्स, भित्ति चित्र, फिल्मों, मिति-लेखों, मेलों आदि सहित समस्त श्रव्य और दृश्य माध्यमों को गतिशील बनाना।

(ग) उर्वरक उद्योग की सब मिलाकर कच्चे माल की आवश्यकताओं को सन्तोषजनक रूप से पूरा किया जाता है। आयातित उपकरण और अतिरिक्त पुर्जों के लिये उद्योग की आकस्मिक आवश्यकताओं को भी उस आवर्तक निधि से पूरा किया जाता है जो पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय को सौंपी गई है।

पेट्रो-उद्योग समूहों को तेल शोधन शालाओं के समीप स्थापित करने का प्रस्ताव

6966. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान तथा प्रस्तावित तेल शोधन शालाओं के पास पेट्रो-उद्योग समूहों की स्थापना करना चाहती है; और

(ख) क्या बरोनी तेल शोधनशाला के उपोत्पादों से 110 विभिन्न वस्तुओं के निर्माण का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उस में इस समय कितनी वस्तुएं बनाई जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। 1 मिलियन मीटरी टन शोधनशाला से नैफ्था पर आधारित बौगई गांव में उसी स्थान पर 33,000 मी० टन/प्रति वर्ष डी एम टी एव 20,000 मी० टन/प्रति वर्ष पोलिएस्टर स्टैपल फाइबर संयत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। बरौनी तथा/अथवा गोहटी शोधन-शालाओं के समीप एरोमैटिक उत्पादन सुविधाओं हेतु एक प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

खाली माल डिब्बों के लाने ले जाने से रेलों द्वारा उठाई गई हानि

6967. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक खाली माल डिब्बों के लाये ले जाने से रेलों को वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में कितनी हानि उठानी पड़ी ;

(ख) उसके क्या कारण है और ऐसे अनावश्यक व्यय को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) रेल परिवहन में माल डिब्बों की खाली ढुलाई तो निहित ही है। एक ही और का यातायात होने के कारण कोयला, अयस्क और खनिज तेल आदि की ढुलाई के लिए खाली माल डिब्बों का संचलन किया जाता है। कभी कभी अति आवश्यक पदार्थों जैसे खाद्यन्न, उर्वरक और नमक के लदान के लिए खाली माल डिब्बों की ढुलाई करनी पड़ती है। इस आशय की हिदायतें पहले से मौजूद है कि खाली माल डिब्बों में आवक माल का लदान भी किया जाये।

राम नगर से काठ गोदाम तक नई रेल लाइन

6968. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम नगर से काठगोदाम के बीच नयी लाइन बिछाने के लिये आरम्भिक कार्यवाहियां पूरी कर ली गई है; और

(ख) निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी लाइन की व्यवस्था करने के काम को 1974-75 के बजट में शामिल कर लिया गया है। रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी लाइन की व्यवस्था के सर्वोत्तम विकल्प का पता लगाने के लिये शीघ्र ही प्रारिम्भक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जायगा प्रस्तावित सर्वेक्षण पूरा हो जाने और परियोजना अनुमान अनुमोदित हो जाने पर ही वास्त-विक निर्माण शुरू किया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली के सहायक स्टेशन निदेशक द्वारा आत्महत्या किए जाने का समाचार

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूँ कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"टेलीविजन केन्द्र के सहायक स्टेशन निदेशक द्वारा 11 अप्रैल, 1974 को आकाश वाणी भवन नई दिल्ली की चौथी मंजिल से कूद कर आत्म-हत्या किये जाने का समाचार"

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : 11 अप्रैल, 1974 को 11–30 बजे मध्याह्न पूर्व दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के सहायक स्टेशन निदेशक श्री जे० एन० गौढ़ आकाशवाणी भवन की चौथी मंजिल स्थित अपने कमरे (संख्या 410) से गिर पड़े। उन्हें तुरन्त विलिंगडन अस्पताल के आपात कालीन विभाग में ले जाया गया जहां कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

क्योंकि पुलिस मामले की जांच कर रही है इसलिए मृत्यु की परिस्थितियों के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देना उचित नहीं है। श्री गौढ़ हमारे टेलीविजन केन्द्र के बड़े तेजस्वी अधिकारी थे तथा उन्हें अपने काम से बेहद लगाव था। कार्यक्रमों के संयोजक और निर्माता के रूप में उनका बड़ा मान था तथा नए टेली-विजन केन्द्र के खुलने पर हम उनके भविष्य को उज्ज्वल करने का विचार कर रहे थे।

श्री गौड़ की अचानक मृत्यु से टेलीविजन केन्द्र में उनके सभी साथियों और सहयोगियों को भारी दुःख पहुँचा है। हमारे हृदय में श्रीमती गौड़, जोकि आकाशवाणी में कार्य करती हैं, के लिये अत्यंत सहानुभूति हैं।

हम इस निष्ठावान कलाकार के निधन पर उनके परिवार के प्रति अत्यन्त चिन्तित हैं तथा शिक्षा पूरी करने पर उनके पुत्र को आकाशवाणी में कार्य देने का हमने निर्णय किया है।

इस निष्ठावान कलाकार की स्मृति में हमने सर्वोत्तम टेलीविजन वृत्त चित्र के लिए प्रतिवर्ष गौढ़ पुरस्कार देने का निर्णय किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम यहां पर संवेदना संदेश सुनने के लिये नहीं आये। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को उठाने का हमारा उद्देश्य केवल यही है कि टेलीविजन केन्द्र के कर्मचारियों की हालात की सही जानकारी मिले। केन्द्र की प्रशासनिक राजनीति में जो खेल खेले जाते है वह सर्व विदित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डा० विनोद शाह के मामले में नियुक्त जांच समिति के बारे में सभी जानते है कि केवल पुलिस जांच का ही प्रश्न नहीं है। जांच का वास्तविक विषय तो यह है कि क्या इस देश में प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार हो रहा है ? क्या वैज्ञानिकों तथा अन्य व्यक्तियों को संतोषजनक परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है ? क्या पुलिस जांच से इन सभी बातों की जांच सम्भव है ?

समाचार-पत्रों से ज्ञात होता है कि उनकी नोटबुक खो गई है। इन सभी बातों से हमें चिन्ता है।

ऐसी कहानियां भी रची गई है कि श्री गौड़ रोगग्रस्त थे तथा उनकी चिकित्सा हो रही थी। श्रीमती गौड़ ने ऐसे समाचारों का खण्डन किया है। श्रीमती गौड़ ने यह भी बताया है कि जिन कारणों से श्री गौड़ को आत्महत्या करनी पड़ी वह पारिवारिक नहीं थे।

ऐसे समाचार, शिकायतें तथा आरोप है कि टेलीविजन केन्द्र ठीक से नहीं चल रहा तथा वहां के कर्मचारियों में भारी असंतोष है। एक शिकायत तो यह है कि टेलीविजन केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन आकाशवाणी के कलाकारों से शायद कम हो है अधिक तो कदापि नही है। टैलीविजन कलाकार अधिक परिलब्धियों की आशा रखते है।

पदोन्नति के अवसरों तकनीकी उपकरणों की कमी तथा अधिकारी वर्ग के रुख के बारे में शिकायत की गई है। इस प्रकार के सभी आरोप उक्त घटना से सम्बद्ध है। ऐसी बातें बहुत से सरकारी निकाओं में घटती है। श्री गौड़ निश्चय ही भारी काम के बोझे से दबे हुए थे।

उपलब्धि टिप्पणियों में एक टिप्पणी ऐसी मिली है जिसमें उन्होंने अपने अधिकारी को इतना अधिक कार्य कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। ऐसी बातों से हमें अत्यन्त चिन्ता है।

क्या मंत्री महोदय इन सभी शिकायतों, आरोपों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आयोग गठित करेंगे जिसके अध्यक्ष कोई सार्वजनिक सन्मान-प्राप्त व्यक्ति हों और जो टेलीविजन केन्द्र के पूरे कार्यकरण की जांच करे तथा देखे कि क्या वास्तव में वहां पर अन्याय हो रहा है तथा असंतोष विद्यमान है तथा इन सभी मामलों में समुचित सुधारों के बारे में सुझाव दें। इस प्रकार की जांच पुलिस जाँच से अच्छी रहेगी क्योंकि उससे माननीय मूल्यों का ध्यान रखा जा सकेगा।

श्री आई० के० गुजराल : जब मैंने वक्तव्य दिया था तब बहुत से तथ्य प्रकाश में नहीं आये थे।

किसी सृजनशील कलाकार का मत हमारे आपके मनों से अधिक भावुक होता है और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कुछ भी कर बैठता है।

जहां तक टेलीविजन केन्द्र की सामान्य दशा का सम्बन्ध है मै संतोषपूर्वक कह सकता हूँ कि कर्मचारी इसके निर्माण में, रुकावटों के होते हुए भी, सल्लग्न है। यह कहन गलत है कि हमारे पास उपकरणों की कमी है। परन्तु हम केवल चार घंटे का कार्यक्रम तथा स्कूली कार्यक्रम ही दे पाते है।

मैंने श्री गौड़ के निधन पर हुई शोकसभा में भाग लिया था। उसके सहयोभियों ने उसकी निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता की प्रशंसा की है। वेतनों के बारे में मैं यह तो नहीं कहता कि वे आदर्श हैं, परन्तु श्री गौड़ को 1100 रुपए मिलते थे। उनकी पत्नी को 800 रुपए मिलते हैं उनका एक ही पुत्र है। इस लिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनपर परिवार का भारी बोझा था।

पदोन्नति के अवसरों का भी अभाव नहीं था। आकाशवाणी से टैलीविजन में आने पर वे प्रसन्न थे और उन्हें सहायक निदेशक का पद प्राप्त हुआ।

खोये हुई वस्तुओं के बारे में पुलिस जांच करेगी।

स्टाफ कलाकारों और आकाशवाणी के कर्मचारियों के वेतन पर हाल ही में वेतन आयोग में चर्चा हुई है। उसकी सिफारिशों, को लागू किया जा रहा है तथा उनके वेतन काफी अच्छे हो जायेंगे।

कुछ अन्य अप्रिय घटनाओं की भी चर्चा की गई हैं। मैंने उनकी जांच की है उनमें इस प्रकार के आरोपों का कोई कारण नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अन्य मंत्रालयों की तुलना में हमारे मंत्रालय में पारिवारिक वातावरण है। यहां तनावपूर्ण वातावरण होने का कोई कारण नहीं है। श्री ज्योतिर्मय बसु तो हर जगह तनाव देखना चाहते है। उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय में तनाव न पाकर दुःख हो सकता है।

इस सम्बन्ध में पुलिस जांच पूरी होने पर यदि आवश्यक हुआ तो और जांच करने पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री गौड़ के खिड़की से कूद पड़ने का कुछ तो कारण होगा ? उनकी पत्नी का कहना है कि किसी बात ने उन्हें उत्तेजित किया है ।

श्री आई० के० गुजराल : हमारी जानकारी में ऐसा कोई कारण नहीं आया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको इसकी जांच करानी चाहिए ।

श्री आई० के० गुजराल : यदि विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी तो मैं निश्चय ही उसपर विचार करूंगा ।

ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि श्री गौड़ मानसिक रोगी थे । उनके बारे में जो उनके अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट है वह अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): I am very sorry that with the sad demise of Shri Janki Nath Gaur we have lost a prominent artiste. This case of suicide is a matter of great sorrw. Shri Gaur was a successful artiste. In All India Radio he worked continuously on one post for 16 long years. He went to Germany to receive special training and on return from there has been working as an Executive in T. V. About three years ago, when an opportunity for his promotion came it was made impossible due to the remarks of his officer that it is impossible to spare him. The strain on his mind was, as such, natural. The doubt arises in public minds regarding promotional avenues for T. V. and A.I.R. staff.

I, therefore, stress upon the Government to institute an enquiry into the causes that led to the suicide of Shri Gaur. Does the Ministry approve of the setting up of a cell to attend to the grievances of these artiste's.

I hope the hon. Minister would give a balanced reply to my questions.

Shri I. K. Gujral: Shri Jagannath Mishra has almost repeated what Shri Indra Jit Gupta has said. Regarding the promotion of Shri Gaur it may be stated that he was appointed as Assistant Director w.e.f. 2nd. April 1973.

उपाध्यक्ष महोदय : उनका प्रथम प्रश्न यह है कि क्या उस बैठक में तनाव था जो कि उनकी आत्म-हत्या से कुछ समय पूर्व हुई थी; क्या श्री गौड़ ने कोई योजना पेश की थी जिसके प्रति टी० वी० संगठन ने उपेक्षा बरती; क्या आप टेलीविजन केन्द्र में एक सैल की स्थापना करेंगे तथा पूरे प्रश्न की जांच करायेंगे ।

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक बैठक का संबंध है उसमें तनाव का कोई कारण नहीं था । स्टेशन निदेशक वहां पर नहीं थे और कोई भी उनसे बड़ा अधिकारी वहां पर नहीं था ।

मुझे उनके द्वारा पेश की गई किसी योजना का पता नहीं है । उन्होंने अपनी सेवा के बारे में कोई अभ्यावेदन नहीं दिया था ।

जांच के बारे में अभी कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajanpur): The police cannot investigate the causes that led to the situation which resulted in his suicide. The hon. Minister has referred to creative artistes. Another artiste who was sent for training to Germany did not stay here and went back to Germany.

Why a creative Artiste community suicide? When an Artiste finds that his career is bleak, he is frustrated. The Government want committed persons in every field. An artiste can never be committed. He will be committed to his art only.

Full investigations of the affairs be made so that such things may not occur again.

Shri I. K. Gujral: One thing is common with Mishraji and myself. Both of us create news. But here what Shri Joshi has said about creative artistes is that they are sensitive persons. But there are two types of creative artistes. The Artistes of 1st type perform their job individually, while the artistes of other type do their jobs along with other artistes.

I feel that in our country we should create an environment wherein creative artistes are provided with opportunities so as to enable them to fully exhibit their creativity. If T.V. network is made an autonomous body it would be governed by so many separate rules. Since an artiste has to live in a society he has to bear some burden.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मंत्री महोदय ने स्वोकार किया है कि श्री गौड़ किसी मानसिक रोगसे पोड़ित नहीं थे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री गौड़ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले कलाकार को ऐसा गम्भीरतम कदम क्यों उठाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी को एक मार्मिक पत्र लिखा था मंत्री महोदय ने उस पत्र का क्या आशय लिया? मंत्री महोदय ने कहा है कि उनका मासिक वेतन 1100 रुपया था तथा उनकी पत्नी को 800 रुपया वेतन मिलता है। क्या टेलीविजन के लिये ऐसी सुन्दर फिल्में तथा वृत्त चित्र बनाने वाले कलाकार के लिये इतना वेतन पर्याप्त तथा न्यायसंगत है?

मंत्री महोदय ने कहा है कि टेलीविजन केन्द्र का पुनर्गठन किया जाएगा। क्या उन्होंने इसके लिये पर्याप्त धनराशि प्राप्त कर ली है? मुझे ज्ञात हुआ है कि न टेलीविजन सम्बन्धी उपकरण पर्याप्त हैं और न कर्मचारी। इस क्षेत्र में भी नौकरशाहों का प्रभुत्व हैं। एक सम्मेलन में, जिसका उद्घाटन मंत्री महोदय ने किया था, यह संकल्प पारित किया गया था कि इस विभाग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया बन्द की जाए। इस क्षेत्र में आई० ए० एस० अधिकारियों को लाने का क्या औचित्य हैं?

श्री आई० के० गुजराल : वेतन के बारे में मैंने यह कहा था कि पति-पत्नी की आय लगभग 2000 रुपया प्रतिमास थी तथा इस कारण उसे कोई ऐसा मानसिक तनाव नहीं था जिससे उसे आत्महत्या करनी पड़ती। एक समाचार-पत्र में प्रकाशित यह रिपोर्ट सच नहीं है कि टेलीविजन कार्यक्रम के लिये बाहर से आने वाले कलाकारों को अधिक धनराशि दी जाती है। टेलीविजन वृत्त चित्र के लिये 1,000 रुपयों से 3,000 रुपयों तक का भुगतान किया जाता है। यह कहना भी सच नहीं है कि विभागीय कलाकारों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। **(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या आपके मंत्रालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध असंतोष है?

श्री आई० के० गुजराल : संपूर्ण आकाशवाणी व्यवस्था में केवल दो आई० ए० एस० अधिकारी हैं, एक महानिदेशक और दुसरा उप महानिदेशक (प्रशासन)। उप महानिदेशक (प्रशासन) के अतिरिक्त अन्य सभी उप-महानिदेशक व्यावसायिक श्रेणी में से हैं। कुछ वर्ष पहले पद विवाद उत्पन्न हुआ था कि यदि उप महा निदेशक (प्रशासन) के पद पर आकाशवाणी की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों और स्टाफ आर्टिस्टों मे से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया तो वह सभी श्रेणीयोंके साथ न्याय नहीं कर सकता। इसी विचार को ध्यान में रखते हुये इस पद पर आई० ए० एस० का अधिकारी नियुक्त किया गया था।

मैं स्वयं इस पक्ष में हूं कि रेडिओ और टेलिविजन जैसे विभागों में पूर्णत: तकनीकी व्यक्ति होने चाहिए। सम्मेलन में भाग लेते समय भी मेरी यही धारणा थी। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी सेवा काल में रेडिओं और टेलिविजन विभागों का पुनर्गठन हो सकें। मैं इस दिशा में कदम उठा रहा हूं।

[श्री आई० के० गुजराल]

जहाँ तक उपकरणों का प्रश्न है मेरे विचारसे हमारे उपकरण किसी प्रकार घटिया नही हैं। हाल में हमने कुछ उपकरणों का आयात किया है। वास्तव में समस्या उपकरणों की नही वरन स्टूडियों की है। इस योजना में मण्डी हाऊस में एक स्टूडियों की मंजूरी दी गई है तथा उसका डिजाइन भी मंजूर कर लिया गया है।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

मंत्री महोदय द्वारा कथित गुमराह करनेवाली जानकारी देना

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : महोदय! विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति देने के लिये मैं आपका आभारी हूं। कर्फ्यु का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मार दिये जाने के आदेशको अवैध घोषित करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2093 के उत्तर में श्री एफ० एच० मोहसिन ने बताया था कि गुजराथ उच्च न्यायालय के धारा 144 के अन्तर्गत पास की गई किसी भी अधिसूचना को अवैध ठहराया गया है। राज्य सरकार अथवा पुलिस कमिशनर द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नही किया गया जिसके अन्तर्गत कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मार दी जाए।

मुझे गुजरात उच्च न्यायालय की फैसले की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध हो गई है जिसमें कहा गया है कि "हमारे विचार से 'महत्त्वपूर्ण घोषणा' में निहित कार्यकारी निदेशों में उन्होंने कर्फ्यू आर्डर को तोडने पर ही उन लोगों को गोली मार दिये जाने की धमकी देकर उन्हें प्राप्त शक्तियों का तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के विरुद्ध है तथा प्रभावहीन है।"

इससे स्पष्ट है कि मंत्री महोदय तथा उपमंत्री महोदय ने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है। यह गम्भीर मामला है तथा इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : महोदय, मुझे अभी-अभी यह सूचना मिली थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : प्रश्न गृहमंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित से पूछा गया था और श्री मोहसिन ने उनकी ओर से उत्तर दिया था। इतने गम्भीर मामले में मंत्री महोदय को सभा में उपस्थित रहना चाहिये था।

श्री एफ० एच० मोहसिन : विशेषाधिकार संबंधी प्रस्ताव की प्रति मुझे अभी-अभी मिली है। मैं कागजात देखुंगा तथा कल एक वक्तव्य दुंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उप राज्य पाल तथा भूमि के सौदे के बारे में श्री मिर्धा का उत्तर कुछ विवादास्पद था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस नियम 115 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति दे दी है तथा 19 तारीख को मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमारे पास ये दस्तावेज मौजूद हैं। हमें पता चला है कि उप राज्यपाल कुछ दस्तावेजों को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले उनसे त्याग पत्र दिलाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अत्यंत गम्भीर आदेश है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जांच करें।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा उत्तर की शुद्धि करने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सा० सां० नि० 321, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30, मार्च 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्ययाख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 322, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30, मार्च 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6709/74]**

(2) (एक) पांचवी लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले–विवरण संख्या 7 में, जो 27 जुलाई, 1973 को सभा पटल पर रखा गया था, मध्य प्रदेश में शीर्षस्थ व्यक्तियों से आयकर की बकाया राशि के संबंध में श्री जी० सी० दीक्षित के 18 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2765 के संबंध में दी गयी जानकारी को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण,

(दो) उपर्युक्त विवरण को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखा गया । दखिये लंख्या एल० टी० 6710/74]**

गुजरात पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1974

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गुजरात पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 8) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6711/74]**

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) (एक) औद्योगिक विकास मंत्रालय — औद्योगिक लाइसेंस संबंधी 50 वां प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(2) (एक) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय – भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण संबंधी 52 वां प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में समिति के बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

121वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मैं रक्षा उत्पादन के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1971–72 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (रक्षा सेवाएं), में दिये गये पैराग्राफों के बारे में लोक लेखा समिति का 121वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कानपूर के अस्पताल में नकली ग्लुकोज इंजेक्शनों के कारण अनेक रोगियों की मृत्यु के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : DEATHS OF SEVERAL PATIENTS IN KANPUR HOSPITAL DUE TO SPURIOUS GLUCOSE INJECTIONS

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : अध्यक्ष महोदय, कानपुर के अस्पतालों में ग्लूकोज सलाईन के इंजेक्शन लगाने से इक्कीस व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई यह घटना बहुत ही हृदयविदारक है । ग्लूकोज इंजेक्शनों से 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और बाकी आठ व्यक्ति, जिन्हें भी ग्लूकोज इंजेक्शन दिया गया था, अन्य गम्भीर बिमारियों से पीडित थे । उत्तर प्रदेश सरकार से की गई पूछताछ से पता चलता है कि मैसर्स बी० जी० फार्मा, कानपुर द्वारा बनाए गए 5% ग्लूकोज घोल के एक खास बैच से इन रोगियों की मृत्यु होने का अंदेशा है । मौतों की सूचना मिलने पर राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवाओं के संयुक्त निदेशक और राज्य औषधि नियंत्रक को यथा स्थल छानबीन करने के लिए कानपुर भेज दिया था । केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारी भी तुरन्त कानपुर चले गए है । एक तीन सदस्यीय समिति ने इन मौतों के कारणों की जांच की और पता चला कि उसने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फर्म के दो हिस्सेदारों को गिरफ्तार करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की है। उत्तर प्रदेश ड्रग कण्ट्रोलर, इस क्षेत्र के सीनियर ड्रग इन्स्पेक्टर तथा कानपुर के ड्रग इन्स्पेक्टर को निलम्बित कर दिया गया है । इस फर्म के तीन और व्यक्तियों की, जो फरार है, पुलिस द्वारा खोज की जा रही है। अस्पताल अधीक्षक को छुट्टी पर जाने क लिए आदेश दे दिए गए है। राज्य सरकार ने इस घातक औषधि के स्टाक को इस फर्म के यहां से जब्त करने के आदेश दे दिए है। इस ग्लूकोज घोल और ग्लूकोज पदार्थ के नमूने केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता को जांच के लिए शीघ्र भेजे जा रहे है। अस्पतालों और बाजार से इस घातक दवाई को हटाने के आदेश दे दिए गए है। अन्य राज्यों को भी सतर्क कर दिया गया है ।

केन्द्रीय और राज्य सरकार इस घटना को गम्भीर रूप से ले र है। दवाइयों में मिलावट करना एक अपराध है और हमारे विचार से दोषी व्यक्तियों को तुरन्त सजा मिलनी चाहिए और उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए । नकली दवाइयों के प्रश्न पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की हाल में हुई बैठक में

जिसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया था। उसमें यह निर्णय किया गया था कि दवाइयों में मिलावट की इस खराबी को दूर करने के लिय देश-व्यापी आधार पर ठोस और समन्वित प्रयास किये जाने चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला नियम 377 के अन्तर्गत उठाया गया था तथा मंत्री महोदय ने उसके उत्तर में यह वक्तव्य दिया है। मैं इसे विशेष मामला मानता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आज के समाचार पत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सालिगराम जायसवाल इस मामले पर अपना त्यागपत्र देना चाहते थ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस फर्म के दो साझीदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो घातक वस्तुओं का उत्पादन करते रहे है किन्तु उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्यों कि कुछ समय पूर्व उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वे रोहतगी परिवार से सम्बन्ध रखते है। एक व्यक्ति फरार है तथा मुझे प्रसन्नता है कि मुख्य मंत्री ने उसकी सम्पत्ति जब्त किये जाने के आदेश दिये है। मेरा सुझाव है कि इस मामले को राज्य की पुलिस के उपर न छोडा जाये। स्वास्थ्य मंत्री तथा गृह मंत्री मिलकर इस मामले पर निर्णय करें तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों को यह पता लगाने का आदेश दे कि जाली दवाइयों के उत्पादन में किस-किस का हाथ है। जो व्यक्ति उसके कारण मरे है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाये। मेरा अनुरोध है कि इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कराई जानी चाहिये।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मंत्री महोदय ने यह नही बताया कि इन व्यक्तियों पर औषधि नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत प्रकरण न चलाकर आम अपराध कानूनों के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे है? क्या सरकार इनके विरुद्ध धारा 302 के अधीन मुकदमा चलायेगी? दूसरे मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये की मृतकों के परिवारों को तुरंत पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। तीसरे, मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्युरों द्वारा कराई जायें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस फर्म को कब सपलायर बनाया गया था ?

डा० कर्ण सिंह : मुकदमा चलाये जाने के प्रश्न पर कानूनी सलाह लेनी होगी। दुर्भाग्य से इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिक से अधिक 10 वर्ष के कारावास की व्यवस्था है।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कानून की गिरफ्त में न आ सके। यदि कोई जानकारी दी जाये तथा कोई प्रमाण दिया जाये तो मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार अवश्य ही तुरंत कार्यवाही करेगी। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समस्या से निपटने में सक्षम है तथा उसे यदि केन्द्रीय सरकार से किसी सहायता की आवश्यकता हुई तो हम सहायता देने को तैयार है।

मुआवजे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। मैं इस मामले पर मुख्य मंत्री से विचार-विमर्श करूंगा। यह सच है कि देश में दवाइयों में मिलावट की अनेक घटनायें हो रही है। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इस मामलों को आपराधिक कानूनों को लागू किया जाये। जहां तक इस मामले में अन्तर्राज्यीय गिरोहों का सम्बन्ध है हमारी अपनी भेषज संस्थाए इससे अवगत है तथा मैं आश्वासन देता हूं कि इस मामले में सभी सम्भव कार्यवाही की जाएगी।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

वियतनाम में अमरीकी सेनाओं के बारे में प्रधान मंत्री के विचारों के बारे में समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में "मिसेज गांधी फेवर्ड यू० एस० ट्रुप्स इन वियतनाम" शीर्षक के अन्तर्गत इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके सहयोगियों ने श्री ह्यूबर्ट हैंफ्री से गुप्त रूपसे यह कहा था कि अमरीकी सेना का वियतनाम में होना अनिवार्य है। श्री हंफ्री ने यह दावा दि न्यूयार्क टाइम्स, दिनांक 15 अप्रैल, 1974 को दिये इन्टरव्यू में किया था। हम चाहते है कि इस बात का स्पष्टीकरण दिया जाये।

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): मैं इसका उत्तर अवश्य देना चाहूंगी।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह वक्तव्य सर्वथा निराधार है। ऐसे मामलों और विशेषकर वियतनाम में विदेशी सेना के संबंध में मेरे विचार सर्वविदित है। मेरे ये विचार मेरे सरकार में आने से पूर्व के है और मैंने अपने इन विचारों को 1961 में जब मैं अमरीका गयी थी तो मैंने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया था। बाद में जब मैं 1966 में सरकारी अतिथि के रूप में अमरीका गई थी, तो मैंन अपने इन विचारों को निजी और सार्वजनिक रूप से भी व्यक्त किया था। या तो उप राष्ट्रपति के वक्तव्य को ठीक प्रकार से प्रकाशित नहीं किया गया था किसी और के विचारों को मेरे विचार समझ रहे है। मैं यही निष्कर्ष निकाल सकती हूं। इस मामले पर मेरी भावनायें बहुत सी तीव्र है। वास्तव में हमारी सरकार के प्रति अमरीकी प्रशासन की नाराजगी का यह एक मुख्य कारण था। हमें प्रायः यही बताया जाता है कि हम लगभग सभी अन्य देशों की अपेक्षा अधिक कड़े शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करते है।

रेलकर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित रेल हड़ताल के बारे में
RE : PROPOSED STRIKE BY RAILWAYMEN

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों पर चर्चा को जारी रखेंगे . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सात ईरानी छात्रों को इस देश से निकाला दिया गया है . . . (**व्यवधान**)।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) श्रीमान जी, रेल कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने हड़ताल का नोटिस दिया है। अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री जय प्रकाश नारायण ने रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और रेल कर्मचारियों को अपील की है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में बातचीत द्वारा समझौता कर लिया जाये मैंने उसके लिये सूचना दी हुई है। रेल मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ बताना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अभी उनसे मिलना है। यही कुछ मुझे बताया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम यह चाहते है कि रेल मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि बातचीत द्वारा समझोता कर लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आज प्रात: मैंने इन सूचनाओं को देखा तो मेरी प्रथम प्रतिक्रिया यह थी कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि रेल कर्मचारियों ने 8 मई से हड़ताल करने की धमकी दी है। किन्तु फिर मुझे यह बताया गया कि मंत्री महोदय ने उन्हें फिर से बातचीत करने का निमंत्रण दिया है। मेरे विचार में यही उचित होगा कि हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिये और मंत्री महोदय को एक और अवसर देना चाहिए और उपयुक्त समय पर इस मामले पर विचार कर लिया जाये।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह आपकी धारणा है कि बाद में अर्थात 18 तारीख के बाद हमें इस मामले पर विचार करने का अवसर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में हम बाद में विचार करेंगें।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतुर) : कल बातचीत के समय हमें बताया गया था कि किसी मांग पर बातचीत नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह किस प्रकार जान सकता हूं कि वह 18 तारीख को क्या कहेंगे। यदि वह बातचीत नहीं करना चाहते तो उन्होनें उनके निमंत्रण क्यों दिया ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं आप को इस का कारण बताता हूं। उन्हें बातचीत का निमंत्रण दिया गया और उन्होनें पाया कि रेलवे बोर्ड के केवल एक ही सदस्य, जो कर्मचारी संबंधी मामलों के प्रभारी है, मौजूद थे।

कोई मंत्री उपस्थित नहीं था। जब उन्होनें यह पूछा कि क्या इस विषय पर सरकार का यह अन्तिम निर्णय है, तो उन्हें श्री एल० एन० मिश्र द्वारा सुचित किया गया कि इस विषय पर सरकार का यह अन्तिम निर्णय नहीं है और यदि वह चाहें, तो उन्हें 18 तारीख को मिल सकते है। हम यह जानना चाहते है कि क्या सरकार ने नीति के रूप में उनको बातचीत करने का निर्णय कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपने प्रश्न का उत्तर यह कह कर अपने आप दे दिया है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि यह अन्तिम निर्णय नहीं है . . . (**व्यवधान**) हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह सच है कि मंत्री महोदय उनसे 18 तारीख को मिलेंगे। किन्तु उत्तर सीमान्त रेलवे और कानपुर में पहले ही नियम अनुसार कार्य किया जा रहा है। हम यह नहीं चाहते कि रेलों का चलना बन्द हो जाये। मैं आप से यह प्रार्थना करता हूं कि आप रेल मंत्री से कहें कि वह तुरन्त एक वक्तव्य दें, अन्यथा रेलों का चलना ठप्प हो जायेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि आज उसी दिन का एक दर्शक कार्ड जारी किया गया है। उसके कार्ड के शिखर पर यह लिखा हुआ है **"सदस्य द्वारा परिचय कराया जायेगा"** . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे मिलें या इसके बारे में मुझे लिखें। कोई मंत्री इसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : सदस्यों के लिये यह कैसे सम्भव हो सकता है कि वे हर समय परिचय कराते रहे . . .

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। जहां वे प्रश्न पूछे जाते है जिनका उत्तर मंत्रीगण ही दे सकते है । यह एक ऐसा मामला है जिसका संबंध अध्यक्ष के उत्तरदायित्व से है। आप मुझे लिखें या मुझे मिलें। यदि कोई गलती हुई होगी, तो मैं इस पर ध्यान दूंगा और इस गलती को सुधारूंगा। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं। कृपया इस मामले को यहां न उठायें ।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda): At the time of inauguration of first boiler of Thermal Plant at Bhatinda by the Chief Minister of Punjab, one of the Directors has issued a statement that this plant would not function properly due to non-availability of adequate supply of coal, because there is acute shortage of coal. Government wants to commission this plant in July, but they are not supplying coal to them, how would it function?

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। प्रतिदिन कुछ सदस्य आप का ध्यान उन मामलों की और दिलाते रहते है जिनके बारे में हम समझते है कि उनपर सभा में विचार किया जाना चाहिये और अधिकतर ये मामले विशेष रूप से उन क्षेत्रों के संबंध में होते है । जहां न तो लोकप्रिय सरकार है और न ही विधान सभा है। दुर्भाग्यवश आज गुजरात भी एक ऐसा राज्य है । और कई ऐंसी समस्याएं हैं जिनका हम सामना कर रहें है मैं यह तभी करूंगा कि एक विशेंष प्रस्ताव दूसरें प्रस्ताओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण या अधिक । . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह महसुस कर सकते है कि आप को एक शिकायत है। कृपया किन्तु आप मेरी स्थिति को समझिये । मुझे 30 अथवा 40 या 50 सूचनाओं में से एक को चुनना होता है । इस बारे में निर्णय करना होता है कि कौनसा मामला अधिक आवश्यक है । आप इस पर आपत्ति कर सकते है । किन्तु आप को यह बात समझनी होगी कि हम एक या दो मामलो पर विचार कर सकते है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं आपकी बात की सराहना करता हूं और इस बारे में आपसे सहमत हूं किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात में कुछ ऐसी घटनायें हो रही है जिनका उन घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है जिनके परिणाम स्वरूप बिधान सभा भंग हुई थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): You have just now said that the hon. Railway Minister is ready to have negotiations with the Railway Trade Unions. It is true, but on the one hand he talks of holding negotiations and on the other, the railway workers are being victimised on a very large scale and they are being transferred . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसी मामले को उठा रहे है ।

Shri Ramavatar Shastri : This morning the leaders of the All India Railwaymen's Federation had met him... (*Interruptions*)... If he wants to have negotiations, he should stop such things and hold talks for the settlement.

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में उन्हें बता दिया जायेगा।

अनुदानों की मांगें 1974-75—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—1974-75—*Contd.*

इस्पात और खान मंत्रालय

Shri Chandulal Chandrakar (Durg): Yesterday, I was saying that the officials of steel plant's take petty matters concerning the labourers working there to the Labour Courts. They waste much money in litigation instead of paying smaller amount to the workers. I hope the hon. Minister would redress this kind of injustice.

[**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** पीठासीन हुये
SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*]

The Labourers working in Steel Plants got lesser wages in 1973-74 that what they got in 1972 73. They also got lesser incentive bonus on account of fall in production due to shortage of coal. I hope the Hon. Minister would look into the matter and would also see that the labourers specially the labourers working in Bhilai Steel Plant are paid more bonus, who have the privilege of record production.

I would also request the Hon. Minister to take immediate steps to make available essential commodities of daily use to them at fair prices.

The system of recruitment in Public Sector Undertakings, industrial establishments and corporations, which are autonomous, should be improved. Jobs should also be provided to the needy. If steps are not taken immediately to provide employment to people of Madhya Pradesh in Bhilai Steel Plant and Hindustan Steel Works Construction Company, a very explosive situation is likely to arise. I would request the Hon. Minister to look into the matter and do justice to the sons of the soil.

In this connection, it can be suggested that the names of candidates suggested by Employment Exchange for recruitment should be displayed prominently on the Notice Boards and also the names of the candidates finally selected and the reasons for not selecting the other candidates should also be mentioned. It is said that bribe has to be given even for pronouncing the names of selected candidates. An enquiry committee should be appointed to find out the names of the officers and contractors who have indulged in corrupt practices in the matter of recruitment. Also priority should be given in the matter of appointment to the members of those families whose lands have been acquired for setting up the Steel Plants.

Then the selection board for recruitment should consist of 50 per cent members should be the representatives of the State Government. The facility of Leave Travel Concession should also be accorded to the local people who have been employed in the Bhilai Steel Plant. The labourers working in that steel plant have no houses to live in and so the efforts should be made to construct and provide more and more houses to them, but one-roomed tenements should not be constructed. Then the Steel Ministry should also make arrangements to provide drinking water and roads in the labour residential colonies.

The Town Administration in Bhilai is not giving proper attention to this. In the beginning they allow the people to construct huts etc. but they try to remove them after one year or 1½ years, because they earn individual income by doing so.

Workers are retrenched in steel plants or they are transferred without assigning any reason therefor. An worker, who is retrenched, must be told the reasons therefor.

There is a good deal of bungling in the sale of scrap iron and coking coal powder. They should be sold through public auction to the highest bidder.

[Shri Chandulal Chandrakar]

Bhilai Steel Plant has 50,000 acres of land, but the actual steel plant covers only 5,000 acres with the result that a vast land has gone into the unauthorised occupation. If this land is sold, it can fetch 1-2 crores of rupees. There is a co-operative farm in several thousand acres of land. This is Employees Cooperative farm, the expenditure is incurred by the plant on water, power, tractors etc., but income of the farms goes only to some persons. The local people have demanded land for agricultural purposes on annual lease, so that this land may be utilised by them until it is required by the plant.

Moreover, there are complaints that in the steel plant, machines or tractors are sold without inviting tenders to outsiders and not to the local people. I would request the Hon. Minister to look into this matter.

Shri Prabodh Chandra (Gurdaspur): I want to draw the attention of the Government towards a few things.

The steel industry is the most important industry in the economy of the country. But there has been several shortcomings in the proper functioning of this industry and nothing has been done during the last several years to rectify the neglects that have been conducted. There were no refractories attached to the steel plants. If such refractories are set up, it would certainly help to bring about an increase in production. Efforts should be made to make each steel plant self sufficient. The steel plants should lay their own railway lines so that they can take their goods to railheads. If the thermal plants are set up at pit-heads, it would facilitate the entire productive process in steel plants. If the Depots should be set up near the main lines at a distance of 30 or 40 miles, you would have control over it and these would be no pilferage.

Regarding manganese, an enquiry should be made into the case in which the manganese ore exported to Japan last year was returned by them on the ground that it was substandard and the responsibility should be fixed for the heavy losses incurred by the country.

I would request you to make efforts to make the existing industrial units stronger rather than investing money in setting up new industries. I believe the Hon. Minister would take steps to reduce the expenditure in setting up steel mills.

श्री सी० टी० दंडपाणि (धारापुरम) : मुझे इस बात में संदेह है कि इस्पात और खान मंत्रालय के प्रभारी मंत्रियों ने इस मंत्रालय के महत्व को, ठीक तरहसे समझा है। इस मंत्रालय का दावा है कि उसका कार्यकरण बहुत अच्छा और उत्साहवर्धक है। किन्तु, जब हम परिणामों को देखते हैं, तो पता चलता है कि मंत्रालय के नियंत्रण में जो एकक ह, उनके उत्पादत से उनका लाभ साधारण लोगों की बजाये बड़े लोगों को पहुंच रहा है। निर्मित इस्पात, अलुमिनियम धातु, पिण्ड स्टेनलेस इस्पात और अन्य वस्तुओं का वितरण अनुचित ढंग से किया जा रहा है और केवल बडे लोगो को ही ये वस्तुएं प्राप्त हो रही है।

दूसरे, हजारो जाती एककों इस मंत्रालय में पंजीकृत है जो इस्पात का कोटा अपने वास्तविक उपयोग में न लाकर चोर बाजारी कर के बहुत अधिक लाभ कमा रहे है। मंत्रालय को इस्पात की वितरण व्यवस्था या तो अपने हाथों मे ले लेनी चाहिये या इसे राज्य सरकारों को सोप देनी चाहिये, ताकि लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिये इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकें।

री-रोलर्स की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें 'स्क्रैप' प्राप्त नहीं हो रहे है। इसके साथ ही समूचे भारत में 116 बडे बिलट री-रोलर्स की ही सारी आयातित और देशीय 'स्क्रैप' मिल रहा है। 748 लघु, री-रोलर्स लघु उद्योगों के रूप में पंजीकृत है किन्तु 'स्क्रैप' प्राप्त नहीं हो रहे है। अत: इस मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

जहां तक धातु पिण्ड इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात का संबंध है, भिलाई, दुर्गापूर और राउरकेला, इन तीनों मुख्य संयंत्रों का कार्यसम्पादन बहुत ही असंतोषजनक है किन्तु दुर्गापूर और राउरकेला की अपेक्षा भिलाई संयंत्र का कार्यसम्पादन कुछ बेहत्तर है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि कटु औद्योगिक सम्बन्धों से दुर्गापूर और राउरकेला में उत्पादन कम हुआ।

जब भिलाई में श्रमिक प्रबन्धक सम्बन्ध बेहत्तर और अच्छे हो सकते है, तो अन्य दोनों इस्पात संयंत्रो में ऐसे श्रमिक संबंध स्थापित क्यों नहीं किये गये।

श्री मालवीय समाजवादी तथा मजदूर संघ के बहुत बड़े नेता है। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि वह श्रमिक संबंधों की समस्या का समाधान क्यों नही कर सकें।

नेवेली में भी श्रमिक संबंधों की समस्या विद्यमान है। प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच पुराने समझौते की अवधि समाप्त हो चुकी है। नेवेली में श्रमिक संघ और प्रबन्धकों के बीच नया समझौता होने वाला है। नेवेली के वर्तमान प्रबन्धकों के मूल वेतन के रूप में तदर्थ भुगतान करने का जो प्रस्ताव किया है, वह बहुत ही अनुचित है। किन्तु, इसके साथ ही प्रबन्धकों ने यह भी कहा है कि उन्हें बहुत घाटा हो रहा है। जहां तक श्रमिकों के कार्य निष्पादन का सम्बन्ध है, कोई भी घाटा नहीं हुआ है। इस एकक को इन वर्षों के दौरान 12 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ है। अतः सरकार को इस मामले पर अविलम्ब विचार करना चाहिये।

इसके साथ ही लिग्नाइट और विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता का उल्लेख किया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप म तामिलनाडू में नेवेली के लिये दुसरे खान क्षेत्र और 1000 मेगावट बिजली देने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध लोगों में उत्तेजना और असंतोष व्याप्त है। यदि अब दूसरे खानक्षेत्र को स्वीकृति प्रदान न की गयी, तो तामिलनाडू में उद्योग और कृषि के भविष्य और सामान्य आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

तामिलनाडू में कोयले की बहुत कमी है। कोयले और मट्टी तेल की अनुपलब्धता के कारण सीमेंट के कारखानों में उत्पादन बहुत ही कम हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप सीमेंट के कारखाने बन्द हो गये। इससे बेरोजगारी बहुत बढ़ गयी है। और इससे मुख्य विकास कार्यों को भी क्षति पहुंची है।

कोयला की अनुपलब्धता के कारण बिजली घट विशषकर एलोर और बेसिल ब्रिज के बिजली घर अधिक बिजली पैदा करने की स्थिति में नहीं है। तामिलनाडु विद्युत बोर्ड की आवश्यकता 4800 टन की है किन्तु बिजली की सप्लाई 40 प्रतिशत से कम है और अपेक्षित मात्रा में कोयला समय पर उपलब्ध नहीं किया गया, तो बिजली की सप्लाई और कटौती होने की सम्भावना है। इस पुस्तक में प्रकाशित आंकडो से पता चलता है कि कोयले का उत्पादन बढ़ गया है। कोयले के बारेमें जब हम इस्पात और खान मंत्री से बात करते है, तो वह कहते है कि कोयला उपलब्ध है, परन्तु उसक परिवहन के लिये वगन उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में जब रेल मंत्री से बात करते है तो वह कहते है कि वैगनों की तो कोई कमी नही है, कोयला ही उपलब्ध नहीं है। जब परिवहन मंत्री से बात की जाती है तो वह कुछ और ही ढंग दिखाते है। उनका कहना होता है कि कोयला और वैगन दोनों ही उपलब्ध नहीं है। अतः तीनों ही मंत्रियों या उनके मंत्रालयों में किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। सभी अपने दायित्व को दूसरे पर लादने के प्रयत्न में रहते है।

10—14L.S.S.74

[श्री सी० टी० दंडपाणि]

अन्त म में सलेम इस्पात संयंत्र के बारे में एक दो शब्द कहना चाहता हूं। इस संयंत्र के लिए 1974–75 के बजट नियतम में निर्धारित राशि 5 करोड़ रुपये से घटाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई है। मेरे विचार से इस मूल नियतन के फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी और लगभग 7,500 मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। इस परियोजना के कार्य में आगे होने वाली प्रगति रुक जायेगी और इसक पूरा होने में भी विलम्ब होगा। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिये कि क्या सरकार का विचार इस परियोजना को बंद करने का है।

हमारे वर्तमान इस्पात और खान मंत्री, श्री के० डी० मालवीय ने 4 मई, 1972 को किसी सन्दर्भ में कहा था कि हमें सम्पूर्ण इस्पात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। आज मैं उनसे इसी सन्दर्भ में पुनः यह पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी यह उत्पादन के सम्पूर्ण ढांच को बदल कर राज्य के नियंत्रण में दोने के पक्ष में हैं। क्या सरकार समस्त इस्पात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है?

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : मैं पहले कोयले के उत्पादन, वितरण और उसके मूल्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज स्थिति यह है कि इस्पात और खान मंत्रालय में विद्यमान अक्षमता, भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन के परिणामस्वरूप लोगों का विचार है कि राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य असफल हो गया है। यह दावा किया गया है कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है यदि यह सत्य है तो फिर कोयले की कमी क्यों है और यदि कोयले की कमी नहीं है तो फिर इतनी गाड़ियां रद्द क्यों की गई हैं?

आज स्थिति यह है कि सरकार जब कभी भी अपने आप को संकट में पाती है, वह श्रमिकों पर दोष लगाना आरम्भ कर देती है। क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह एक आदर्श नियोजक की भांति कार्य करे। वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार श्रमिकों की समस्याओं के प्रति उदासीन रहती है। ऐसा करना सरकार के लिए उचित नहीं है।

अब समन्वय के प्रश्न को ही लीजिये रेल मंत्रालय और इस्पात तथा खान मंत्रालय एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। वह समस्या के मूल तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते। कोयले के मूल्य में आज 200 से 300 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है और आश्चर्य की बात यह है कि यह वृद्धि केवल दूरस्थ स्थानों पर ही नहीं हुई, अपितु कलकत्ता तथा रांची जैसे कोयला क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी हुई है।

कोयले की कमी के कारण कई औद्योगिक एकक, इंजीनियरी एकक, ईंट निर्माता तथा वस्त्रों की मिले अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए बाध्य हो गये है। इसके बावजूद भी सरकार ने इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

मेरे विचार से वर्तमान स्थिति का कारण उत्पादन की कमी और समन्वय का अभाव रहा है। सरकार के अनुसार यदि उत्पादन में वृद्धि हुई है तो फिर बी० सी० सी० एल० और सी० एम० ए० एल० में 30 करोड़ रुपये की हानि क्यों हुई है? सरकार को यह बताना चाहिये कि न्यायालय आदेशों के उपरान्त भी राष्ट्रीयकृत बैंकों को 10–15 करोड़ रुपये का भुगतान क्यों नहीं किया गया है? कुछ विदेशी कम्पनियों को 2 करोड़ रुपये क्यों दिये गये हैं। विदेशी कम्पनियों को अधिकाधिक धन दिया गया जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों को इससे वंचित रखा गया। यह मेरा सरकार पर आरोप है।

सरकार को यदि विश्वास है कि उत्पादन में कमी नहीं हुई है तो उन्हें वर्ष 1970, 1971, 1972 और 1973 के लिए जनवरी-जून तथा जून-दिसम्बर के उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिये। यह आंकड़ बड़ौदा-भावनगर-पूना और खूंदामर्दाह खानों के बारे में दिये जाने चाहिय।

अब मैं सरकार का ध्यान पुनर्वेल्लन मिलों से सम्बद्ध समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। दो मंत्रालयों के बीच मतभेद का यह बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। रिरालिंग मिलों के बारे में जब वित्त मंत्रालय से बातचीत की गई तो, उनका उत्तर था कि जब तक यह मामला न्यायालय के पास है तब तक इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। यह मामला न्यायालय को इसलिए सौंपना पड़ा क्योंकि स्थानीय प्राधिकारियों तथा अधीनस्थ प्राधिकारियों ने इससे कोई सही और तर्क संगत निष्कर्ष नहीं निकाला। इनके उत्पादन शुल्क के बारे में जो विवाद चल रहा है, उसे इस्पात तथा खान मंत्री और वित्त मंत्री को एक साथ बैठ कर हल करना चाहिये।

अन्त में मैं सरकार का ध्यान एक साधारण से मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस मामले का सम्बन्ध केवल एक कर्मचारी को ही जाने वाली पेंशन से है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व उसे पेंशन दी जाती थी। यह साधारण प्रश्न असाधारण महत्व का इसलिए बन गया है कि इसके पीछे सिद्धांत का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकरण के बाद भी गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन को जारी रखगी या नहीं। मैंने इस सम्बन्ध में भूतपू मंत्री महोदय को भी लिखा था। मंत्री महोदय को इसके बारे में शीघ्र विचार कर, अपना निर्णय देना चाहिये।

डा० महिपतराय मेहता (कच्छ) : मैं इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि स्वर्गीय श्री कुमार मंगलम के नेतृत्व में जो कार्य आरम्भ किया गया, उसे वैसी ही विचार-धारा वाले नेता श्री के० डी० मालवीय द्वारा पूरा किया जा रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि 1971 में जो उत्पादन 466 करोड़ रुपये का था, 1973 में वह बढ़ कर 521 करोड़ रुपये का हो गया। परन्तु इस उत्पादन वृद्धि के साथ जो समस्या हमारे सामने आई है, वह है उचित वितरण की। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप सड़क का यातायात काफी महंगा हो गया है, अत: उसमें काफी कमी आई है। परन्तु इसके बावजूद भी आज वास्तविक स्थिति यह है कि सैकड़ों ट्रक लदान के लिए कोयला खानों के पास खड़े रहते हैं। एक ट्रक को यदि एक दिन भी अधिक रोका जाये तो उसके लिए 250 रुपये देने पड़ते हैं। इसी सम्बन्ध में यह आरोप भी लगाया गया है कि ट्रक में 10 टन कोयला लादा जाता है परन्तु कम्पनी को केवल 5 टन का ही लाभ दिया जाता है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। गुजरात राज्य को हर महीने 19,000 वैगन कोयले की आवश्यकता होती है परन्तु इसे केवल 10,000 वैगन कोयला दिया जा रहा है। फलस्वरुप अनेक मिले बंद होने की स्थिति में है। सरकार को स्थिति में सुधार करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

गुजरात में 1952 में लिग्नाइट का पता लगा था। उस समय सौराष्ट्र एक अलग राज्य था। अब वर्ष 1974 चल रहा है परन्तु अभी तक किसी प्रकार का लाभ उठाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। लिगनाइट से कार्बन बनाया जा सकता है, इसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

अल्युमिनियम और बोक्साइट को ही लीजिये। मैंने हंगरी का दौरा किया था। कच्छ और हंगरी में स्थिति एक जैसी थी। हंगरी में भी लिग्नाइट और बौक्साइट साथ साथ ही मिलें थे। परन्तु वहां इनका पूर्ण उपयोग कर लिया गया। हमारे यहां अभी इस सम्बन्ध में कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। सरकार को इन निक्षेपों से भरसक लाभ उठाने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये। परन्तु यह खेद की बात है कि सरकार कारखाने आदि लगाने के लिए जो भी निर्णय करती है, वह राजनीतिक आधार पर करती है। जब भी कोई राजनीतिक आन्दोलन अधिक बलशाली हो जाता है, तभी सरकार उसके आगे झुक कर अपना निर्णय बदल देती है। यही प्रमुख कारण है कि हमारे इस्पात संयंत्र सफल नहीं हुये है। सरकार को इनके बारे में निर्णय करते समय गुण दोषों के आधार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये।

कोयले की सप्लाई ठीक ढंग से की जानी चाहिये। कोयला वैगनों से कोयला चोरी हो जाता है। फलस्वरूप उसकी कीमतों में और वृद्धि होती है क्योंकि वह महंगे दामों पर पहुंचता है। इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

[डा० महिपतराव मेहता]

अब इस्पात को ही लीजिये। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इस उद्योग की स्थिति काफी पतली हो गई है। इसमें भ्रष्टाचार और चोरबाजारी में काफी वृद्धि हुई है। अगर हमें वास्तव में समाजवाद की ओर अग्रसर होना है तो हमें इन सब ओर पूर्ण ध्यान देना चाहिय।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): The hon. Minister is responsible for steel and mines which are of vital importance for the country. These things can make the country self-sufficient. In reply to a question, it was stated by hon. Minister that a cell has been established for co-ordination, direction and to increase the production sources in the Steel industry. He also stated that he is interested to give more autonomy to different units. I am at a loss to understand as to whether the job of Ministry is just to formulate the national policy and fix the targets and for all other things Cell is responsible. If this is the case, we will have to reconsider whether 'Cell' is fulfilling the purpose for which it was established? It is felt that this cell is becoming a top-heavy administration. The time has come when Government will have to change its policy of allotting steel directly to DGTD from steel plants, because it adversely affects the small scale industries.

[**श्री इसहाक सम्भली** पीठासीन हुए
SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

It has been observed that the production of coal has gone down after the nationalisation of coal mines. Why is it so? It appears that the lack of coordination between the production and distribution is the main reason for it. A good number of labourers from 22 districts of Eastern U.P. used to work in the coal mines but now many of them are unemployed. Late Shri Mohan Kumaramangalam, the then Minister for Steel and Mines assured on 14th March, 1973 that Gorakhpur Labour Depot will continue to enjoy its special employment exchange, Hospital, Labour Centre and some other facilities. But now, no proper heed is being paid to uphold this assurance. All these matters should be properly looked into.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस्पात के क्षेत्र की सफलता और असफलता का प्रभाव सम्पूर्ण देश के विकास कायक्रम पर पड़ता है। अत: इस पर विचार करते समय हमें भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पुर्ननिर्माण, उत्पादन बढ़ाने और इस्पात कारखानों की कार्यकुशलता तथा उनसे सम्बद्ध नीतियों आदि के बारे में विचार करना होगा।

आज स्थिति यह है कि जब भी किसी क्षेत्र में सरकार की असफलता की आलोचना की जाती है. सरकार तुरन्त उसका उत्तर देती है कि यह तो विश्वव्यापी घटना है। जब कभी मूल्यों की वृद्धि, अखबारी कागज की कमी आदि की बात की जाती है तभी सरकार यह तर्क प्रस्तुत करती है परन्तु वह इस ओर कोई ध्यान नहीं देती कि विश्व में अन्य सभी क्षेत्रों यथा उत्पादन आदि में कितनी वृद्धि हुई है। इस ओर भी ध्यान देकर सरकार को अपना तर्क प्रस्तुत करना चाहिये।

उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिक समस्याओं के साथ साथ उन्हें हल करने के ढंग की ओर भी हमें उचित ध्यान देना चाहिये। केवल इस्पात संयंत्रों के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने मात्र से उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। उद्योग के आर्थिक अनुशासन और स्वस्थ्य औद्योगिक सम्बन्धों पर यह काफी सीमा तक निर्भर करता है। सरकार द्वारा इस पहलू की काफी उपेक्षा की गई है अत: इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

बोकारों इस्पात संयंत्र के निर्माण इंजीनियरों की कुछ शिकायतें हैं। 30 मार्च को, उनमें से 1500 इंजीनियर प्रबंध निदेशक से अपनी आर्थिक मांगों के सम्बन्ध में मिलने के लिए इकठ्ठे हुये थे। परन्तु

खेद की बात यह है कि प्रबन्ध निदेशक ने बजाये उनसे बात करने के उन पर लाठी चार्ज करवा दिया। उन में से 700 व्यक्तियों को गिरफ्तार करवा कर ट्रकों में पुलिस स्टशन भिजवा दिया गया। मैं इससे सम्बद्ध चित्र भी प्रस्तुत कर सकता हूं।

आप फोटो से देख सकते हैं कि निश्चित रुप से वे कई सौ हैं। भ्रष्टाचार के मामलों को 60 प्रतिशत के बजाय 68.5 बताया जाय तो उससे उस बात का खण्डन नहीं होता।

मजदूर संघ को मान्यता देने का प्रश्न भी है। खानें इस्पात और खान मंत्रालय क अधान आती हैं, इसलिए मान्यता देने के प्रश्न पर भी इस मंत्रालय को विचार करना चाहिए। 9 अप्रैल, 1974 को बौलिया क्वेरी मजदूर संघ कार्यालय पर इन्टक के कार्यकर्ताओं ने सशस्त्र हमला किया, जिसमें 31 मजदूर घायल हुए। हिंद मजदुर सभा से सम्बन्धित मजदूर संगठन 35 साल से मान्यताप्राप्त है। मैंने इस बारे में ध्यानकर्षण प्रस्ताव और नियम 377 के अधीन नोटिस भी दिया था। मंत्री महोदय इस मामले पर भी विचार करें।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० का पुनर्गठन करने की भी समस्या है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० का उत्पादन के क्षेत्र में कार्यकरण भी बहुत असन्तोषजनक रहा है। व अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने में भी सफल नहीं हुए हैं। नियंत्रक कम्पनियों और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के बेतरतीब विकास को रोका जाना चाहिए। नियंत्रक कम्पनियाँ सरकारी क्षेत्र का पुनर्गठन करने का प्रयास कर रही हैं। नियंत्रक कम्पनी को उन वित्तीय संस्थानों की ओर से भी काम करना चाहिए, जिनके गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में शेयर हैं।

दुहरी मूल्य-नीति में भी काफी गड़बड़ी हो रही है। इस प्रक्रिया के कारण रेलवे, सरकारी उपक्रम और महत्वपूर्ण क्षेत्र को उचित मूल्य पर इस्पात का आवंटन किया जायगा। दुहरे मुल्य के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। महाराष्ट्र में नकली लघु उद्योग कारखाने, जिनका कागज पर ही अस्तित्व है, स्टील का कोटा प्राप्त करके चोर बाजार में बेच रहे हैं। मंत्री महोदय को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। भ्रष्टाचार को दूर किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच अच्छे सम्बन्ध हों और कार्यकुशलता तथा उत्पादन में वृद्धि हो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय सवा पांच बजे बहस का उत्तर देंगे।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : इस्पात और कोयला ऐसे दो मूलभूत पदार्थ हैं, जिन पर सारे देश का विकास निर्भर करता है। मैं केवल कोयले के बारे में ही चर्चा करूंगा। सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और इनका प्रबन्ध कोयला खान प्राधिकरण तथा भारत कोकिंग कोल लि० संभाल रहे हैं। कोयला खान प्राधिकरण के अधीन 341 कोयला खानें हैं और भारत कोकिंग कोल लि० 390 कोयला खानों का प्रबन्ध संभाल रहा है। इस प्रकार सारे प्रबन्ध को एक समन्वित तरीके से पुनर्गठित करना सम्भव है।

अनेक सदस्यों ने कोयले के बढ़ते हुए उत्पादन के बारे में शंका व्यक्त की है। आँकड़ों से पता चलता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 1972 में कोयले का उत्पादन 748.10 लाख टन था, जो वर्ष 1973 में बढ़कर 772.50 लाख टन हो गया। इस प्रकार एक वर्ष में 24 लाख टन कोयले का अधिक उत्पादन हुआ। वर्ष 1973-74 के लिए 790 लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके प्राप्त हो जाने की पूरी सम्भावना है। वर्ष 1974-75 के लिए पहले 850-900 लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जो अब तेल संकट को ध्यान में रखते हुए बढ़ाकर 950 लाख टन कर दिया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयला खान प्राधिकरण और भारत कोकिंग कोल लि० ने अनेक उपाय किये हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : श्री हंसदा ने कोयला उत्पादन में 24 लाख टन वृद्धि होने का दावा किया है। रिकार्ड के अनुसार यह सही हो सकता है। पहले प्राइवेट खान मालिक अधिक उत्पादन करते थे, परन्तु अधिक उत्पादन को रिकार्ड में नहीं दिखाते थे और इस प्रकार फायदा कमाते थे। क्या वह इस तथ्य का खण्डन कर सकते हैं ?

श्री सुबोध हंसदा : मैं तो रिकार्ड के अनुसार जानकारी दे रहा हूँ। संभव है पहले के मालिक वास्तविक उत्पादन को रिकार्ड में नहीं दिखाते हों।

पाँचवीं योजना में 1350 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, और इस लक्ष्य की पूर्ति वर्ष 1978-79 तक की जायेगी।

तेल संकट को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने कोयला उत्पादन सहित पाँचवीं योजना की समीक्षा करने के लिए अनेक अध्ययन दल गठित किये हैं। ये अध्ययन दल तेल पर आधारित भट्टियों और बिजली घरों व उद्योगों आदि में ईंधन के रुप में कोयला घर कोयले से निर्मित गैस के उपयोग की सम्भावना पर विचार करेंगे। रिपोर्ट अभी मिली नहीं है और रिपोर्ट मिलने पर योजना आयोग इस बारे में अन्तिम निर्णय करेगा।

अनेक सदस्यों ने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया। भ्रष्टाचार के उदाहरण के रूप में सामान की खरीद, परमिटों का जारी किया जाना, कर्मचारियों की नियुक्ति आदि का उल्लेख किया गया। एक विशाल संगठन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार की बातें नहीं हो सकती। परन्तु भ्रष्टाचार के सभी मामलों के बारे में कोयला खान प्राधिकरण तत्काल कार्यवाही करता है। कोयला खान प्राधिकरण और उसके अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर तत्काल विचार किया जाता है और उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है। बिना नाम और छद्म नामों से की गई शिकायतों के बारे में कार्यवाही की जाती है।

भ्रष्टाचार के कथित मामलों के बारे में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए सतर्कता संगठन गठित किया गया है, जिसका सर्वोच्च स्तर पर निरीक्षण कोयला खान प्राधिकरण का अध्यक्ष करता है। पश्चिमी और मध्य डिवीजन में सभी आरोपों की जाँच करने के लिए स्वतन्त्र अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

श्री भोगेन्द्र झा (जयकार) **:** भ्रष्टाचार के जिन स्पष्ट मामलों का हमने उल्लेख किया है, उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार यह नीति अपनायेगी कि किसी भी भूतपूर्व खान मालिक अथवा भूतपूर्व ठेकेदार को एजेन्ट का सप्लायर नियुक्त नहीं किया जायगा ?

श्री सुबोध हंसदा : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसके अनुसार किसी भी भूतपूर्व खान मालिक की ठेकेदार के रूप में नियुक्ति की गई हो। अगर कोई निश्चित मामला हमारे ध्यान में लाया जाता है, तो हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

यद्यपि सतर्कता संगठन कोयला खान प्राधिकरण के अधीन है, मगर फिर भी यह एक स्वतन्त्र संगठन है। जाँच के परिणामस्वरुप अनेक अधिकारियों को दण्ड दिया गया है और अनेक का स्थानान्तरण किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में राज्यों की पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। फिर भी मेरा यह विचार है कि सतर्कता संगठन कोयला खान प्राधिकरण के अधीन न होकर एक अलग संगठन होना चाहिए।

गैर-कोककारी कोयले की कीमत में अभी तक बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। भारत कोकिंग कोल लि० के अधीन कोयला खानों के कोयले में 3 रु० 20 पैसे प्रति टन की दर से मामूली वृद्धि की गई है। इसका कारण है मजदूरों की संख्या 87,941 से बढ़कर 1,15,504 हो जाना। कर्मचारियों के मँहगाई भत्ते और बोनस में वृद्धि होने के कारण 2 रु० 75 पैसे प्रति टन की कीमत में मामूली वृद्धि की गई है। इस वृद्धि का जनता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह वृद्धि केवल इस्पात कारखानों के मामले में की गई है।

राष्ट्रीयकरण के बाद मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों के लिए 39 रु० की और दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के लिए 1 रु० 50 पैसे की वृद्धि की गई है। इससे उत्पादन-लागत में भी वृद्धि हुई है। इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए एक अन्तर्मन्त्रालयी समिति गठित की गई है।

यह भी कहा गया कि रेल मन्त्रालय और इस्पात तथा खान मन्त्रालय में तालमेल नहीं है। तालमेल बराबर रहा है। सदस्यों को पता ही है कि रेल कर्मचारियों ने एक निश्चित तारीख से हड़ताल करने की धमकी दी है। आगस्त में कुछ रेल कर्मचारियों ने हड़ताल की और कुछ ने "नियमानुसार काम करने" तथा "धीमे काम करने" का आन्दोलन किया। इस प्रकार खानों से उपभोक्ताओं तक कोयला नहीं पहुंच सका। कुछ अदूरदर्शी व्यापारियों ने स्थिति का लाभ उठाकर उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूल की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कोयला खान प्राधिकरण अथवा भारत कोकिंग कोल लि० ने अधिक कीमत वसूल नहीं की है।

कुछ सदस्यों ने पांचवीं योजना में 1350 लाख टन उत्पादन करने के लक्ष्य के बारे में आशंका व्यक्त की है, परन्तु हमें विश्वास है कि खान श्रमिकों के सहयोग से हम लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हो सकेंगे।

कुछ सदस्यों ने खान मजदूरों को सुविधायें उपलब्ध करने की बात कही। कोयला खान प्राधिकरण के अधीन लगभग साढ़े तीन लाख श्रमिक हैं। इन श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने और निकट भविष्य में उन्हें आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकरण से पहले कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि में 10 करोड़ रु० की राशि इकठ्ठी हो चुकी थी। इस समय इस राशि का उपयोग नहीं हो सका। सभी खानों के सरकारी क्षेत्र के अधीन आ जाने के कारण यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि श्रमिकों के पास क्वार्टर हों। राष्ट्रीयकरण से पहले केवल 71,947 क्वार्टर थे और उनमें से अधिकांश क्वार्टर जीर्णशीर्ण अवस्था में थे। अब उनकी मरम्मत कर दी गई है। 7,046 क्वार्टरों का निर्माण शुरू हो चुका है और आगामी वर्षों में 9,000 क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा।

श्रम मन्त्रालय के पास जो धनराशि इकठ्ठी पड़ी है, उसे कोयला खान प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा।

पहले श्रम मन्त्रालय आवास परियोजनाओं की क्रियान्विति करता था। अब कोयला खान प्राधिकरण क्वार्टरों का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रीयकरण से पहले अस्पतालों में सारे उपकरण नहीं थे और डाक्टरों तथा नर्सों की भी कमी थी। अब अस्पताल पूरी सुसज्जित हैं।

खान श्रमिकों के लिए जल सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए कुंओं का निर्माण किया गया और खान क्षेत्रों में वर्तमान जल सप्लाई योजनाओं में सुधार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कोयला खान प्राधिकरण को अस्तित्व में आये हुए अभी एक ही साल हुआ है और श्रमिकों को पेय जल सुविधायें उपलब्ध करने में अभी कुछ समय तो लगेगा ही।

बन्द पड़ी कोयला खानों के बारे में इस सदन में चर्चा की गई है और मन्त्रालय की सलाहकार समिति में भी चर्चा की गई है। कोककारी कोयला खानों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया, इस समय 42 कोयला खाने बन्द पड़ी थीं। गैर-कोककारी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय 152 कोयला खानें बन्द पड़ी थीं। झारिया कोयला क्षेत्र में चार कोयला खानें चालू कर दी गई हैं और दो अन्य खानों को चालू करने का प्रश्न विचाराधीन है। कोयला

[श्री सुबोध हंसदा]

खान प्राधिकरण ने 10 बन्द पड़ी खानें पहले ही चालू कर दी हैं, जिनमें 1200 से ज्यादा कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर लगा दिया गया है। अन्य खानों को खोलने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं आलोचना करने के बजाय कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा।

ईंधन के बारे में भारतीय तेल निगम का विद्यमान संगठन बनाया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे आशा है कि सारे मन्त्रालय के कार्यकरण में सुधार करेंगे।

इस समय प्रत्येक चीज का अभाव है। कोयला, इस्पात और बिजली का अभाव है। चालू वर्ष के दौरान इस्पात की माँग 58 लाख टन होने की सम्भावना है। अगर इस्पात का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इस्पात की माँग को कम किया जाना चाहिए। वर्ष 1978-79 तक 106 लाख टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा है परन्तु मुझे इसमें सन्देह है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हो भी सकेगी। भिलाई कारखाने की उत्पादन-क्षमता का 40 लाख टन उत्पादन तक विस्तार किया जाना है और यह कार्य दिसम्बर, 1976 तक होने की सम्भावना है। रूरकेला के विस्तार का कोई प्रश्न ही नहीं है। बोकारों का उत्पादन 17 लाख टन है। 100 लाख टन की अधिष्ठापित क्षमता किस प्रकार प्राप्त की जायेगी ? इस प्रकार पाँचवीं योजना के अन्त तक कमी की स्थिति जारी रहेगी।

भिलाई में 77 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग हो रहा है। रूरकेला में 58 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है। इसके बाद टाटा आता है। जब तक कम से कम 85 प्रतिशत क्षमता का उपयोग न हो रहा हो, हम यह नहीं कह सकते कि कारखाने ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

नियन्त्रक कम्पनी से इस्पात उत्पादन में वृद्धि होने की हम आशा नहीं कर सकते। कारखाने के महा प्रबन्धक या संयन्त्र प्रबन्धक को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे स्वतन्त्र रूप से काम कर सकें। नीति-निर्धारण के मामलों में मन्त्रालय को अधिकार होना चाहिए।

कोककारी और गैर-कोककारी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का मैं स्वागत करता हूँ। देश के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण मूलभूत पदार्थ है। यह उचित ही होगा कि इनका प्रबन्ध सरकार के हाथ में रहे। राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त बुरा नहीं है, परन्तु राष्ट्रीयकरण के दो साल बाद भी कोयला खान प्राधिकरण या भारत कोकिंग कोल लि० क्या कोई नई खान खोदी है ?

वर्ष 1978-79 के लिए कोयला-उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी भी नई खान में उत्पादन शुरू होने में कम से कम तीन साल लगते हैं। अभी बन्द पड़ी खानों को फिर से चालू किया जाना है। उत्पादन के बारे में हर महीने या त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। मन्त्रालय को इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो सके। जब तक कोककारी कोयलाखानों का विकास नहीं होगा इस्पात के उत्पादन में कमी बनी रहेगी।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्राइवेट खान मालिक गलत आँकड़े प्रस्तुत करते थे रेल मंत्रालय कहता है कि वैगन उपलब्ध किये जा रहे हैं और कोयला खान प्राधिकरण कहता है कि वैगन नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की बातों से सरकारी क्षेत्र के बारे में अच्छी धारणा नहीं बनती।

योजना आयोग अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करता है। दूसरी योजना के लिए 670 लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, तो तीसरी योजना के लिये 970 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया। योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर मंत्रालय को इस दृष्टि से विचार करना चाहिए, जिससे पूंजी विनियोजन बेकार न होने पाये। सरकार को राष्ट्रीय ईंधन नीति की घोषणा करनी चाहिए जिससे सही वितरण हो सके।

अल्युमीनियम एक महत्वपूर्ण अलोह धातु है। इसकी मांग 95,000 टन है। हम इसके बारे में आत्म निर्भर नहीं हैं। स्मैल्टर प्लान्ट के कब तक बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है। जे० के० को कोरापुट जिले में 30,000 टन की क्षमता के अल्युमीनियम संयंत्र को स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार उड़ीसा सरकार के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना में हाथ बंटा सकती है। वहां बाक्साइट उपलब्ध है, मूलभूत ढांचा भी है और सस्ती दर पर बिजली भी उपलब्ध है। अल्युमीनियम की मांग बढ़ती जा रही है और वह तांबे का स्थान ले रहा है, इसलिए बाक्साइट से अल्युमीनियम का उत्पादन किया जाना चाहिए, क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में बाक्साइट उपलब्ध है।

तांबा एक अन्य दुर्लभ धातु है। इसकी मांग 83,000 मीट्रिक टन है, जबकि उत्पादन केवल 12,000 मीट्रिक टन ही है। उत्पादन कम से कम 18,000 मीट्रिक टन होना चाहिए, तभी हम कह सकते है कि कुछ अच्छा काम हो रहा हैं।

जिंक की मांग लगभग 1,51,000 टन है और वर्ष 1978–79 तक इसकी 2,00,000 टन मांग होने की सम्भावना है। यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान जिन्क की उत्पादन-क्षमता शीघ्र ही बढ़ाकर 45,000 टन कर दी जायेगी। विजाग कारखाना कब स्थापित हो रहा है? क्या उदयकर संयंत्र की क्षमता में वृद्धि की जा रही है?

सीसे का उत्पादन केवल 3600 मीट्रिक टन है। सीसा जिंक का उपरिउत्पाद है। उड़ीसा के सरगपल्ली क्षेत्र में अच्छी किस्म के 56 लाख टन सीसे के भण्डार पाये गये हैं। अलौह धातुओं का विकास किया जाना चाहिए जिससे विदेशों से हमें इनका आयात न करना पड़े। योजना आयोग को भी इन धातुओं के विकास के लिए अधिक धन राशि की व्यवस्था करनी चाहिए।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : सलेम इस्पात संयन्त्र तमिलनाडु की जनता का एक स्वप्न रहा और वे सभी इस बात के लिए उत्सुक हैं कि इस संयंत्र का निर्माण शीघ्रातिशिघ्र पूरा हो। सलेम इस्पात संयंत्र के बारे में राज्य सरकार ने सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर दी है। भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था की सलेम इस्पात संयंत्र में वर्ष 1977–78 के अन्त तक काम शुरू हो जायेगा। अभी तक निर्माण-कार्य भी शुरू नहीं हुआ है और मशीनरी के लिए क्रयादेश भी नहीं दिये गये हैं।

वर्ष 1974–75 के लिए 15 करोड़ रुपये का आवंटन घटाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 7500 श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि यह कारखाना निर्धारित समय के अनुसार पूरा हो जाना चाहिए।

स्वर्गीय श्री मोहन कुमारमंगलम जिस काम को पूरा करना चाहते थे, उस काम को करने की जिम्मेदारी अब श्री केशव देव मालवीय के कन्धों पर आ पड़ी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सलेम इस्पात संयंत्र का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो जाना चाहिए।

स्टील आँथोरिटी आँफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने अभी तक सलेम इस्पात संयंत्र का दौरा नहीं किया जबकि इस आँथोरिटी को बने दो वर्ष हो चुके हैं। इसी प्रकार श्री मोहन कुमारमंगलम के दुःखद

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Hindi translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री ई० आर० कृष्णन]

निधन के पश्चात किसी भी इस्पात और खान मंत्री ने सलेम इस्पात संयंत्र का दौरा नहीं किया है। मैं श्री के० डी० मालवीय से अनुरोध करता हूं कि वह सलेम इस्पात संयंत्र का दौरा करें और इसे यथाशीघ्र चालू कराने के लिये कार्यवाही करें।

अनेक माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि देश की सभी आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिये इस्पात आधारभूत वस्तु है परन्तु ऐसा लगता है कि भारत सरकार का इस्पात उद्योग के बारे में भिन्न ही विचार है। एक ओर हम करोड़ों रुपये की इस्पात की वस्तुओं का आयात कर रहे हैं और दूसरी ओर वर्ष 1973–74 के दौरान इस्पात उद्योग में निर्धारित क्षमता का केवल 60 प्रतिशत उत्पादन हुआ। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने हेतु कदम उठायें उसी स्थिति में सरकार इस्पात की वस्तुओं का आयात कम कर के विदेशी मुद्रा के संसाधन बचा सकती है।

यदि मैं यह कहूं कि देश के उत्तरी भाग में इस्पात उद्योग विकसित हो रहा है तथा दक्षिणी भाग में यह पीछे रह रहा है तो मेरी बात का गलत अर्थ लगा लिया जायेगा परन्तु कर्नाटक राज्य के उद्योग मंत्रीने यह आरोप लगाया है कि केन्द्रीय सरकार दक्षिणी राज्यों में इस्पात उद्योग की उपेक्षा कर रही है। मैं इस्पात और खान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में, इससे पूर्व कि वहां के लोग केन्द्रीय सरकार के प्रति रोष प्रकट करें, कार्यवाही करें।

तमिलनाडु के नार्थ अर्काट जिले के तिरुवन्नामलाई स्थान पर लोह अयस्क के भूमिगत निक्षेपों का पता चला है। संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंसी के निदेशक, श्री ए० हटन ने बताया है कि उन खानों से 14 करोड़ टन लोह अयस्क मिल सकता है जिसका 65 प्रतिशत भाग इस्पात के उत्पादन के उपयोग में लाया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इन खानों के विदोहन और खानों के निकट इस्पात संयंत्र के लिये ठोस कार्यवाही करें।

वर्ष 1973–74 के दौरान 700 राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में उत्पादन कम हुआ है, मंत्री महोदय को कोयले के उत्पादन में कमी के कारणों की जांच करनी चाहिये तथा राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के उत्पादन में वृद्धि के लिये उचित कदम उठाने चाहियें।

Shri C. D. Gautam (Balaghat): There is a public sector company in Balaghat District in Madhya Pradesh which is called Manganese Ore India and which deals in manganese. This is the only company dealing in manganese but to-day it is running in loss. About 3 lakh tons of stock has accumulated with the company for want of adequate railway wagons. When the company does not earn profit, naturally the workers suffer. The workers were to go on strike on 26th March but the strike was averted when we intervened. Foodgrains should be supplied to workers at cheap rates.

I suggest that the unemployed engineers and geologists should be entrusted with the work of manganese mining.

Recently large deposits of copper have been found in Malanj area. These deposits are estimated to be about 60 million tonnes. The exploitation work at Malanj would cost much less than what it costs at Khetri and moreover, these deposits could meet the entire requirement of the country. Therefore, the work of exploitation of the said deposits should be undertaken expeditiously.

It is learnt that the Hindustan Copper Limited has entered into an agreement with a Soviet Agency for undertaking this work. If the work undertaken there and production starts, I hope the country would be benefitted by it. Attention should be paid to the Malanj area.

There are various obstacles in the implementation of schemes. Railways are obstructed in the movement of goods and there is the shortage of coal, gas and power. The strike by railway employees is particularly harmful for the country. It should be avoided.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर): हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में विचार किया जा रहा है ताकि इसके चारों युनिटों में से प्रत्येक को एक स्वायत्तशासी कम्पनी बना दिया जाये। मुझे इस पर आपत्ति है क्योंकि यह एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिये। इसे इस्पात और खान मंत्रालय के सचिव, जो स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं, के नियंत्रण में रखा गया है। इन विभागों के दो अलग प्रधान होने चाहियें अन्यथा स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

स्वर्गीय, मोहन कुमारमंगलम का तात्पर्य यह कदापि नहीं था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को एस० ए० आइ० एल० का चैयरमैन बना दिया जाय और उसके निर्णयों पर मंत्रालय आपत्ति न कर सके।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। स्वर्गीय कुमारमंगलम अब हमारे बीच नहीं हैं अतः उनकी बात का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

Mr. Chairman: If there is something in writing or a press statement, only then the hon. Member can refer to that.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जैसी एस० ए० आई० एल० की सहायक कम्पनियों के पुनर्गठन से काम नहीं चलेगा।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के यूनिटों में निरन्तर घाटा हो रहा है। इस प्रकार वे कितने दिन तक घाटे में चलेंगे, क्या मंत्री महोदय इस बारे में प्रकाश डालेंगे? मेरा सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात कारखाने में एक ही मजदूर संघ हो जिसका निर्वाचन मतदान द्वारा हो और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन प्रति वर्ष होना चाहिये। इस्पात और खान मंत्री को भविष्य में मजदूर संघ के नेता को सरकारी कारखाने का प्रधान नियुक्त करने में, दुर्गापुर के अनुभव को देखते हुए, सावधानी बरतनी चाहिये।

भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों के विस्तार में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र का कार्यकरण और उत्पादन संतोषजनक है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन कभी भी पूरी क्षमता से नहीं हुआ। हर बार कुछ न कुछ अड़चन आती रही है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में भी कभी संतोषजनक कार्य नहीं हुआ। ब्रिटिश और पश्चिम जर्मनी की कम्पनियों ने हमें दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के मामले में धोखा दिया है क्योंकि इन संयंत्रों में उत्पादन कभी भी अनुमानानुसार और पूरी क्षमता से नहीं हुआ। अतः जब तक ये संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं करते तब तक इसका विस्तार नहीं किया जाना चाहिये।

वर्ष 1974–75 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा 200 करोड़ रुपये की लागत से दस लाख टन इस्पात का आयात, जहां तक प्रति टन मूल्य का सम्बन्ध है, अनुचित है क्योंकि इसका कुप्रभाव हमारी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा।

सरकार को चाहिये कि वह टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर को अपने नियंत्रण में ले लें क्योंकि उसमें सरकार तथा आम जनता के अधिकांश शेयर हैं।

[श्री स्वर्ण सिंह सोखी]

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, घाटसिला का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है और उत्पादन पूरा नहीं हो रहा है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

भारत सरकार और सिक्किम के संयुक्त प्रयास से सिक्किम में सीसे, जस्ते और ताम्बे के भण्डार विकसित कराने के लिये इस्पात मंत्री बधाई के पात्र हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोइम्बतूर) : यह आश्चर्य की बात है कि 1973-74 में सलेम इस्पात संयंत्र में केवल भूमि को समतल बनाने के कार्य पर चार करोड़ रुपये खर्च किये ग े और अभी अभी मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसे महत्वपूर्ण संयंत्र को लगाने के लिये तीन करोड़ रुपय पर्याप्त हैं। यह संयंत्र राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां विशेष प्रकार के इस्पात का उत्पादन होना है जिससे विदेशी मुद्रा का बाहर जाना कम हो जायेगा।

ऐसे संयंत्र, जिसकी लागत 120 करोड़ रुपये आती हो उसके लिये यदि तीन करोड़ रुपये दिये जायें तो इस राशि से क्या होगा जबकि चार करोड़ रुपय केवल भूमि को समतल बनाने में खर्च हो गये हैं।

मैंने एस० ए० आई० एल० के कार्यकरण के बारे में कटौती प्रस्ताव दिया है। सरकार को किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पदोन्नति जैसे छोटे-छोटे मामलों में ही अपना ध्यान नहीं लगा देना चाहिये, अपितु लक्ष्यों के सम्बन्ध में कार्यकरण को देखना चाहिये।

इस्पात विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार एस० ए० आई० एल० को 24 जनवरी, 1973 को समाविष्ट किया गया था। इसने छह मासिक प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत नहीं किया है। हम जानना चाहते हैं कि इस संगठन के बारे में उनके पास क्या सूचना है, क्या होल्डिंग कम्पनी की यह योजना सफल हुई है या नहीं, चेयरमैन ने विभिन्न इस्पात संयंत्रों का कितनी बार दौरा किया है? जब हमने इस होल्डिंग कम्पनी की स्थापना की है तो हम जानना चाहते हैं कि क्या इससे लाभ हो रहा है अथवा नहीं।

एस० ए० आई० एल० का कहना है कि कठिनाइयों के बावजूद, इसने इस वर्ष 80 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हम यह जानना चाहते हैं कि अधिष्ठापित क्षमता में से कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है? जब तक हमें नियमित प्रतिवेदन नहीं मिलता तब तक हम कैसे जान सकते हैं कि यह संभव या नहीं?

एस० ए० आई० एल० ने दिल्ली में हिन्दुस्तान टाइम्स के भवन की दो मंजिलें एक लाख रुपये प्रति माह किराये पर ले रखी हैं। यह निजी भवन है। मंत्री महोदय इस मामले की अच्छी तरह जांच करें और व्यावहारिक प्रस्ताव पेश करें ताकि सरकारी उपक्रमों पर सही ढंग से धन खर्च किया जाय और गैर-सरकारी या एकाधिकारी क्षेत्र में न जाना पड़े।

इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में रुकावट के लिये हम रेलवे तथा इस्पात और खान मंत्रालयों पर आरोप लगाते हैं कि वे इस संकट के लिये उत्तरदायी हैं। श्रमिकों ने अच्छा कार्य किया है और उत्पादन बढ़ाया है। उन्होंने कोयले का उत्पादन भी बढ़ाया है परन्तु वे अन्तर्मंत्रालयीय सम्बन्धों के शिकार हैं।

कल रेलवे के कर्मचारी रेलवे बोर्ड स्टाफ के सदस्य से मिलें। हमें कहा गया है कि सभी मांगों पर बातचीत नहीं हो सकती। रेलवे के कर्मचारियों की मांगों का फैसला करने के लिये सरकार का नीति निर्णय आवश्यक है।

मैं आशा करती हूं कि मंत्री महादय इस बारे में गंभीर तापूर्वक विचार करेंगे।

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): There is not a single item in the country whose price has not increased. The price of non-ferrous metal has increased in the whole world. It has automatically increased in proportion to the increase in demand. Regarding aluminium, its production is not sufficient. So, we want that new aluminium plants should be set up in the Public Sector. The domestic demand of aluminium in 1973-74 was 2 lakh and 30 thousand tons and the anticipated production was 1 lakh and 50 thousand tons. Thus there was a shortfall of about 70-80 thousand tons. Similarly in 1978-79 the demand will be of the order of 3 lakh and 30 thousand tons whereas our production will be 3 lakhs and 70 thousand tons. The demand of copper is of 83 thousand tons and the production is 18 thousand tons. In 1978-79 the demand will be of 1 lakh and 4 thousand tons and the anticipated production capacity is of 57,650 tons. The demand of zinc is of 1 lakh and 31 thousand tons and the production is 28 thousand tons. The demand in 1978-79 will be of 2 lakhs tons and the anticipated production is 1 lakh and 65 thousand tons. The demand of lead is of 80 thousand tons and the production is 3 thousand tons. In 1978-79 the demand will be of 1,18,000 tons whereas the production will be 41,000 tons. The anticipated demand of nickel is 4 thousand tons. The anticipated production will be known later on as its production has not started as yet. Thus, we see that our domestic demand is increasing day by day and we will have to make more efforts to meet it. With this end in view, we are setting up some new plants.

Feasibility report of Malardkhund area has been prepared. The Mineral Exploration Corporation has explored the whole area and we hope that during the 6th plan, the production will be started there. By the end of fifth plan or at the beginning of sixth plan, the target of producing 45 thousand tons of zinc will be achieved. This will help greatly in meeting the demand. So far as Alwayee factory is concerned, we are going to increase its capacity from 20 thousand tons to 40 thousand tons. The capacity of Sargpalli factory is also being increased. The production capacity of lead and nickel will also be increased. As huge quantity of manganese ore has accumulated, we have given permission for its export.

The G.S.I. is doing great work in finding out mineral resources in the country. After exporting it, the G.S.I. is handing it over to Mineral Exploration Corporation, which in turn is evaluating the deposits.

So far as Alloy Steel Plant in Salem is concerned, we want that it should start production by the end of Fifth Five Year Plan. We will take a decision in respect of expansion of Tatas after going through the report submitted by the Steering Committee.

Shri Shrikrishan Modi (Sikar): In the progress of a country, minerals play an important part. Almost all progressive countries give concessions for the production of minerals. Fortunately this Department is having experienced and well-qualified personnel, but inspite of this the production is not stepping up.

Rajasthan abounds in minerals. So, special attention is required there. The Central Government should set up a cell there to make progress in this respect. The Steel Plants are facing difficulties due to shortage of refractories. We have all the necessary minerals. Why not the Government set up Small scale industries to produce refractories etc. This can solve the problem.

Steel plants are likely to face the shortage of limestone, dolomite and other materials. So, the Government should purchase them in advance to avoid difficulties. Japan is helping her minor mines in different ways to increase production, such as giving depreciation allowance, grant of subsidy to meet increased transport expenses. When you have everything, then why not you make efforts to increase production after handing over mineralwise work to Indian Mines Bureau. Like Finance Corporations for mining in other countries, corporations should be set up here also for mining. Minor minerals should be registered under small scale industry.

[**Shri Shrikrishan Modi**]

Free technical advice should be provided to mines. Steps should be taken to remove shortages of technical staff like mines foremen, surveyors, engineers and others.

Shri N. P. Yadav (Sitarmarhi): A sum of Rs. 834 crores was spent on steel industry during the Fourth Five Year Plan, but only 13.8 million tons of steel was produced during that plan period which is far below the target. It is the result of irrational and extravagant expenditure. If we do not take lesson from the results of Fourth Five Year Plan and go on spending extravagantly, we will not be able to increase the production and it will remain static.

Steps should be taken to streamline the working of industries first. For this, coordination should be brought about between Trade Unions and the management of industries. Necessary attention has not been paid towards the proper functioning of industries. The condition of washeries is very bad. We do not get washed coal in adequate quantities. The production of coking coal has been very unsatisfactory. The shortage of power added to the deteriorating conditions. It resulted in the shortage of steel. The transport problem, non-cooperation of Railways, strange behaviour of trade unions posed obstacles in the way of increasing production.

In January, 1973 steel authority came into existence. But it needs some impotant changes because it is not functioning properly. The production of steel was very low in the Fourth Five Year Plan due to shortage of Power, transport facilities, coal washeries etc.

[**श्री जगन्नाथराव जोशी** पीठासीन हुए
SHRI JAGANNATHRAO JOSHI *in the Chair*]

I want to draw the attention of the hon. Minister to the small blacksmiths of villages who have to purchase iron at higher rates to carry on their work. Arrangements should be made to provide them with iron at reasonable rates. Similarly, coal should also be provided at reasonable rates to brick kiln owners.

श्री एस० एल० पेजे (रत्नागिरी) : मैं रत्नागिरी अल्यूमिनियम संयन्त्र द्वारा की गई प्रगति की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पिछले 8-10 वर्षों से महाराष्ट्र सरकार ने 500 एकड़ भूमि ली हुई है। उसने कोयना पन-बिजली परियोजना से रियायती दर पर बिजली देने की पेशकश की है। राज्य सरकार ने परियोजना को पूरा करने हतु लगभग दो करोड़ रुपये व्यय किए हैं। आश्चर्य की बात है कि सरकार ने इस पर 1973 तक मुश्किल से 1.40 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। हम यह आशा कर रहे हैं कि 3-4 वर्षों में इसकी क्षमता 2,51,000 टन हो जाएगी परन्तु 8-9 वर्षों से इसकी प्रगति को देखते हुए इसमें संदेह होता है। मुझे दुख है कि चालू वर्ष के बजट में इसके लिए 8 करोड़ रुपये रखे गए हैं और उसमें भी शर्त लगी है। इससे कठिनाईयां ही पैदा होंगी। यह पता नहीं है कि सरकार ने मार्च, 1974 से पूर्व इसकी मंजूरी दे दी है या नहीं। यदि अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है तो हमें भय है कि निर्धारित तिथि के अंदर परियोजना पूरी न हो सकेगी। रत्नागिरि औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा जिला है। इसीलिए यहाँ परियोजना पर कार्य आरम्भ किया गया था। हम इस बात पर जोर देते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाए। मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दी जाए ताकि इसे कार्यक्रमानुसार चालू किया जा सके।

रत्नागिरी के अलावा भंडारा और चन्द्रपुर में खनिज बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं परन्तु उनका कई वर्षों से उपयोग नहीं किया जा रहा है। रत्नागिरी जिले में बड़ी मात्रा में इल्मेनाइट रेत विद्यमान है। इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ताकि वहाँ लोगों को रोजगार मिल सकें। इस जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण लोगों को बाहर जाना पड़ता है। यदि रत्नागिरी संयन्त्र का कार्य आरम्भ नहीं किया गया तो इसका प्रभाव वहां की बंदरगाह परियोजना पर भी पड़ेगा। इसलिए इस संयन्त्र का कार्य यथाशीघ्र आरम्भ किया जाये ताकि अन्य सहायक उद्योगों सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जा सके।

Shri Genda Singh (Padrauna): The Government should retain the coal mines in its own hands. They should not budge in face of difficulties. A news has appeared today in the 'Economic Times', at page 3, that deposits of about 8 lakh tons of coal have been found at Mirzapur. The hon. Minister should take proper action in this matter.

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): माननीय सदस्यों ने जो अमूल्य सुझाव दिए हैं, उन पर सरकार विचार करेगी। हालांकि सभी सुझावों पर चर्चा करना कठिन होगा, फिर भी सामान्य समस्याओं पर चर्चा की जानी चाहिए। सबसे पहले मैं कोयला खानों में होने वाली दुर्घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा, यह बड़े दुख की बात है कि कोयला खानों में अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं। सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि खानों में कम से कम दुर्घटनाएं हों। दुर्घटनाओं का कारण यह रहा है कि अधिकांश खानों में कार्य वैज्ञानिक ढंग से नहीं होता रहा है। पुराने मालिकों ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। अब हमारा प्रयास यह रहेगा कि ये दुर्घटनाएं न हों। इसके लिये सरकार खनन तकनीकों तथा खानों में सुधार करने हेतु अधिक धन व्यय करने से नहीं हिचकिचाएगी। औद्योगिक संबंधों में बिगाड़ आने पर सरकार की जो आलोचना की जाती है, वह अकारण और अनुचित है। इसके लिए सरकार, गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण करने वाली एजेंसियां, कार्मिक संघ के नेता तथा मजूरी कमाने वाले श्रमिक जिम्मेदार हैं। कुछ राजनैतिक उद्देश्य भी काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इन चारों तत्वों में सहयोग नहीं है। मेरे विचार में इसका संतोषजनक समाधान खोजा जाना चाहिए। कार्मिक संघों को किसी समझौते पर सहमत होना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार बने, उसे इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हम अपनी ओर से कार्मिक संघों को भरपूर सहयोग देने को तैयार हैं। लेकिन सरकार की नीति यह है कि केवल मान्यताप्राप्त कार्मिक संघों को बातचीत के लिए प्राथमिकता दी जाये। साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम उन संघों से बातचीत करने और उनकी न्यायोचित मांगों पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है और जिनका अखिल भारतीय आधार है। यदि कोई मजदूर संघ मान्यता-प्राप्त नहीं है पर किसी क्षेत्र में उसका प्रभाव है, तो हम हमेशा उससे सहयोग चाहेंगे।

क्षेत्रीय तनावों का उद्योगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सच तो यह है कि श्रमिक नेताओं द्वारा इन तनावों को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार अथवा श्रमिक नेताओं को क्षेत्रीय पक्षपात आदि की प्रवृति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यदि दोनों पक्ष इस दिशा में प्रयत्न करें तो स्थिति सुधर सकती है। यदि हड़तालें और क्षेत्रीय तनाव जारी रहे तो इसका परिणाम यह होगा कि काम ठप्प हो जाएगा और कोई समझौता नहीं हो पाएगा। साथ ही उत्पादन की गति भी धीमी हो जाएगी।

इस समय कोयला खानों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न हमारे सामने है। सरकार का इरादा कानून और व्यवस्था की चुनौती का सामना करने का है। यह स्थिति राजनीतिक उद्देश्य अथवा संघों की आपसी शत्रुता के कारण उत्पन्न हो जाती है। अच्छे मजदूरों में यह भय उत्पन्न किया जाता है कि यदि वह घर से बाहर काम के लिए जायेंगे तो उनका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा और बाद में उन्हीं लोगों को दोषी ठहराया जाता है। ऐसे मजदूरों का आदर करना और उनकी कार्यकुशलता बनाये रखना मेरा कर्तव्य है, जो उत्पादन में अपना योगदान देते हैं।

वास्तविकता तो यह है कि 90 प्रतिशत मजदूर हड़ताल करना नहीं चाहते, परन्तु श्रमिक संघ राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्हें हड़ताल करने पर विवश कर देते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे कई तत्त्व विद्यमान हैं जो झगड़ा करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

मैं स्वयं यह स्वीकार करता हूं कि स्थिति सुधारने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है। हम मिल कर इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। मैं श्रमिक नेताओं को यह आश्वासन देता हूं कि यदि वे सच्चे भाव से श्रमिकों का कल्याण चाहते हैं और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं हैं तो हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि संघों की आपसी शत्रुता होगी अथवा राजनीतिक उद्देश्य होंगे तो समस्या को हल करना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

[श्री के० डी० मालवीय]

श्री पी० एम० मेहता ने एक राष्ट्रीयकृत खान के एक कर्मचारी को पेंशन न दिए जाने का मामला उठाया था। ऐसे सभी मामलों में कोयला खान प्राधिकरण ने कर्मचारियों को प्रति माह 500 रुपये तक पेंशन देने का निर्णय किया है।

सेलम इस्पात संयंत्र का मामला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कई माननीय सदस्यों ने इस परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब किए जाने पर चिन्ता व्यक्त की है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार तथा इस्पात मंत्रालय की यह पूरी कोशिश रहेगी कि यह कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा हो जाए ?

इस समय देश में घोर आर्थिक संकट आया हुआ है। इस समय देश में खाद्यान्न का, तेल का तथा कई अन्य वस्तुओं का संकट है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके कारण संसाधन पूरी तरह जुटा पाना असम्भव हो गया है। फिर भी सेलम परियोजना सहित सभी इस्पात परियोजनाओं को अधिक से अधिक संसाधन जुटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि ज्योंहि हमें अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे, हम सेलम इस्पात संयंत्र की ओर और अधिक ध्यान देंगे।

रक्षित संयंत्रों के बारे में मेरा तथा मंत्रालय का यह विचार है कि कोयले तथा इस्पात के क्षेत्रों में रक्षित संयंत्र होने चाहिएं क्योंकि ये इस्पात उत्पादन में वृद्धि के कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप देते हैं। हमें विद्-युत प्रजनन एककों के रख-रखाव पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय बिजली उत्पादन की क्षमता में वृद्धि कर रहा है और हम योजना आयोग को आश्वस्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि वे रक्षित विद्युत् संयंत्रों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करे।

उत्तर प्रदेश के किसी नेता ने यह सुझाव दिया है कि कोयला खानों को फिर गैर सरकारी मालिकों को सौंप देना चाहिए। मेरे विचार में ऐसे व्यक्ति का राष्ट्रीयकरण में बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं आशा करता हूं कि हमारी नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग ऐसे नेता का कभी साथ नहीं देंगे।

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि की दर को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास प्रति दिन 36,000 टन कोयले का स्टाक होना चाहिए। यदि हम यह स्टाक नहीं रख सकते तो हमारा उत्पादन नहीं बढ़ सकता। मेरे विचार में इस वर्ष के अन्त तक, हमारा इस्पात का उत्पादन 54 लाख 66 हजार टन होगा, जो कि उत्पादन स्तर से कम है। हमें यह आशंका है कि इस्पात के उत्पादन के लिए पर्याप्त कोयला नहीं मिल पाएगा। यदि हम स्टाक में पड़े कोयले का अन्धाधुन्ध प्रयोग करते जाएं तो हमारी भट्टियों को खतरा पहुंच सकता है और हमें इस सम्बन्ध में जोखिम नहीं लेना चाहिए। जहां तक रेलवे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, बातचीत चल रही है। मैं किसी भी पार्टी को दोषी नहीं ठहराना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हम रेल मंत्रालय को इस बात के लिए दोषी ठहराए कि उन्होंने वैगन उपलब्ध नहीं कराए अथवा वह हमें दोष दे कि हमने कोयले का पर्याप्त उत्पादन नहीं किया।

वैगनों की व्यवस्था श्रमिक तनावों और क्षेत्रीय तनावों के कारण नहीं हो सकी। यदि माननीय सदस्य वस्तुतः मजूरी पाने वालों की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। परन्तु शर्त यह है कि राजनीति को अलग रखा जाए। यदि सदन से बाहर का कोई नेता यह समझता है कि वह कांग्रेस दल पर दबाव डाल सकता है तो यह उसकी मिथ्या धारणा है। अब भी हमारे पास परिवहन के लिए पर्याप्त कोयला है परन्तु रेलवे को इस्पात संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने नहीं दिया जा रहा...

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : रेल मंत्रालय का कहना है कि कोयले की कमी है और इस्पात और खान मंत्रालय का कहना है कि कोयला है। इनमें से कौन से मंत्रालय की बात सही है ? हम इसका उत्तर चाहते हैं क्योंकि यह हमें 14 रुपये के भाव से मिल रहा है।

श्री के० डी० मालवीय: स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस मामले में कुछ निर्णय...

श्री वसन्त साठे (अकोला) : श्रमिक सम्बन्धों की समस्या को हल करने के लिए मंत्री महोदय द्वारा श्रमिक नेताओं सहित सभी सम्बद्ध मंत्रालयों का सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में दिए गए सुझाव का क्या हुआ ? मंत्री महोदय इसमें पहल क्यों नहीं करते ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इसके लिए बिलकुल तैयार हूं । शर्त यह है कि मजदूरों के हितों को ध्यान में रखा जाए ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहती हूं । मैंने यह सुझाव दिया था कि इस्पात और खान मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय को संयुक्त प्रयत्नों से समस्याओं को हल करना चाहिए । मंत्री महोदय सम्बन्धित मंत्रालयों और मजदूरों का सम्मेलन क्यों नहीं बुलाते ताकि समस्याओं को हल किया जा सके ? मंत्री महोदय इसका उत्तर क्यों नहीं देते ?

श्री के० डी० मालवीय : रेल मंत्रालय तथा इस्पात और खान मंत्रालय की बैठक सप्ताह में दो बार होती है और वे समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं । मैं आल इण्डिया ट्रेड युनियन कांग्रेस के क्षेत्रीय स्तर के रवैये से असंतुष्ट नहीं हूं परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर इनका रवैया बदल जाता है । लेकिन जहाँ भी राजनीतिक उद्देश्य आ जाते हैं वहां कोई हल ढूंढना कठिन हो जाता है । कई बार गुटों में आपसी झगड़े हो जाते हैं और वे नेताओं की बात मानने के लिए तयार नहीं होते । श्रमिक संघों के राजनीतिक उद्देश्यों के कारण ही स्थिति बिगड़ी है और उत्पादन को क्षति पहुंची है । इसीलिए मेरी अपील है कि सदन के सभी सदस्य श्रमिक संघों पर अपना प्रभाव डालें ताकि एक अच्छा वातावरण बनाया जा सके और उन कर्मचारियों को काम पर जाने का अवसर प्राप्त हो सके जो काम करना चाहते हैं परन्तु समाज-विरोधी तत्त्व उन्हें ऐसा नहीं करने देते हैं ।

Shri Dhan Shah Pradhan: Who is responsible for the death of persons who died under the debris of Dhanpuri Colliery in Madhya Pradesh ?

श्री के० डी० मालवीय : उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा और हम उनके लड़कों को नौकरी देंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि आगे से ऐसी कोई दुर्घटना न हों ।

स्टील अथारिटी बनाने के उद्देश्यों और इसके कार्यकरण से सदन अवगत है । यह अथारिटी लगभग एक वर्ष पूर्व बनाई गई थी । इस संगठन में प्रतिभावान कर्मचारियों का अभाव नहीं है । फिर भी इसमें सुधार की आवश्यकता है और हम इसके कार्यकरण की सम्पूर्ण प्रणालियों के विकेन्द्रीकरण पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । हमें अपने तकनीशियनों की कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना होगा । यह पूछा गया कि स्टील अथारिटी का प्रतिवेदन सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा गया । इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इसे शीघ्र ही सभा पटल पर रखा जाएगा ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब किए जाने के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र का काम पूरा नहीं हो सका । हम इस संयंत्र का निर्माण समेकित ढंग से करेंगे ताकि 40 लाख टन उत्पादन किया जा सके । प्रत्येक चरण के लिए समन्वित निर्माण अनुसूची तैयार की जा चुकी है ।

बोकारो में हुई गड़बड़ के बारे में मैंने तथ्य एकत्रित किए हैं । लगभग 1500 कर्मचारी एक संघ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । उन्होंने मेरे से मुलाकात भी की थी और मेरे विचार में उनकी कुछ मांगें न्यायोचित हैं और सरकार मामले को निपटाने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न कर रही है । उनको अधिक दवाब नहीं डालना चाहिए (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरे पास निश्चित सूचना है कि उन पर लाठी-चाज किया गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया ।

श्री भागवत झा आजाद : श्री खन्ना ने इंजीनियरों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें जेल भेजा गया। उनके लिए यह शर्म की बात है। श्री खन्ना को हटा देना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री खन्ना ने शर्मनाक काम किया है और श्री वदूद खान उसका समर्थन कर रहे हैं। दोनों व्यक्तियों को हटा देना चाहिए।

Shri Nagendra Prasad Yadav (Sitamarhi) : I would like the hon. Minister to tell us about Mr. Khanna. Why some 'Bihari' is not posted there?

श्री के० डी० मालवीय : अनुशासन बनाए रखने के लिए उच्चाधिकारी की नियुक्ति की गई है। चाहे वह गलत निर्णय ही क्यों न ले, यदि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के कार्य में व्यवधान डाला जाता है तो इस्पात मिल अथवा संयंत्र का अनुशासन बिगड़ सकता है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारी मुझ से मिले थे। उनकी कुछ मांगें न्यायोचित हैं और उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे वातावरण को दूषित न करे **(व्यवधान)**

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : सरकार की नीति हर वर्ष इनकी सेवाओं की अवधि बढ़ाने की है ताकि उनके पद स्थायी न हो सकें।

श्री के० डी० मालवीय : उनके भविष्य को कोई खतरा नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय लाठी चार्ज की बात को न तो मानते हैं और न ही उसका खण्डन करते हैं।

श्री के० डी० मालवीय : तथ्य-तथ्य ही रहेंगे। लाठी चार्ज के बारे में अलग अलग बयान प्राप्त हुए हैं। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मेरा कहना केवल इतना है कि उनकी कुछ मांगें न्यायोचित हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : बिहार जिले में श्रमिक संघ के एक अधिकारी पर राइफल से हमला किया गया और 31 श्रमिक नेता घायल हुए। मंत्री महोदय ने इसका उल्लेख नहीं किया।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने अधिकांश प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं। शेष प्रश्नों का उत्तर बाद में दिया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए --

सभापति महोदय : शांति, शांति। कृपया बैठ जाइये। श्री एस० एन० सिंह ने एक कटौती प्रस्ताव पेश किया था। वह इस समय उपस्थित नहीं हैं। मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Cut Motion No. 3 was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा इस्पात और खान मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following demands in respect of Ministry of Steel and Mines were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये) राजस्व	पूंजी
78	इस्पात विभाग . . .	20,85,13,000	1,33,90,69,000
79	खान विभाग . . .	27,63,000	
80	खान और खनिज . . .	27,73,08,000	2,18,98,68,000

तत्पश्चात लोकसभा बुधवार, 17 अप्रैल, 1974/27 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 17, 1974/*Chaitra* 27, 1896 (*Saka*).

भा०स०मु०ना०—वि० 5—14 लोक सभा/74—20-8-74—490.